दैनिक जागरण
आपके विचार ही आपको अच्छा-बुरा बनाते हैं

उच्चस्तरीय जांच समिति

यह अपेक्षित ही नहीं आवश्यक था कि अहमदाबाद के भयावह विमान हादसे की सघन जांच के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की जाती। गृह सचिव की अध्यक्षता में ऐसी जो समिति गठित की गई है, उसे तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और यह सुझाव भी कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना रोकने के क्या उपाय किए जाएं। भारत के साथ विश्व समुदाय को स्तब्ध करने वाली इस दुर्घटना की जांच अन्य एजेंसियां भी करेंगी। इस जांच में विमान निर्माता कंपनी के साथ अमेरिकी और यूरोपीय जांच एजेंसियों की भी भागीदारी होगी। यह भी समय की मांग थी, क्योंकि यह दुर्घटना बहुत ही चकित करने वाली है। बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान जिस तरह हादसे का शिकार हुआ, उसे देखते हुए इस कंपनी को भी दुर्घटना के कारणों की तह तक जाना ही होगा। इसलिए और भी, क्योंकि एक तो भारत में इस कंपनी के और भी विमान हैं और दूसरे, उस पर अपने विमानों के निर्माण में सुरक्षा उपायों की अनदेखी के गंभीर आरोप लग चुके हैं।

सरकारी से निजी कंपनी टाटा के हाथों में गई एअर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की गहन जांच के साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा और उनमें से एक यह भी है कि हमारे सभी प्रमुख हवाईअड्डे जिन जगहों पर स्थित हैं, वे चारों तरफ आबादी से घिरे हैं। इसके चलते किसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में आसपास की आबादी को भी क्षति पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। अहमदाबाद में ऐसा ही हुआ। यहां विमान के एक मेडिकल कालेज के हास्टल पर गिरने से वहां के मेडिकल छात्रों समेत कई लोग मारे गए। चारों ओर आबादी से घिरे हवाईअड्डों के आसपास विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उस तक सहायता पहुंचाने में भी बाधा पहुंचती है। विमान यात्रा को केवल इसलिए सुरक्षित बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद सरीखे हादसे विमानों से यात्रा के प्रति लोगों के मन में संदेह बढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि आज विमान यात्रा करना एक आवश्यकता बन गई है। देश में पिछले कुछ वर्षों में विमान यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ ही हवाईअड्डों की भी संख्या बढ़ रही है। स्पष्ट है कि डीजीसीए एवं एयरपोर्ट अथारिटी जैसी एजेंसियों को और सजग होना होगा। विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर रह-रहकर सवाल उठते रहते हैं। कम से कम सुरक्षा को तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बात केवल सुरक्षित विमान संचालन की ही नहीं, रेल और बस समेत आवागमन के अन्य साधनों को भी सुगम और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। यह एक तथ्य है कि अपने देश में रेल और सड़क हादसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है।

जान बचाएगी सख्ती

बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में शुरू हुई सख्ती असरकारक होगी। कई लोगों ने यह मान लिया था कि आनलाइन चालान बस कागजों तक सिमटा है। रोज हो रहे हादसे हंसती-खेलती जिंदगियां लील रहे हैं। यातायात नियमों की अनदेखी हादसों की बड़ी वजह है। यह अच्छा है कि यातायात निदेशालय ऐसे वाहनों को सूचीबद्ध कर रहा है, जिनका पांच या उससे अधिक बार चालान हुआ और शमन शुल्क भी लंबित है। हद तो यह है कि एक वाहन के 100 से अधिक चालान के मामले भी पाए गए हैं। ऐसे ही लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और दूसरों को भी इनकी वजह से जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण निरस्त होने से संभव है कि अनदेखी रुके। लगभग पौने तीन लाख वाहनों को पंजीकरण रद करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस रद होने योग्य पात्रता भी तीस हजार से अधिक है। यह भी समझना होगा कि अभी कार्रवाई ज्यादातर पुलिस कमिश्नरेट वाले बड़े जिलों में है। पूरे प्रदेश में सख्ती शुरू होगी तो यह आंकड़ा और बड़ा होगा। पुलिस व परिवहन विभाग को चाहिए कि बिना देरी किए आदतन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई और तेज करें। अभी जितने लोगों पर सख्ती हुई है, उनकी संख्या दोषियों की तुलना में अत्यल्प है।

> ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन चालकों का पंजीकरण निरस्त होने से संभव है कि कुछ सुधार हो

भारत-कनाडा रिश्तों में जमी बर्फ पिघली

कुशल मेहरा

कनाडा में सरकार की दिशा प्रधानमंत्री के रवैये से तय होती है और उसका अपने दल पर दबदबा होता है। लिबरल पार्टी में वही होगा, जैसा पीएम मार्क कार्नी चाहेंगे

इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, भारतीय प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच रहे हैं। उन्हें कनाडा आने का कथित निमंत्रण न मिलने पर कांग्रेस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय प्रधानमंत्री को जी-7 सम्मेलन में आमंत्रित न करना मोदी सरकार की कमजोर कूटनीति का प्रमाण है। इसके बाद जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मोदी को निमंत्रण दिया, तो कहा गया कि यह देर से दिया गया, पर आखिर देरी को कैसे परिभाषित किया जाएगा? भारतीय प्रधानमंत्री को जी-7 में भाग लेने के लिए निमंत्रण देने को लेकर कनाडा में भी सवाल उठे। इनका जवाब देते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था एवं सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के साथ कई आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है। मार्क कार्नी ने खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में तथाकथित भारतीय एजेंटों का हाथ होने के आरोपों की जांच से जुड़े प्रश्न पर कहा था कि कानूनी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यह समझा जाना चाहिए कि मार्क कार्नी का भारत समेत अनेक मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अलग रवैया है। इसका प्रमाण यह है कि भारत-कनाडा आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए एक-दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करेंगे।

मार्क कार्नी तब कनाडा के अंतरिम पीएम बने थे, जब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने रवैये के कारण जस्टिन ट्रूडो की फजीहत हो गई थी। उनकी ही पार्टी की ओर से उन पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव था। यदि वह प्रधानमंत्री बने रहते, तो लिबरल पार्टी बुरी तरह हारती। कनाडा-भारत संबंध बिगड़ने के लिए जस्टिन ही जिम्मेदार थे। वह अपने कार्यकाल में खालिस्तान समर्थकों को खुश करने में लगे रहे और तब तो ऐसा करना उनकी मजबूरी हो गई थी, जब अपनी अल्पमत सरकार चलाने के लिए वह खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के समर्थन के मोहताज हो गए थे। उन्होंने जगमीत और अन्य खालिस्तान समर्थकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकी निज्जर मामले में उन्होंने यह हास्यास्पद बयान दिया था कि उसकी हत्या में भारतीय एजेंटों के हाथ होने के ''पुख्ता आरोप'' मिले हैं। यह पहली बार था, जब किसी शासनाध्यक्ष ने प्रमाण नहीं, बल्कि आरोपों के आधार पर किसी देश को कठघरे में खड़ा किया हो और वह भी ऐसे शख्स की हत्या के मामले में, जो अवैध तरीके से कनाडा पहुंचा था और जिसे भारत में आतंकी करार दिया गया था। इसके बाद कनाडा-भारत संबंध बिगड़ने ही थे और वे बिगड़े भी।

अवधेश राजपूत

जस्टिन ट्रूडो की जगह अंतरिम प्रधानमंत्री बने कार्नी परंपरागत राजनेता नहीं हैं। वह व्यवसायी रहे हैं और भारत से संबंधों समेत अन्य मामलों को अपनी तरह से देखते हैं। इसके संकेत तभी मिल गए थे, जब चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में खालिस्तानी झंडे नहीं दिखे। जस्टिन न सिर्फ खालिस्तान समर्थकों से घिरे रहते थे, बल्कि उनकी सभाओं में खालिस्तानी झंडे भी लहराते थे। चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री बने कार्नी के मंत्रियों में से एक जूनियर मंत्री को छोड़ अन्य के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह खालिस्तान समर्थकों का साथी है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, पर उन्हें खालिस्तान समर्थक नहीं कह सकते। मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण मिलने के पहले विदेश मंत्री जयशंकर और अनीता आनंद में बात हुई थी। कार्नी की जीत के बाद मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। इसी कारण इस कहानी में दम नहीं दिखता कि जी-7 के बाकी देशों ने जब दबाव डाला, तब कार्नी ने मोदी को निमंत्रण दिया।

अभी यह नहीं कह सकते कि मोदी की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के संबंध बहुत मधुर होने जा रहे हैं, पर इतना अवश्य है कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। यह भविष्य बताएगा कि वह कितनी पिघलती है? यदि कनाडा को भारत की जरूरत है तो उसे भी भारत की। यह कह सकते हैं कि कनाडा को भारत की ज्यादा जरूरत है, पर भारत को ऊर्जा सुरक्षा का जो स्रोत और अपने तकनीकी विकास के लिए जो दुर्लभ खनिज चाहिए, वे उसे कनाडा से आसानी से मिल सकते हैं। यदि दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आते हैं तो मौजूदा व्यापार दोगुना यानी 20 अरब डालर तक पहुंच सकता है।

कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की आबादी कुल आबादी का करीब आठ प्रतिशत है। यह सही है कि यहां खालिस्तान समर्थक सक्रिय हैं, पर उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। उनकी राजनीतिक सक्रियता का कारण उनकी ओर से कनाडा के राजनीतिक सिस्टम का दुरुपयोग किया जाना है। इसी कारण वे राजनीतिक दलों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। इस बार भारतीय मूल के कहीं अधिक सांसद चुनाव जीते हैं, पर भारत के लिहाज से अच्छी बात यह रही कि एनडीपी का खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह खुद चुनाव हार गया। वह एनडीपी का प्रमुख था। इसी कारण जगमीत को पार्टी प्रमुख से हटना पड़ा। मार्क कार्नी बहुमत से थोड़ा ही पीछे हैं, इसलिए उन्हें एनडीपी के सात सांसदों की जरूरत नहीं। महत्वपूर्ण है कि कनाडा में सत्ताधारी दल की दिशा प्रधानमंत्री के रुख-रवैये से तय होती है और उसका अपने दल पर दबदबा होता है। फिर से सत्ता में आई लिबरल पार्टी में वही होगा, जैसा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहेंगे।

मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण मिलने के बाद से खालिस्तान समर्थक छोटे-बड़े और गुमनाम से संगठन पगलाए हुए हैं। वे धरना-प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। मोदी के कनाडा आगमन पर खालिस्तान समर्थकों को काबू में रखने के लिए कनाडा सरकार को सतर्क रहना होगा, पर भारत के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपनी कनाडा नीति को परिभाषित करे। मेरे लिए भारत सरकार की कनाडा नीति समझना कठिन है। मैं चाहूंगा कि कनाडा के मामलों में विदेश मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा हो।

(लेखक कनाडा मामलों के जानकार एवं पाडकास्टर हैं और वहां प्रवास भी करते हैं)

response@jagran.com

राइटर की फाइटर बनने की चाहत

हास्य-व्यंग्य

आपरेशन सिंदूर के दौरान मैं अपने जांबाज योद्धाओं के पराक्रम और शौर्य से गर्व से भरा हुआ था। मैं जांबाज फाइटर योद्धा तो नहीं, लेकिन लोग मुझे रंगबाज राइटर अवश्य कहते हैं। मैं राइटर से फाइटर बनने के लिए अपने योद्धाओं पर कुछ लिखना चाह रहा था। दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिए जाने की खबर आते ही मेरा मन विचलित हो उठा। दिल से आवाज आई, क्या अब दुश्मन अपने यहां आतंकियों को पालने और आतंकी गतिविधियों के नए-नए तरीके अपनाने से बाज आएगा? मेरा दिमाग बार-बार यही कह रहा था कि इस युद्ध से हम दुश्मन का सोच और उसका भूगोल बदलने में जरूर कामयाब होंगे।

मेरे दिमाग पर ड्रोन और मिसाइल की तरह अनेक प्रश्न तेजी से विचरण करने लगे। तभी एक संपादक मित्र के फोन ने सब संभाल लिया। वह कह रहे थे कि आपकी रचना...। मैंने उनकी बात पूरी होने के पहले अपना प्रश्न दाग दिया, 'कैसे बनते हैं जांबाज फाइटर योद्धा?' उत्तर मिला, 'सर्वप्रथम कैडेट बनने के लिए और देश की सुरक्षा-सेवा हेतु समर्पित होने का जज्बा होना चाहिए। उसके बाद वायुसेना में 'फ्लाइंग अफसर' के लिए सेलेक्शन की तैयारी करनी पड़ती है। सेलेक्ट हो गए तो कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। तब जाकर कोई बनता है जांबाज फाइटर वायुयोद्धा।' उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक पैदा हुई और याद आ गया कि कैसे लोग दुश्मन के क्षेत्र में दागी जाने वाली मिसाइलों की आवाज से तो खुश होते थे, लेकिन कुछ भारतीय इलाकों में 'ब्लैकआउट' की खबर आते ही चिंतित हो जाते थे और यह सोचने लगते थे कि उनके यहां भी ब्लैकआउट की नौबत आई तो कहीं अंधेरे में अंगुली में सुई न चुभ जाए। मैंने देखा था कि जो लोग दुश्मन को मटियामेट करने और कुचल देने को लेकर उतावले थे और पाकिस्तान के कब्जे वाली अपनी जमीन वापस लेने की रणनीति बता रहे थे, वही सिर पर अचानक सूखा पत्ता गिरने से डर जाते हैं और कई दिन तक उस पेड़ के नीचे से नहीं गुजरते। कुछ लोग यह भी चाह रहे थे कि युद्ध में सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को खरोंच भी न आए।

आलोक सक्सेना

कुछ लोग यह भी चाह रहे थे कि युद्ध में सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को खरोंच भी न आए

मैं अपने आप को किसी जांबाज फाइटर से कम नहीं समझ रहा था। तभी मेरी निगाह टीवी पर चल रहे समाचार पर गई। वहां गर्व से 'युद्ध-गाथा' सुनाते हुए बताया जा रहा था, 'दुश्मन ने अपना खाली विमान हमारे फाइटर प्लेन के आगे करते हुए हमारे फाइटर प्लेन पर पीछे से आक्रमण करके उसे मार गिराना चाहा, मगर हमारे योद्धाओं ने दुश्मन के फाइटर प्लेन को ही मार गिराया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित थे और सकुशल भारत की धरती पर लौट आए थे।' मैंने संपादक जी को फोन मिलाया और अपनी एक जिज्ञासा उनके सामने रखी। उन्होंने इसे यह कहकर शांत किया कि दुश्मन हमारे ड्रोन को हमारा प्लेन समझकर उसे गिराकर बहुत खुश हुआ, मोगैंबो की तरह, लेकिन वह नासमझ मूर्ख का मूर्ख ही रहा। आपरेशन सिंदूर में हमारे योद्धाओं को युद्ध में जाने और अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला, तो लोगों का जज्बा भी आसमान पर है। अपने देश के लिए कुछ नया कर दिखाने के जज्बे से उनका रोम-रोम भरा है। इसलिए हे मेरे मित्र, तू चिंता मत कर।

मेरा मन अब भी चिंतित था। मैंने प्रश्न किया, लेकिन कुछ लोग अचानक युद्ध थमने से खुश नहीं हैं। मेरे संपादक मित्र ने समझाया, 'इसे ऐसे समझो कि यदि किसी लेखक ने यह समझकर कहीं कोई रचना भेजी कि उसे तो तत्काल छाप दिया जाएगा और पाठक उसे कालजयी करार देंगे, लेकिन उसे प्रकाशन योग्य न समझा जाए तो जैसा उस लेखक को लगेगा, वैसा ही कुछ लोगों को भी लग रहा है। आप चिंतित न हों।'

response@jagran.com

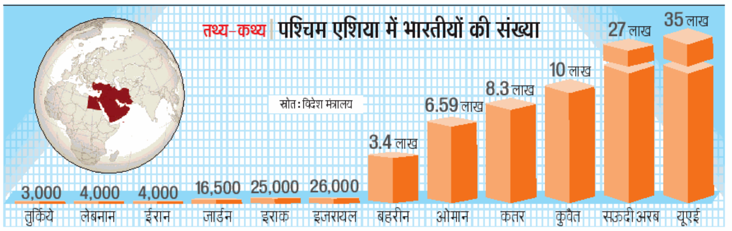

ऊर्जा

पिता का त्याग

भारतीय संस्कृति में समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का वर्णन किया गया है। पिता को धार्मिक ग्रंथों में देवतुल्य माना गया है। इस धरती पर पिता से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ मार्गदर्शक नहीं है। पिता का संघर्ष, अनुभव और ज्ञान संतान को कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और स्नेह को पिता शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से प्रकट करता है। वह जीवनभर संघर्ष कर अपनी संतान के सुनहरे भविष्य की नींव रखता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पुत्र कितना भी निर्दयी स्वभाव का क्यों नहीं हो जाए, पिता उसके प्रति ममता और प्रेम को नहीं त्यागता, क्योंकि उसके लिए पिता ने कितनी ही विपत्तियां झेली होती हैं। पिता के हृदय में उसके लिए सदैव ममता और प्रेम ही अंकुरित होता है। इसीलिए पिता का विराट व्यक्तित्व स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि पिता में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए संतान को हमेशा पिता का सम्मान और आदर करना चाहिए।

जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उसके कंधे पर जनेऊ धारण कराया जाता है, जिसमें से एक धागा पितृ ऋण का प्रतीक है। यह धागा संतान को अपने माता-पिता के प्रति दायित्वों का बोध कराता है। पिता अपने संतान का मार्गदर्शन करते हुए उसके जीवन को सुदृढ़ बनाता है। पूरी दुनिया में केवल पिता ही है, जो अपनी संतान को अपने से भी श्रेष्ठ और सफल देखकर प्रसन्न होता है। पितृदिवस, पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पिता का योगदान और त्याग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने पिता के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष और बलिदान हमारे लिए अनमोल हैं।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

हमारे वायुमंडल की बढ़ती हुई 'प्यास'

मुकुल व्यास

वायुमंडल मिट्टी, नदियों, झीलों और यहां तक कि पौधों से भी ज्यादा नमी खींचता है। इस बढ़ती प्यास के कारण सूखे की समस्या गंभीर होती जा रही है

दुनिया भर में सूखे की समस्या गंभीर और व्यापक होती जा रही है, लेकिन इसके लिए सिर्फ बारिश के पैटर्न में बदलाव जिम्मेदार नहीं है। विज्ञानियों ने पता लगाया है कि हमारे वायुमंडल की बढ़ती हुई 'प्यास' भी सूखे जैसे हालात पैदा करती है। पिछले चार दशकों (1981-2022) में सूखे की गंभीरता में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि वायुमंडलीय प्यास की वजह से हुई है। विज्ञानी इस वायुमंडलीय प्यास को एटमास्फेरिक इवेपोरेटिव डिमांड (एइडी) भी कहते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में कहा गया है कि यदि बारिश आपकी 'आय' है तो एइडी आपका 'खर्च' है। भले ही आपकी आय (वर्षा) वही रहे, लेकिन अगर आपका खर्च (एइडी) बढ़ता है, तो आपका बैलेंस घाटे में चला जाता है। सूखे के साथ ठीक यही हो रहा है। वायुमंडल जमीन से ज्यादा पानी की मांग कर रहा है। जैसे-जैसे ग्रह गर्म होता है, यह मांग बढ़ती जाती है। वायुमंडल मिट्टी, नदियों, झीलों और यहां तक कि पौधों से भी ज्यादा नमी खींचता है। इस बढ़ती प्यास के कारण सूखे की समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसा उन इलाकों में भी हो रहा है जहां बारिश में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। एइडी की प्रक्रिया बताती है कि वायुमंडल सतह से कितना पानी चाहता है।

हवा जितनी ज्यादा गर्म, धूपदार, हवादार और शुष्क होगी, उसे उतने ही अधिक पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए उन जगहों पर भी जहां बारिश में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है, हम सूखे की स्थिति को बदतर होते हुए देख रहे हैं। प्यासा वायुमंडल चीजों को तेजी से और अधिक तीव्रता से सुखा रहा है। नए विश्लेषण से पता चलता है कि एइडी न केवल मौजूदा सूखे को बदतर बनाती है, बल्कि यह सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार भी करती है। 2018 से 2022 तक सूखे का सामना करने वाले वैश्विक भूमि क्षेत्र में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उस विस्तार का 58 प्रतिशत एइडी में वृद्धि के कारण था।

नए अध्ययन के अनुसार 2022 चार दशकों में सबसे अधिक सूखाग्रस्त वर्ष रहा। दुनिया की 30 प्रतिशत से अधिक भूमि ने मध्यम से लेकर अत्यधिक सूखे की स्थिति का अनुभव किया। यूरोप और पूर्वी अफ्रीका में 2022 में सूखा ज्यादा गंभीर था। यह मुख्य रूप से एइडी में तेज वृद्धि के कारण था, जिसने उन जगहों पर भी सूखा उत्पन्न कर दिया जहां वर्षा में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई थी। इसने जल आपूर्ति, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों पर अभूतपूर्व दबाव डाला, जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया। इसलिए आने वाले समय में हमें सूखे से निपटने के लिए ठोस उपाय करने होंगे।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

सहानुभूति वोट

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सभी विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भाजपा के भीतर भी इसके प्रभाव को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन भाजपा विपक्ष के इस हमले को भी सकारात्मक नजरिए से देख रही है। इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इससे नीतीश कुमार के समर्थकों का सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का अति पिछड़ों और महिलाओं के बीच एक बड़ा समर्थक वर्ग है। जाहिर है वे भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे और उनके आखिरी चुनाव को देखते हुए सहानुभूति में उन्हें वोट देने के लिए एकजुट हो सकते हैं। इसके पहले कई बड़े नेताओं के मामले में ऐसा देखा जा चुका है।

महाराष्ट्र हार की चुभन

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को भले ही छह महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार को भूल नहीं पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने छह महीने बाद एक लेख के जरिए महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियों के उन्हीं आरोपों को दोहराया है, जिनके जवाब चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है। हालांकि लेख में लगाए उनके आरोपों पर आयोग ने फिर से जवाब दिया। बाद में आयोग पर लिखित में जवाब न देने जैसे आरोप लगाए गए। इस पर आयोग ने लिखित में भी जवाब दिया। लोगों का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को धार देने में जितनी ताकत लगा रही है, उतनी यदि मतदाता सूची की गड़बड़ियों को खोजने के लिए लगाती तो शायद उसे चुनाव आयोग को घेरने के लिए कुछ पुख्ता सुबूत मिल जाते। यह देखना दिलचस्प होगा कि लिखित जवाब के बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र की हार पर कौन सा नया शिगूफा लेकर आती है या फिर उसे भूल कर नई जमीन तैयार करने में लगती है।

उड्डयन मंत्रालय

एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाई। सरकार की तरफ से यह पहला बयान आने वाला था। मंत्रालय के एक कमरे में 60 से ज्यादा कैमरे और उससे ज्यादा कैमरामैन और उससे भी ज्यादा पत्रकारों की ऐसी भीड़ जमा हुई जैसी मंत्रालय के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। सारे कर्मचारी जी-जान से लगे हुए थे। मंत्री जी के आगमन से ठीक पहले किसी की नजर उस कुर्सी पर गई, जहां वह बैठने वाले थे। यह क्या? यह कुर्सी तो बाकी अन्य कुर्सियों की ही तरह है। फिर जल्दी से दूसरी ऊंची कुर्सी मंगाई गई। तभी किसी ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का तो कोई बोर्ड ही बैकग्राउंड में नहीं है। जल्दी से बोर्ड मंगाया गया, कीलें मंगाई गईं, हथौड़ा लाया गया और उसे टांगा गया।

कोई भी सही

भाजपा के अध्यक्ष फलां हो सकते हैं... पार्टी हाईकमान इन पर दांव लगा सकती है... ये अध्यक्ष संगठन के लिए सबसे बेहतर होंगे...! महीनों से उत्साह के साथ चल रही ये अटकलें और आकांक्षाएं भी अब थकी-मांदी दिखाई दे रही हैं। जिस भाजपा मुख्यालय में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा कभी समीकरण तो कभी क्षमताओं का एंगल ढूंढ़कर होती थी, अब वहां का माहौल बदल चुका है। जैसे ही इस मुद्दे पर बात की जाती है तो अधिकतर का टका सा जवाब होता है- जिसे बनाना हो पार्टी बना दे, लेकिन अब जल्दी बना दे।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

नरेंद्र मोदी : योद्धा और विजेता

मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से उनके द्वारा किए गए कार्यों को कुछ शब्दों में बयां करना, एक छोटे से जहाज में सागर भरने जैसा होगा। आने वाले दशकों में, उनके अनुकरणीय योगदान को उचित रूप से मान्यता दी जाएगी

डॉ हर्षवर्धन
(लेखक, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं)

प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से उनके द्वारा किए गए कार्यों को कुछ शब्दों में बयां करना, एक छोटे से जहाज में सागर भरने जैसा होगा। आने वाले दशकों में, भारत को बचाने में उनके अनुकरणीय योगदान को उचित रूप से मान्यता दी जाएगी, जो अन्यथा कांग्रेस और उसके साथियों द्वारा सुनिश्चित किए गए रसातल में चला जाता। प्रधानमंत्री मोदी एक मानसिकता प्रदर्शित करते हैं और हमारे वैदिक दर्शन में निहित शासन के सिद्धांतों का पालन करते हैं। भारतीय परिदृश्य पर उनके प्रकट होने से पहले, सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग की मानसिकता औपनिवेशिक और अधीनस्थ थी, जो साहसिक निर्णय लेने से बहुत डरता था। भारतीय शास्त्रों में एक आदर्श शासक के कई गुणों की रूपरेखा दी गई है – जो सक्षम, दयालु और अन्याय के खिलाफ दृढ़ रुख बनाए रखते हुए मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हो। ये महाभारत में वर्णित एक आदर्श राजा के छत्तीस गुणों में से हैं। महाभारत के नायक भीष्म ने घोषणा की कि चाहे युग राजा को आकार देता है, या राजा युग को आकार देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है – यह राजा ही है जो यह निर्धारित करता है कि समय अच्छा होगा या बुरा –
कालोवाकारणंराज्ञोराजावाकाल.कारणम्।
इतितेसंशयोमाभूद्.राजाकालस्यकारणम्॥

श्री मोदी ने इन प्राचीन और समय-परीक्षित गुणों को अपने निजी जीवन और आचरण में आत्मसात करके इनके प्रति अपना स्पष्ट समर्थन प्रदर्शित किया है। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण अन्य धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हमारी सभ्यता के वैदिक स्तंभों को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू करने की उनकी पहल का विश्व स्तर पर स्वागत किया गया, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी, और यह भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिह्नित है। उनकी उपलब्धियों का पूरा विवरण देने के लिए कई खण्डों की आवश्यकता होगी। इस संक्षिप्त विवरण में, हम उन चार क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें उन्होंने बदल दिया- अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और स्वास्थ्य। तेज़ी से हो रहे औद्योगीकरण के बावजूद, कृषि अभी भी रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है। लगभग 40 प्रतिशत श्रमिकों को कृषि में रोज़गार मिलता है, जबकि केवल 20 प्रतिशत विनिर्माण और अन्य सेवाओं में काम करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके उत्पादकता को बढ़ावा देना है। किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है जो प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, परम्परागत कृषि विकास योजना जैसी पहल टिकाऊ और जैविक खेती के तरीकों का समर्थन करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं जैसे सरकारी कार्यक्रमों और पहलों ने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व बैंक के अनुसार, 2011-12 में 27.1 प्रतिशत से 2022-23 में 5.3 प्रतिशत तक अत्यधिक गरीबी में कमी आई है।

सामाजिक क्षेत्र में श्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं के कल्याण पर बहुत ज़ोर दिया है। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और निर्णय लेने में अपर्याप्त पहुँच का सामना करना पड़ा है – विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में। 2014 से, प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में, परिदृश्य बदल गया है। मोदी सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी योजनाओं ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में योगदान दिया है। पीएम आवास योजना, डीएवाई-एनआरएलएम और कृषि सहायता पहल जैसी योजनाओं ने महिलाओं को अधिक वित्तीय और सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की है।

पर्यावरण के मोर्चे पर, भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। कई शहरों में शहरी निवासी खतरनाक प्रदूषण स्तरों के संपर्क में हैं। फसल अवशेषों, लकड़ी और अन्य ठोस ईंधन को जलाने से घरेलू वायु प्रदूषण का गंभीर प्रभाव कम ही लोगों को पता है।

अकेले 2020 में, घरेलू वायु प्रदूषण पांच वर्ष से कम उम्र के 2,37,000 से अधिक बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार था। महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं, और यह संकट दशकों तक काफी हद तक अनदेखा रहा। घरेलू वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए, मई 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। इस योजना ने गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने, जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन की जगह स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।

इन नौ वर्षों में, इस योजना ने देश भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। 01.03.2025 तक, पूरे भारत में 10.33 करोड़ कनेक्शन हैं। भारत द्वारा अपनी प्राकृतिक विरासत को बहाल करने के प्रयासों को मान्यता देते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी को पुनर्जीवित करने की पहल के लिए भारत सरकार को एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत में प्रमुख नदियों का प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन गंगा बेसिन- 520 मिलियन से अधिक लोगों और लगभग 25,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर- पुनरुद्धार के संकेत दे रहा है। गंगा का मैदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 40त्न का योगदान देता है, और इसके जंगल कार्बन कैप्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने %नमामि गंगे कार्यक्रम% के रूप में जानी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। प्रदूषण में परिणामी कमी ने वनों की कटाई को रोकने में मदद की है; नदी के 2,525 किलोमीटर हिस्से में से 1,500 किलोमीटर का कायाकल्प किया गया है और 30,000 हेक्टेयर वनों को बहाल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करने की पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के दस अग्रणी प्रयासों में से एक के रूप में मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के साथ उनके पर्यावरण नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। सौर ऊर्जा से समृद्ध देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए उनकी वकालत भारत की वैश्विक पर्यावरणीय दृष्टि को दर्शाती है।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर, प्रधानमंत्री मोदी ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत का पारंपरिक ज्ञान कहता है कि बीमारी का न होना अच्छे स्वास्थ्य के समान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को न केवल बीमारियों से मुक्त होना चाहिए बल्कि स्वस्थ रहने की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। योग, आयुर्वेद और ध्यान जैसी पारंपरिक प्रणालियों के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि यह स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को संबोधित करता है और इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि डब्ल्यूएचओ का पहला वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भारत में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण और पौष्टिक अनाज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हुए 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में वैश्विक मान्यता का भी जश्न मनाया। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के समग्र दर्शन की घोषणा की। उन्होंने 'एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य' के भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का दृष्टिकोण सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशुओं, पौधों और पर्यावरण सहित संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तक फैला हुआ है तथा इस बात पर बल दिया कि मानव स्वास्थ्य जीवमंडल की भलाई के साथ जुड़ा हुआ है।

सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना – आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार और देश के लाखों परिवारों को स्वच्छता और पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान की घोषणा की।

संक्षेप में, नरेंद्र मोदी हमारे पूज्य पूर्वजों द्वारा समर्थित लोकतांत्रिक शासन का उदाहरण हैं। जब राजा दशरथ ने अपनी वृद्धावस्था में राजगद्दी त्यागने की इच्छा जताई, तो उन्होंने श्री राम को राजगद्दी सौंपने से पहले अपने राज दरबारियों की सलाह और सहमति ली। विनम्रता और कर्तव्य की यह परंपरा आज भी जारी है।

जब श्री राम को ऋषि वशिष्ठ द्वारा उनके राज्याभिषेक की सूचना दी गई, तो वे और माता सीता शांतिपूर्वक अपने महल में लौट आए, स्नान किया और वैदिक परंपरा के अनुसार सर्वशक्तिमान की पूजा की। इसी तरह, प्रधानमंत्री मोदी का मंदिरों, आध्यात्मिक संस्थानों और पूज्य गुरुओं के दर्शन करना भक्ति की अभिव्यक्ति है, न कि केवल समारोह। उनका नेतृत्व गहरी सांस्कृतिक जड़ों और आध्यात्मिक आधार को दर्शाता है। भारत का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है और वैश्विक मंच पर देश का कद लगातार बढ़ रहा है। शायद बहुत जल्द ही दुनिया भारत को विश्व गुरु यानी राष्ट्रों के शिक्षक के रूप में देखने लगेगी।

यथार्थ की कसौटी पर मोदी के 11 साल

पवन खेड़ा
(लेखक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं)

ग्यारह साल पहले, 2014 में अच्छे दिन और एक बदले हुए भारत का वादा किया गया था — और इन वादों के आधार पर नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर उदय हुआ। आज, उन वादों को पूरे ग्यारह साल हो चुके हैं, और देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वैश्विक महाशक्ति और समावेशी लोकतंत्र की उम्मीदें टूटे हुए वादों, आंकड़ों की हेराफेरी और परिणाम के बजाय दिखावे पर आधारित शासन की वास्तविकताओं में बदल चुकी हैं। शासन अब एक तमाशा बन चुका है, घोषणाएं वास्तविक उपलब्धियों पर भारी पड़ रही हैं, और राष्ट्र एक गहन विश्वसनीयता संकट में फंसा हुआ है।

मोदी की विरासत उनकी कमजोर आर्थिक नीतियों पर टिकी है। नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी एक विनाशकारी नाकामी साबित हुई। बंद की गई 99.3 प्रतिशत मुद्रा बैंकों में वापस लौट आई, जिससे काले धन पर अंकुश लगाने का घोषित उद्देश्य विफल रहा। इसके विपरीत, इससे पैदा हुई नकदी की किल्लत ने असंगठित क्षेत्र की 9.5 लाख नौकरियों को खत्म कर दिया, जिसमें 4.77 करोड़ कर्मचारी शामिल थे।

जुलाई 2017 में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का उद्देश्य कर प्रणाली को एकीकृत करना था, लेकिन अपनी जटिलता के कारण यह भी विफल हो गया। इसकी बहु-दर संरचना, तकनीकी खामियों और ईंधन तथा रियल एस्टेट को इसमें शामिल न करने की नीति ने छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर भारी बोझ डाला।

मार्च 2020 में लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन ने गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट को जन्म दिया। सीएमआईई के अनुसार अप्रैल 2020 में 12.2 करोड़ भारतीय रोजगारविहीन हो गए। प्रवासी मजदूरों को आय की कमी, भोजन का अभाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, जबकि सरकार राहत से अधिक प्रचार-नियंत्रण में व्यस्त रही। स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर कुप्रबंधन और व्यापक मौतों ने संकट को और गहरा किया, जिससे लोगों का विश्वास और भी क्षीण हो गया।

2014 से सरकार ने सुधारों की अपेक्षा राजस्व कमाने को प्राथमिकता दी —एयर इंडिया की बिक्री, एलआईसी का आईपीओ , बीपीसीएल और कोनकोर जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की कोशिशें इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत सार्वजनिक आधारभूत संरचना को 6 लाख करोड़ मूल्य में लीज़ पर देने की योजना ने पारदर्शिता की कमी, लोक-हित के प्रति उदासीनता और जवाबदेही की समस्या को उजागर किया। इससे नौकरियाँ घटीं, असमानता बढ़ी और सार्वजनिक नियंत्रण कम हो गया।

साथ ही, भारत में रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। 95 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधे से भी कम लोगों के पास रोजगार है, जबकि 'एशियाई टाइगर' अर्थव्यवस्थाओं में यह दर 70 प्रतिशत के आसपास है। बहुत से लोग स्वरोजगार या बिना वेतन के पारिवारिक कार्य में लगे हैं, जिससे छुपी बेरोजगारी का पता नहीं चलता।

वर्ष 2023 में कामकाजी महिलाओं में से केवल 32.7 महिलाएं के पास रोजगार था, और कॉलेज स्नातकों में से मात्र आधे ही रोजगार के योग्य थे। आईएलओ के अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा युवा एनईईटी (ना पढ़ाई, ना रोजगार, ना प्रशिक्षण) श्रेणी में हैं। शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत 2000 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 66 प्रतिशत हो गया। सरकारी नौकरियों में रिक्त पद खाली पड़े हैं, और अग्निपथ योजना सेना में भर्ती चाहने वाले युवाओं में असंतोष फैलाने वाली बनी।

लेकिन भाजपा की अब तक की सबसे भयावह देन सार्वजनिक जीवन का सांप्रदायिकरण है। भड़काऊ भाषण, मुस्लिम-विरोधी कानून जैसे सीएए-एनआरसी ने धार्मिक असहिष्णुता को सामान्य बना दिया है। भाजपा नेताओं की घृणास्पद भाषा को अनदेखा किया जाता है, जबकि सार्वजनिक जीवन में मुस्लिमों की हिस्सेदारी तेज़ी से घट रही है।

त्योहारों और कानून व्यवस्था को हथियार बनाकर मुसलमानों को खतरे के रूप में पेश जाता है, और भाजपा समर्थक मीडिया डर और झूठ फैलाने का काम करती है। 2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जानें गई, विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों की भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएँ हुईं, और 'लव-जिहाद' जैसे विभाजनकारी रणनीतियों ने सत्ताधारी पार्टी की नफरत भरी राजनीति को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर राज ने न्यायेतर विध्वंस और सामूहिक दंड वाले शासन मॉडल को जन्म दिया है, जो अक्सर मुसलमानों, दलितों और राजनीतिक असहमति दर्ज कराने वाले लोगों को निशाना बनाता है। इस रणनीति ने रोज़मर्रा के सांप्रदायिक विखंडन को मजबूत किया, जिससे भारत के धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक मूल्यों को झटका लगा है।

बिना किसी गंभीर बहस के पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ़ किसानों ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ा, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हुए। सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और खालिस्तानी कहकर बदनाम किया। अंततः सरकार ने कानूनों को वापस तो लिया, लेकिन मुआवज़े की मांगों को अनसुना कर दिया गया।

हाथरस, कठुआ और उन्नाव जैसी बलात्कार की बड़ी घटनाएँ महिलाओं की सुरक्षा में सरकार की विफलता को उजागर करती हैं। भाजपा सांसद पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को कभी न्याय नहीं मिला, और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी सैन्य अधिकारी को केवल सांकेतिक सम्मान दिया गया।

डांगावास की लिंचिंग, रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसी दलित आत्महत्याएँ इस तंत्र के भ्रष्ट चरित्र को दिखाती हैं, जिसे सुधारने से इस सरकार ने इनकार कर दिया है। पानी के बर्तन को छूने पर दलित बच्चे इंद्र मेघवाल की हत्या ने अभी भी मौजूद जातीय भेदभाव को बखूबी उजागर किया। अपराधियों के खिलाफ निम्न सज़ा दर और लंबे समय तक छूट सरकार की मिलीभगत को दर्शाते हैं।

2014 के बाद से भारत, जिसे कभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था, उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएँ लगातार कमजोर हो रही हैं। संवैधानिक संतुलन ढह रहा है, संस्थानों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, और असहमति को अपराध मानकर दबाया जा रहा है। ये सब हमें एक चुनावी तानाशाही की छोर पर ले आया है।

नागरिक स्वतंत्रता भी लगातार घट रही है। फ्रीडम हाउस ने भारत को पार्टली फ्री बताया है, और वीडेम ने इसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा है। 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है, जहाँ पत्रकारों का उत्पीड़न प्रमुख वजह बताया गया है। 2015 से 2025 तक ईडी ने 193 विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ़ मामले दर्ज किए हैं, जबकि 95 प्रतिशत सीबीआई जांचें विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती हैं। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए के संदिग्ध साक्ष्य और यूएपीए (3 प्रतिशत) तथा पीएमएलए(0.4) की निम्न सज़ा दर यह दिखाती हैं कि सरकार न्याय के बजाय डर फैलाने में विश्वास रखती है। एफसीआरए के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित 20,600 से अधिक एनजीओ लाइसेंस रद्द किए गए, जिससे लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाया गया।

चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा; यह मोदी सरकार के चुनावी तानाशाही की व्यवस्था का सहायक बन गया है। 2018 में 'इलेक्टोरल बॉन्ड्स' की व्यवस्था ने गुप्त कॉर्पोरेट चंदों को वैधता दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इसे असंवैधानिक करार दिया, इससे भाजपा को 6,060 करोड़ मिले थे (पूरे बॉन्ड राशि का करीब 48 प्रतिशत)—जो कि वोटरों के अधिकारों का हनन और कॉर्पोरेट सौदों का सहारा था।

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर में संचार व मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध और कानूनी परिवर्तन के जरिए शांति स्थापित करने का वादा किया गया था, लेकिन इनसे शांति हासिल नहीं हुई। मिलिटेंसी जारी है, आर्थिक विकास धीमा है, और लद्दाखियों में राज्य का दर्जा देने की माँगें तेज़ हो रही हैं।

केन्द्र सरकार अपनी पीठ थपथपाने के बावजूद जम्मू-कश्मीर को 'सुरक्षित' करने में पूरी तरह विफल रही। पठानकोट (7 की मौत), उरी (19 सैनिक), अमरनाथ यात्रा (8 नागरिक), पुलवामा (40 जवान) और हाल की पहलगाम घटना (26 नागरिक) जैसी सुरक्षा विफलताओं ने इंटेलिजेंस की कमज़ोरी और सरकार की लचर रणनीति को उजागर किया है। मोदी की पाकिस्तान नीति — कभी अचानक दौरे, तो कभी एयर स्ट्राइक — निरंतरता और स्पष्टता से रहित रही है, जो कि सीमा पर खतरों पर लगाम लगाने में विफल रही है।

मई 2023 में शुरू हुआ मणिपुर संकट, जिसमें मैतेई- कूकी झड़प ने 250 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और 60,000 लोग विस्थापित हो गए; लेकिन मोदी की चुप्पी और अमित शाह की निष्क्रियता के साथ एक विवादास्पद मुख्यमंत्री के समर्थन ने , इस राज्य को एक 'अनाथ' स्थिति में पहुँचा दिया।

घरेलू तबाही से परे, मोदी की विदेश नीति का रिकॉर्ड भी एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है जो गंभीर समीक्षा की माँग करता है। लेकिन एक सरसरी निगाह इस शासन की अक्षमता को उजागर करती है, 2017 के डोकलाम गतिरोध ने चीन को वहाँ स्थायी रूप से जमने का मौका दिया।

2020 की गलवान झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई और चीन ने एलएसी पर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चीन-पाकिस्तान गठजोड़ सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों पर और मज़बूत हुआ है—चीन न केवल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को ढाल बनकर बचाता रहा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की कोशिशों को बार-बार बाधित भी करता रहा है।

दिल्ली में मोदी के आगमन के बाद से भारत ने अपने पड़ोसी देशों में भी अपना प्रभाव खोया है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश अब इन्फ्रास्ट्रक्चर और रक्षा साझेदारियों के ज़रिए चीन के साथ और अधिक निकटता बना चुके हैं। संकटों को नज़रअंदाज़ कर मोदी ने जवाबदेही के बजाय दिखावे को प्राथमिकता दी, जिससे भारत की वैश्विक साख और नेतृत्व क्षमता को गंभीर आघात पहुँचा है।

यह सूची पूरी नहीं है और पतन के गहरे गर्त में केवल साफ दिख रही दरारों को ही उजागर करती है। ग्यारह साल बाद मोदी युग ने एक ऐसी शासन शैली सामने रखी है, जो सार्थकता की जगह प्रदर्शन को स्थापित करती है, सेवा के बजाय नियंत्रण को महत्व देती है, और विकास से अधिक विभाजन को प्रोत्साहित करती है।

जहाँ परिवर्तन का आश्वासन था, वहां एक खोखला गणराज्य बन चुका है — जिसकी अर्थव्यवस्था, संस्थाएं, सामाजिक ताना-बाना और नैतिक दिशा सभी खिसक चुके हैं। कश्मीर से मणिपुर तक, दलितों से पहलवानों तक, युवाओं से किसानों तक — सभी ने न्याय की मांग की, लेकिन केवल आपराधिक उदासीनता पाई।

मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन देश को एक पिछड़ते हुए लोकतंत्र की ओर धकेल दिया।

शिखर से शून्य की ओर मोहम्मद यूनुस

नीलांत इलांगमुआ

इस सप्ताह सिराजगंज में रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हुआ हमला महज एक घटना नहीं बल्कि बांग्लादेश की गिरावट का एक स्पष्ट लक्षण है। कभी सांस्कृतिक अभयारण्य रहा यह स्थान अब एक मामूली विवाद पर भीड़ की हिंसा से अपवित्र हो गया है – यह एक ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जो चरमपंथ, संस्थागत पतन और राजनीतिक अराजकता से जूझ रहा है। राज्य की कमजोर प्रतिक्रिया उसके कमजोर होते नियंत्रण को उजागर करती है, जबकि उथल-पुथल मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के खंडित प्रबंधन के भयावह गलत आकलन को दर्शाती है। कभी माइक्रोफाइनेंस के वास्तुकार और नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में दुनिया भर में प्रतिष्ठित, जिनके काम ने सामाजिक उद्यमिता को फिर से परिभाषित किया, मुहम्मद यूनुस का बांग्लादेश के राजनीतिक क्षेत्र में प्रक्षेपवक्र विरोधाभासी रूप से संक्षारक साबित हुआ है। कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति, जिसका उद्देश्य निष्पक्षता और एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करना था, इसके बजाय गहराते पक्षपातपूर्ण विद्वेष और प्रशासनिक अदूरदर्शिता का पर्याय बन गई है। अवामी लीग और विशेष रूप से इसकी नेता शेख हसीना – श्रद्धेय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की वंशज – के प्रति यूनुस की तीखी दुश्मनी उनके शासन की परिभाषित विशेषता बन गई है।

यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि शेख हसीना ने एक बार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में यूनुस को कैद करने की कोशिश की थी, आरोप है कि यूनुस ने उनके खिलाफ सार्वजनिक असंतोष को भड़काने और न केवल उन्हें सत्ता से बेदखल करने के प्रयासों को तेज करने के लिए बल्कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना पर उनके परिवार की स्थायी छाप को व्यवस्थित रूप से मिटाने के लिए चालाकी से हेरफेर किया है। यह प्रतिशोध देश के करेंसी नोटों से बंगबंधु की तस्वीर को हटाने से ज्यादा कहीं और दिखाई नहीं देता है। 1971 से, राष्ट्रपिता की छवि टका पर उकेरी गई है, जो मुक्ति संग्राम के लिए एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि और पहचान का एक एकीकृत प्रतीक है। यूनुस प्रशासन द्वारा इस चिरस्थायी प्रतीकात्मकता को सांस्कृतिक स्थलों से प्रतिस्थापित करना, जिसे मुद्रा के अराजनीतिकरण के बहाने तैयार किया गया, खुद को संयमित शासन से कम भावनात्मक प्रतिशोध की कार्रवाई के रूप में प्रकट करता है। बांग्लादेश के जन्म को मूर्त रूप देने वाले चेहरे को मिटा देना देश को उसकी जड़ों से अलग करना है, एक प्रतीकात्मक विकृति जो सामूहिक स्मृति को खंडित करने की धमकी देती है।

यूनुस की बयानबाजी ने विभाजन को और बढ़ा दिया है। लंदन के चैथम हाउस में एक विवादास्पद भाषण में, उन्होंने खुले तौर पर अवामी लीग की वैधता पर सवाल उठाया। उनके भड़काऊ बयान न केवल एक राजनीतिक पार्टी को अवैध बनाते हैं; वे उन लाखों नागरिकों को अलग-थलग कर देते हैं जिन्होंने दशकों से अवामी लीग में अपना विश्वास जताया है। यह ध्रुवीकरण प्रवचन पहले से ही कमजोर राजनीति के भीतर दरारों को और गहरा करता है उसी चैथम हाउस फोरम में, यूनुस ने दुख जताया कि अर्थव्यवस्था न केवल रुकी हुई है, बल्कि शून्य से भी नीचे चली गई है, अत्यधिक ऋण दबाव के बोझ तले दबी हुई है और विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले स्तर पर है – क्योंकि वे खाली हैं। उन्होंने खुलासा किया कि बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से व्यापक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार है। यह खुलासा कि अवैध माध्यमों से अरबों डॉलर – अनुमानित 234 बिलियन डॉलर – निकाले गए हैं, प्रणालीगत लूट की एक भयावह तस्वीर पेश करता है, जो सुधार की किसी भी संभावना को समाप्त कर सकता है। हालांकि, अतीत के अभियोग वर्तमान पहेली को भी उजागर करते हैं- अंतरिम सरकार ने स्वयं प्रणालीगत सड़ांध को विरासत में प्राप्त किया और उसे कायम रखा। बैंक बोर्डों को उपहार के रूप में ऋण जारी करने वाले मित्रों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापित करना संस्थागत शिथिलता को बढ़ाता है। भाई-भतीजावाद, दंड से मुक्ति और राजनीतिक हस्तक्षेप से अपंग बैंकिंग क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने की चुनौती बड़ी है, एक ऐसा कार्य जो चल रहे गुटीय संघर्ष और बिगड़ते शासन ढांचे के कारण और भी कठिन हो गया है।

वैश्विक स्तर पर, यूनुस के कद में स्पष्ट गिरावट आई है। आईएमएफ और विदेशी सरकारों से भारी समर्थन की घोषणाओं के बावजूद, वास्तविकता अधिक गंभीर तस्वीर पेश करती है। उल्लेखनीय रूप से, यू.के. के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक राजनयिक मिशन के दौरान यूनुस से मिलने से कथित तौर पर इनकार कर दिया, जो कूटनीतिक ठंडेपन का एक स्पष्ट संकेत है जो विश्व मंच पर उनकी अनिश्चित स्थिति को उजागर करता है। यह मौन प्रतिवाद उनकी पिछली वैश्विक प्रशंसा के विपरीत है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे घरेलू राजनीतिक उलझनों और कथित अस्थिरता ने उनकी विश्वसनीयता को कम कर दिया है।

इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकवाद के प्रति अंतरिम सरकार के संशोधनवादी दृष्टिकोण ने केवल आबादी के व्यापक हिस्से को अलग-थलग करने का काम किया है। पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन, सार्वजनिक स्थानों से शेख मुजीब की मूर्तियों को हटाना और अवामी लीग की गतिविधियों को निलंबित करना व्यापक रूप से सुधार के रूप में नहीं बल्कि दंडात्मक शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है। यह व्यवहार राजनेता के रूप में प्रच्छन्न संप्रदायवाद की बू आती है – परिपक्व नेतृत्व का एक गहरा उल्लंघन जिसकी बांग्लादेश को तत्काल आवश्यकता है। नेशनल सिटिजन पार्टी जैसी उभरती राजनीतिक संस्थाओं की प्रतिक्रियाएँ राजनीतिक परिवेश को जकड़ने वाले व्यापक संदेह को व्यक्त करती हैं। अगले साल की पहली छमाही में चुनावों की संभावना का अस्थायी रूप से स्वागत करते हुए, एनसीपी ने व्यापक संस्थागत सुधारों के साथ-साथ जुलाई चार्टर और घोषणा के कार्यान्वयन पर अपना समर्थन दिया है। चुनाव आयोग के पुनर्गठन और स्थानीय चुनावों को प्राथमिकता देने पर उनका जोर किसी भी विश्वसनीय राष्ट्रीय वोट के होने से पहले आधारभूत नवीनीकरण की मांग का संकेत देता है। यह सतर्क रुख समझौतावादी लोकतंत्र के एक और चक्र में फंसने से सावधान नागरिक समाज की व्यापक चिंताओं को दर्शाता है।

गहरी पैठ वाले संरक्षण प्रणालियों से ग्रस्त देशों में चोरी की गई संपत्तियों को वापस पाने की खोज को व्यापक रूप से सिज़िफ़ियन के रूप में स्वीकार किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और विश्व बैंक जैसे शासन निगरानीकर्ताओं द्वारा किए गए व्यापक शोध से स्पष्ट होता है कि इस तरह के प्रयासों के लिए न केवल घरेलू संकल्प की बल्कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, फोरेंसिक अकाउंटिंग विशेषज्ञता और राजनीतिक दबाव को झेलने में सक्षम न्यायपालिका की भी मांग बांग्लादेश की मौजूदा दरारें और संस्थागत कमज़ोरियाँ ऐसी महत्वाकांक्षाओं को गंभीर रूप से बाधित करती हैं, जिससे युनुस के अवैध पूंजी को बिना किसी ठोस, एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास के वापस लाने के वादों की व्यवहार्यता पर संदेह पैदा होता है। युनुस का कार्यकाल उस खतरे को दर्शाता है जो तब निहित होता है जब एक कमज़ोर लोकतंत्र को ऐसे नेतृत्व को सौंपा जाता है जो राजनीति के स्थान पर प्रतिशोध को प्राथमिकता देता है – इतिहास को ज्ञान देने के लिए नहीं बल्कि मिटाने के लिए फिर से लिखना। बांग्लादेश के राजनीतिक वास्तुकार के रूप में मुहम्मद युनुस का उदय और उनका अचानक पतन, उन परिणामों की एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो तब होते हैं जब व्यक्तिगत दुश्मनी सार्वजनिक कर्तव्य को बदल देती है।

राजनीतिक उद्देश्यों की उनकी निरंतर खोज, जो अवामी लीग और उसकी गौरवशाली विरासत के प्रति उनकी स्थायी शत्रुता से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को खतरे में डाला है, बल्कि राष्ट्र को और अधिक विखंडन और निराशा में धकेलने का खतरा पैदा किया है। मुद्रा और सार्वजनिक स्मृति से बंगबंधु का प्रतीकात्मक सफाया केवल मूर्तिभंजन से कहीं अधिक है; यह राष्ट्र की आत्मा का अपमान है। नतीजतन, 'नए बांग्लादेश' का भविष्य आर्थिक ठहराव, प्रतिशोधी राजनीति और उग्रवाद की बढ़ती लहर के बोझ तले अधर में लटक गया है।

समावेशी शासन, ऐतिहासिक विरासत के प्रति सम्मान और मजबूत संस्थागत सुधार की दिशा में बुनियादी बदलाव के बिना, बांग्लादेश युद्धोन्मादी पश्चिमी लोकतंत्रों द्वारा संचालित शासन-परिवर्तन परियोजनाओं के विनाशकारी परिणामों में एक चेतावनीपूर्ण केस स्टडी बनने का जोखिम उठाता है – राष्ट्र अपने हस्तक्षेपों में विवेक से रहित हैं, जो राजनीतिक सुविधा के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid

इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अगर विस्तार लेता है तो यह जहां वैश्विक जंग की शक्ल ले सकता है, वहीं वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और खाद्यान्न आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इजरायल और ईरान के बीच ताजा अदावत बढ़ने की वजह आतंकी गुट हमास का पिकनिक मना रहे इजरायलियों पर वहशियाना हमला है। इजरायल ने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हमास के खिलाफ सैन्य संघर्ष शुरू किया। इजरायल के खिलाफ हमास को खड़ा करने में ईरान का हाथ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह व हूती के पीछे भी ईरान है। ईरान ने इजरायल को परेशान करने के लिए उसकी जमीनी सीमाओं से लगे देशों में हमास, हिजबुल्लाह व हूती जैसे सशस्त्र आतंकी गुट खड़े किए। इजरायल इन तीनों आतंकी गुटों के खिलाफ निर्णायक सैन्य संघर्ष कर रहा है और इस दौरान तीनों की कमर तोड़ दी है। शिकस्त होते देख ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल को निशाना बनाया था। उसके बाद इजरायल ने भी ईरान को करारी चोट पहुंचाई। अब इजरायल ने फिर से ईरान के अंदर घुसकर अब तक का सबसे करारा प्रहार किया है। अमेरिका खुले तौर पर इजरायल के साथ है व ये दोनों मुल्क नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने की स्थिति में आए। ईरान का बदला क्या रुख लेगा, आजकल के इस अंक में पेश है विश्लेषण...

मध्य पूर्व में विनाशकारी युद्ध की दस्तक

विश्लेषण
प्रभात कुमार रॉय
विदेश मामलों के जानकार

यूरोपीय काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का कहना है कि इजरायल ने ईरान पर आक्रमण इसलिए अंजाम दिया ताकि परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए ईरान से समझौता करने की ट्रंप की संभावनाओं को एकदम खत्म किया जा सके। अनेक रणनीतिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस युद्ध के बड़े पैमाने पर विस्तार होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सैन्य रणनीति के विशेषज्ञ यह भी बयान करते हैं कि इजरायल की संसद और हुकूमत की कैबिनेट में ऐसे राजनीतिज्ञ विद्यमान हैं, जोकि ईरान से युद्ध चाहते हैं और उसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री पर राजनीतिक दबाव भी कायम कर सकते हैं। युद्ध हमेशा के टाला नहीं जा सकता, बल्कि आने वाले दौर में इसका दायरा और अधिक बढ़ सकता है।

इजरायल और ईरान के मध्य उत्पन्न हुए आक्रमणकारी सैन्य तनाव के कारण क्या मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर एक विनाशकारी युद्ध प्रारंभ होने का खतरा उत्पन्न हो गया है? प्रश्न है कि आखिरकार यही वक्त इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के लिए क्यों चुना गया? विकट प्रश्न उठता है कि इजरायल और ईरान में यदि एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव स्थापित होगा?

उल्लेखनीय है कि रविवार 16 जून को ईरान और अमेरिका के मध्य परमाणु समझौते को लेकर समझौता वार्ता छठे दौर में पहुंच जाएगी। नेतन्याहू के लिए यह सटीक मौका था कि ईरान पर सैन्य आक्रमण अंजाम देकर इस वार्ता को विफल कर सकते हैं। यूरोपीय काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का कहना है कि इजरायल ने ईरान पर आक्रमण इसलिए अंजाम दिया ताकि परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ईरान से समझौता करने की राष्ट्रपति ट्रंप की संभावनाओं को एकदम खत्म किया जा सके। अनेक रणनीतिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस युद्ध के बड़े पैमाने पर विस्तार होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सैन्य रणनीति के विशेषज्ञ यह भी बयान करते हैं कि इजरायल की संसद और हुकूमत की कैबिनेट में ऐसे राजनीतिज्ञ विद्यमान हैं, जोकि ईरान से युद्ध चाहते हैं और उसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री पर बड़ा राजनीतिक दबाव भी कायम कर सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जब भी स्वयं को राजनीतिक तौर पर अपने देश में कमजोर पाते हैं, वह तुरंत ही ईरानी कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। रणनीति के कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि युद्ध हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता, बल्कि आने वाले दौर में इसका दायरा और अधिक बढ़ सकता है।

परदे के पीछे अमेरिका भी शामिल

संभव है कि ईरान तत्काल इजरायल पर हमला न बोले, लेकिन ईरान सैन्य प्रतिशोध अवश्य ही लेगा। सैन्य संघर्ष का सिलसिला अब बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। अमेरिकन सरकार भले ही दावा पेश कर रही है कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इजरायली बॉम्बर फाइटर जेट्स द्वारा कतर में स्थित अमेरिकन एयर फोर्स बेस से बाकायदा ईंधन लिया गया है। ईरान द्वारा जो ड्रोन इजराइल पर आक्रमण करने के लिए रवाना किए थे, उनको भी अमेरिका द्वारा मार गिराया गया। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन विमानों को इजरायल तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव में इजराइल को अपना एयरस्पेस बाकायदा इस्तेमाल करने दिया। निश्चित तौर पर यह जंग ईरान और इजरायल के मध्य सीमित नहीं रह गई है। इजरायल की हिब्रू यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि तकरीबन 75 फीसदी इजरायली ईरान पर सैन्य कार्यवाही करने के एकदम विरुद्ध हो गए हैं। इजरायली जनमानस यकीनन निरंतर युद्ध से अब बेहद तंग आ चुके हैं। ईरान के साथ यदि इजरायल का एक बड़े पैमाने पर युद्ध प्रारम्भ हो जाता है तो इजरायल को फिर युद्ध में चौतरफा आक्रमणों का मुकाबला करना पड़ सकता है। लेबनान में ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ते हुए सक्रिय हिजबुल्ला तंजीम के गोरिल्ला लड़ाके, ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ते हुए दक्षिण यमन के हूती विद्रोही, ईरान की सैन्य मदद के बलबूते पर इजराइल के अंदर युद्धरत हमास तंजीम के छापामार लड़ाके हमले करेंगे।

जंगजू शक्तियां इजरायल के विरुद्ध

सर्वविदित है कि ईरान के शिया समर्थकों की इराक और सीरिया में एक लंबी जंगजू फौज मौजूद है। ये सभी जंगजू शक्तियां इजरायल के विरुद्ध ईरान के पक्ष में युद्ध में अवश्य ही उतरेंगी। इजरायल की नेतन्याहू हुकूमत ने दावा पेश किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खात्मा करने के लिए इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर धावा बोलकर उसके कुछ सीनियर फौजी कमांडरों को हलाक कर दिया गया। इन हलाक होने वालों में इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी शामिल हैं। हुसैन सलामी 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के संरक्षक रहे और शाह के शासन का खात्मा करने में उनका प्रमुख किरदार रहा था। ईरान के कम से कम छह परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली शामख़ानी भी इजरायली आक्रमण में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ईरान की हुकूमत के मुताबिक इजरायल ने तेहरान और दूसरे अन्य नगरों के रिहायशी इलाकों को अपना फौजी निशाना बनाया। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ऐलान किया कि इजरायल की जियोनिस्ट हुकूमत को अब ईरान से अत्यंत सख्त सजा की उम्मीद रखनी चाहिए।

विराट है ईरान की मिसाइल परियोजना

ईरान की फौज इजरायल को सख्त से सख्त सजा दिए बिना कदापि नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने दावा पेश किया कि ईरान द्वारा इजरायल पर 100 से अधिक ड्रोन दागे गए। विगत वर्ष 2024 के अप्रैल महीने में भी इजरायल और ईरान के मध्य एक अल्पकालिक जंग लड़ी गई थी। इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान पर किया गया एक जबरदस्त आक्रमण है। यह हमला विगत वर्ष ईरान के अंजाम दिए गए मिसाइल और ड्रोन संघर्ष से कहीं अधिक व्यापक और विनाशकारी है। इजरायल और ईरान के मध्य तकरीबन 2100 किलोमीटर की दूरी मौजूद है। अगर ईरान को इजरायल पर आक्रमण करना होगा तो उसे ड्रोन और मिसाइलों द्वारा धावा बोलना होगा। उल्लेखनीय है कि ईरान की फौज के पास फिलहाल तकरीबन 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल विद्यमान हैं। ईरान की मिसाइल परियोजना मध्य पूर्व के देशों में सबसे विराट और सबसे अधिक विविधतापूर्ण मिसाइल परियोजना है। ईरान द्वारा अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन सिस्टम पर काफी महत्वपूर्ण काम किया गया है। विशेष कर 1980 से 1988 के मध्य पड़ोसी देश इराक के विरुद्ध दीर्घकालीन युद्ध के दौरान ईरान ने इनका अत्यंत संजीदगी और विविधता के साथ निर्माण शुरू किया। ईरान द्वारा छोटी रेंज की मिसाइलों और ड्रोन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया। सऊदी अरब और इजरायल पर दक्षिण यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागी सभी मिसाइलें ईरान द्वारा प्रदान की जाती रही। इजरायल के द्वारा अंजाम दिए गए आक्रमण में परमाणु संस्थानों के साथ-साथ मिसाइल और एयर डिफेंस के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। क्षेत्रफल के मुताबिक ईरान वस्तुत इजरायल से कहीं बड़े क्षेत्रफल वाला मुल्क है। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है और इजरायल की आबादी लगभग एक करोड़ है। इजरायल के सैनिकों की तुलना भी ईरानी सैनिकों की संख्या में तकरीबन तीन गुनी है। ईरान की सैन्य सेवा में 6 लाख सक्रिय सैनिक विद्यमान हैं और इजरायल के पास आधिकारिक तौर पर तकरीबन 1,70000 सैनिक विद्यमान हैं।

इजरायल परमाणु हथियारों से लैस देश

सर्वविदित है इजरायल परमाणु हथियारों से लैस देश है, हालांकि इस विषय में कोई स्पष्ट जानकारी प्रदान करने से इजरायल सदैव बचता रहा है। ईरान के पास परमाणु हथियार विद्यमान होने की संभावनाएं बहुत कम प्रतीत होती है। ईरान पर परमाणु हथियार निर्मित करने की कोशिश करने का इल्जाम निरंतर आयद रहा है। लेकिन ईरान इस संगीन इल्जाम से सदैव इनकार करता रहा है। आज के दौर में दुनिया दो शक्तिशाली सैन्य ध्रुवों में विभाजित होती प्रतीत हो रही है। एक तरफ शक्तिशाली सैन्य ध्रुव में अमेरिका और नाटो देश हैं, तो दूसरी तरफ शक्तिशाली सैन्य ध्रुव में चीन, रूस, ईरान, उत्तरी कोरिया आदि अनेक देश हैं। ऐसी स्थिति में विकट प्रश्न यह उठता है कि इजरायल और ईरान यदि पूरी तरह युद्ध में संलग्न हो जाते हैं तो भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? निश्चित तौर पर इजरायल और ईरान के मध्य सैन्य टकराव की विकट स्थिति में भारत का रुख अत्यंत संतुलनवादी रहेगा। भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न ईरान के पक्ष में कदाचित नहीं है। यकीनन भारत भी इजरायल द्वारा ईरान पर हमले का समर्थन कदापि नहीं करेगा। विगत माह मई में जब भारत ने पाकिस्तान के बहुत अंदर घुसकर सैन्य ठिकानों पर आक्रमणकारी धावा बोला था तो उस वक्त इजरायल ने भारत का एकदम खुलकर समर्थन किया था। इजरायल की हुकूमत ने बयान दिया था कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। वहीं ईरान ने भी पाकिस्तान का समर्थन तो नहीं किया और दोनों देशों के मध्य सैन्य तनाव समाप्त कराने के लिए मध्यस्थता करने की भी कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान द्वारा भारत व पाक के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान स्वयं को तटस्थ बनाए रखने की रणनीति अख्तियार की गई थी। इजरायल और ईरान के मध्य आक्रमणकारी सैन्य संघर्ष में भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इजरायल और ईरान को कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से परस्पर विवाद को सुलझाना चाहिए और सैन्य टकराव से पूरी तरह बचना चाहिए। ईरान और इजरायल दोनों देशों के साथ भारत के अत्यंत निकट मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। भारत हर तरह से दोनों देशों की कूटनीतिक मदद करने के लिए तैयार है। भारतीय विदेश नीति के कुछ विशिष्ट जानकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत वस्तुतः सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता देश है। मध्य पूर्व के इलाके में यदि युद्ध का दायरा बढ़ेगा, जिसकी भागीदारी वैश्विक तेल उत्पादन में तकरीबन एक तिहाई है।

इजरायल व ईरान के साथ भारत के गहरे संबंध

निश्चित तौर पर तेल और गैस की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा तो फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर मुत्तासिर हो जाएगी। ऐतिहासिक रूप से गल्फ ऑपरेशन काउंसिल के छह मुल्क बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, और यूएई के साथ ही इराक भारत के लिए तेल और गैस की आपूर्ति करने वाले मुल्क हैं। रूस से तेल और गैस का तकरीबन 40 फीसदी खरीदारी करने से भारत की निर्भरता गल्फ मुल्कों पर कुछ हद तक कम हो गई है। फिर भी भारत के तेल और गैस आपूर्ति में गल्फ मुल्कों का योगदान तकरीबन 50 फीसदी से अधिक रहा है। भारत का विदेशी व्यापार गल्फ और पश्चिम एशिया के साथ तकरीबन 209 अरब डॉलर का है अर्थात भारत के कुल विदेशी व्यापार का तकरीबन 19 प्रतिशत रहा है। इससे प्रतीत होता है कि भारत के लिए पश्चिम एशिया और गल्फ कंट्री कितनी महत्वपूर्ण है। भारत कदापि नहीं चाहता है कि यह युद्ध का दायरा विस्तारित हो जाए। इजरायल और ईरान के साथ भारत के गहरे संबंध रहे हैं और भारत द्वारा फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने में एक बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई जा सकती है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

परमाणु हथियार पर नियंत्रण के लिए हमले

ईरान-इजरायल
प्रमोद भार्गव
साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार

इजरायल और ईरान के बीच युद्ध आरंभ हो गया है। इजरायल ने ईरान के विरुद्ध बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। इसे 'ऑपरेशन राइजिंग लॉयन' नाम दिया गया है। यानी इजरायल एक ऐसा युद्ध करता हुआ देश है, जो ईरान की ओर शेर की मस्तानी चाल से बढ़ रहा है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, तब उन्होंने अपने झंडे पर छलांग लगाते शेर को प्रतीक बनाया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस आक्रमण की पुष्टि करते हुए कहा है, 'जब तक इजरायल के अस्तित्व पर खतरे बने रहेंगे, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। साथ ही यह कोई सीमित कार्यवाही नहीं है, बल्कि एक व्यापक और लंबा चलने वाला रणनीतिक अभियान है।' इजरायल ने 13 जून को 200 लड़ाकू विमानों से ईरान के लगभग 100 ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले 20 प्रमुख सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के घरों पर भी किए गए। ईरान की राजधानी तेहरान में 78 लोग मारे गए। इजरायल की सतर्कता यह रही कि उसने अपने खुफिया संगठन 'मोसाद' के जरिये ईरान के गुप्त ठिकानों पर पहुंचकर कम ऊंचाई वाले ड्रोन छोड़े और ईरान की सुरक्षा प्रणाली एवं मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद इजरायली विमानों को ईरान का खुला आसमान मिल गया। ईरान ने 100 ड्रोन से जवाबी हमला किया भी लेकिन ये सभी ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इजरायल की सीमा लांघने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिए।

डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो कूटनीतिक प्रतिक्रिया आई है, उससे साफ है कि वे दोहरी नीति अपना रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए 60 दिन का समय दिया था, आज 61वां दिन था। फलतः इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया। अब ईरान को समझौता करने के लिए दूसरा मौका दे रहा हूं, वह इस अवसर का लाभ उठाए, क्योंकि इजरायल का दूसरा हमला कहीं ज्यादा आक्रामक और भयावह होगा। साफ है, ट्रंप की सहमति के बाद ही इजरायल ने यह हमला किया है। दरअसल ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये हमला किया गया। इसीलिए इस हमले को नेतन्याहू ने न्यायसंगत ठहराते हुए कहा है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए संकट बन रहा है। क्योंकि यह एक हकीकत है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ऐसी प्रक्रिया है, जो परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। इसके अंतर्गत यूरेनियम-235 के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। अतएव इजरायल के लिए ईरान का परमाणु हथियार संपन्न देश हो जाना चिंता की स्थिति उत्पन्न करने वाली बात है।

परमाणु हथियार संपन्न देश

दरअसल, परमाणु हथियार संपन्न देश होना एक ऐसी सैन्य रणनीति है, जिसके चलते दूसरे देश परमाणु संपन्न देश पर हमला करने से बचते हैं। इसका बुनियादी कारण है कि यदि कोई देश शत्रु देश पर परमाणु हमला करता है तो जवाबी

कार्यवाही में उसे भी परमाणु हमले का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होता है तो देनों देशों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस ने यूक्रेन पर आसानी से इसलिए हमला बोल दिया था, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। रूस और अमेरिका के बहकावे में आकर उसने अपने परमाणु हथियार, परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद समुद्र में नष्ट कर दिए थे। इसका खामियाजा उसे आज उठाना पड़ रहा है। ईरान परमाणु संपन्न देश न बन जाए, इसलिए उस पर अमेरिका ने लंबे समय से परमाणु संबंधी प्रतिबंध लगाए हुए थे। परंतु बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के बीच एक परमाणु समझौता हुआ और ईरान से परमाणु प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए थे। तब भी इजरायल ने इस समझौते का खुला विरोध किया था। नेतन्याहू ने यहां तक कहा था कि यह संधि एक ऐतिहासिक भूल है। किंतु उस समय इस संधि को ओबामा की बड़ी उपलब्धि बताया गया था। ईरान और इजरायल के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन इन देशों ने लंबे समय तक छदम् युद्ध लड़ा है। जब एक अप्रैल 2024 को इजरायल ने सीरिया पर हमला किया था तब ईरान ने इजरायल पर सीधा हमला बोला था। क्योंकि इस लड़ाई में ईरान समर्थित इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ब्रिगेडियर जर्नल मोहम्मद रजा जाहेदी समेत 8 अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इस हमले के जवाब में अप्रत्याशित रुख अपनाते हुए लगभग 320 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल से करीब 1800 किमी की दूरी पर स्थित होने के बावजूद ईरान हमला करने में सफल रहा। ईरान ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद इजरायल से लंबी दुश्मनी के चलते पहली बार यह सैन्य हमला किया था। इस लड़ाई में इजरायल को अमेरिका ने खुली सामरिक मदद की थी। उस संदर्भ में ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि उसने यदि अब इजरायल की मदद की तो नतीजा भुगतने को तैयार रहे। ईरान ने यह पलटवार इसलिए भी किया था, जिससे मध्य-पूर्व की राजनीति में उसके वर्चस्व की महिमा को स्वीकार लिया जाए। यदि वह जवाबी हमला नहीं बोलता तो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसकी जो धारणा है, वह ध्वस्त हो जाएगी। दरअसल ईरान इजरायल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि इजरायल ने मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। हालांकि हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मामले को यहीं समाप्त करने की गुहार भी लगाई थी। बावजूद ईरान ने चेतावनी दी थी कि यदि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यह विरोधाभास भी देखने में आया कि ईरान ने अमेरिका को इजरायल पर सीमित और नियंत्रित हमला करने की जानकारी पहले ही दे दी थी। ईरान के विदेश मंत्री ने ही इस आशय का बयान दिया था। वाकई यह बयान सच था तो यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि अमेरिका दोतरफा कुटिल चालें हमेशा ही चलता रहा है। रूस का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते के लिए जो वार्ता चल रही है, वह उसमें सहयोग करेगा।

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

इस युद्ध को लेकर भारत दुविधा में है, क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब इजरायल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा था। इजरायल भारत का रक्षा साझेदार भी है। दूसरी तरफ ईरान से भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। ईरान ने कई अवसरों पर इस्लामिक देशों के संगठन के मंच पर भारत की मदद की है। इसलिए भारत किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। अतः भारत ने दोनों देशों के बीच कूटनीति व शांति बरतने की अपील की है। बहरहाल, इस युद्ध के साथ बड़ी आशंका यह जुड़ गई है कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर न बढ़ जाए।

बढ़ सकती हैं भारत की कूटनीतिक मुश्किलें

दो टूक
डॉ. एन. के. सोमानी
वरिष्ठ पत्रकार

ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच इसी रविवार को ओमान में वार्ता होनी थी। वार्ता शुरू होती, इससे पहले ही इजरायल ने ईरान पर हमला करके न केवल क्षेत्र में जंग के हालात उत्पन्न कर दिए हैं, बल्कि वार्ता में बड़ा गतिरोध भी पैदा कर दिया है।

समझौता वार्ता से हटा ईरान

इजरायल की आक्रामक कार्रवाई के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर वार्ता से हटने का ऐलान कर दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्षेत्र का राजनीतिक और सैन्य तापमान कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जवाब में ट्रंप ने तल्ख लहजे में कहा कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। ईरान ने भी ट्रंप को कड़े शब्दों में जवाब दिया। रक्षामंत्री अजीज नसीर जादेह ने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में चेता दिया कि यदि हम पर युद्ध थोपा गया तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस तरह की तल्ख टिप्पणियों से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होना ही था। अमेरिका ने खतरे को भांपकर अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने को कह दिया। इराक स्थित दूतावास से भी अपने कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया था। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। हालात बता रहे थे कि अगर ईरान वार्ता के लिए राजी नहीं होता है, तो मध्यपूर्व जंग की चपेट में आ सकता है। ऐसा ही हुआ। इजरायल भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। उसका मानना है कि अगर ईरान परमाणु ताकत हासिल कर लेता है तो उसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। ईरान ने राष्ट्र के रूप में इजरायल के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया है।

इजरायल का यह भी कहना है कि ईरान के परमाणु संपन्न होने से वह पूरे मिडिल ईस्ट को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए ईरान को परमाणु कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह हमला जरूरी था। दूसरी ओर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जूड़े अधिकारियों का दावा है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को हथियार निर्माण के स्तर तक परिष्कृत करके परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इससे पहले ट्रंप भी ईरान को कई बार धमका चुके हैं कि यदि वह समझौते के लिए राजी नहीं होता है तो अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे नष्ट कर देगा। इस बार ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी धमकी पर तल्ख प्रतिक्रिया दी, उसके बाद इजरायल ने ईरान पर धावा बोल दिया। सवाल यह है कि इजरायल-ईरान का यह तनाव कहां तक जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरेशिया (रूस-यूक्रेन युद्ध) के बाद मिडिल ईस्ट भी लम्बी लड़ाई में उलझ जाए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इरादों से तो यही लग रहा है।

नेतन्याहू ने हमले को जायज ठहराते हुए कहा कि हमला इजरायल के अस्तित्व के लिए ईरान के संभावित खतरे को कम करने का एक सैन्य अभियान था। अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है। साफ है कि हमले आगे भी जारी रह सकते हैं।

दूसरी ओर, यदि ईरान लेबनान, सीरिया, इराक या यमन में अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करता है तो निसंदेह मिडिल ईस्ट लंबे समय तक हिंसा की आग में धधकता रहेगा। एक प्रश्न ओर भी है जो दुनिया को डरा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच सीधी जंग शुरू होती है तो दुनिया की सप्लाई चैन का क्या होगा।

वैश्विक व्यापार होगा प्रभावित

ईरान-इजरायल संघर्ष से क्या वैश्विक व्यापार अछूता रहेगा। हमले की स्थिति में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित करने की धमकी दी है। यह दुनिया का एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। यहां से लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन होता है। यदि ईरान शिपिंग लेन या ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई करता है तो तेल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो सकती है। दरअसल, जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित यूएनएससी के पांचों स्थायी सदस्य (फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और चीन) और जर्मनी जिन्हें सामूहिक रूप से पी-5 प्लस वन के रूप में जाना जाता है, के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए इस समझौते को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त व्यापक कार्ययोजना समझौता (जेसीपीओए) के नाम से जाना जाता है। समझौते के अनुसार ईरान ने अरबों डॉलर के प्रतिबंधों को हटाने के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

समझौते का समर्थन करने वाले राष्ट्रों का मानना था कि यह ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर नियंत्रण में मदद करेगा और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों (इजरायल और सउदी अरब) के बीच संघर्ष की संभावनाओं का कम करेगा। शुरू में ऐसा होता हुआ दिखा भी।

यूरेनियम के संवर्धन का अवसर

ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं में कमी आई और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ी। साल 2018 में ट्रंप ने एक तरफा तौर पर समझौते से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ईरान को यूरेनियम के संवर्धन का अवसर मिल गया और जेसीपीओए में तय सीमा को पार कर लिया। यूएन निरीक्षकों ने 2023 में रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने यूरेनियम की मात्रा को लगभग हथियार ग्रेड स्तर तक समृद्ध कर लिया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय चिंताए बढ़ गईं। ईरान फिलहाल 60 प्रतिशत यूरेनियम संवर्धित कर रहा है जो परमाणु हथियार बनाने की हद के बेहद करीब है। भारत के ईरान और इजरायल दोनों के साथ अच्छे संबंध है। भारत ईरान से जो तेल खरीदता है उसका भुगतान वह भारतीय मुद्रा अर्थात रुपये में करता है।

इससे भारत को विदेशी मुद्रा भंडार बचाने और रुपये को मजबूत करने में मदद मिली है। इसके अलावा, भारत ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है। कूटनीतिक दृष्टि से यह पोर्ट भारत के लिए काफी अहम है। इस पोर्ट के विकसित होने के बाद भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से व्यापार के लिए नया मार्ग मिल जाएगा। इससे पहले भारत को मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था। दूसरी ओर इजरायल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायल ने भारत के रुख का खुलकर समर्थन किया था। ऐसे में अगर दोनों के बीच का तनाव किसी बड़े संघर्ष में बदलता है तो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह होगी कि वह पश्चिम एशिया में किसके साथ खड़ा हो। कोई भी निर्णय भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में भारत की कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी ही।

साहित्य

कहानी

सैलाब

■ उपेन्द्रनाथ अश्क

सर ग़रूर बुलंद कर के साहिल ने समुंदर से कहा, मेरी शान ही से तेरी शान है।

समुंदर ने पुर-शोर क़हक़हा लगाया और किनारे को बहा दिया।

पण्डित राधे शाम एक रुजअत-पसंद अख़बार के एडिटर और मालिक थे। उनका ज़मीर इस पज़मुर्दा चिंगारी की तरह था, जो ख़ुशामद और चापलूसी की मनों राख के नीचे दब गई हो। क़ौमी तहारीक से वो दूर भागते थे। तरक़्क़ी-पसंद अंजुमनों की कमज़ोरियों को बे-नक़ाब कर के उन्हें कोसना, उनका रोज़ का मामूल था और उनकी इस ख़िदमत के इवज़ उन्हें सरकारी इश्तिहारात मिलते थे। अगरचे उनके अख़बार की इशाअत चंदाँ हौसला अफ़्ज़ा न थी।

उस वक़्त जब सूबा भर के अख़बारात क़ौमी तहरीक की हिमायत कर रहे थे। नौजवानों की क़ुर्बानियों पर उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे थे। नमक के क़ानून को तोड़ने की तलक़ीन करते हुए उसके पर्दे में वो देर से सोई हुई क़ौमी तहरीक की बेदारी के ख़्वाब देख रहे थे। उनके दिन रात तहरीक की मुख़ालिफ़त करने में सर्फ़ हो रहे थे।

वो तहरीक के ख़िलाफ़ लिखते थे। उसके मुहर्रिकों का मज़ाक़ उड़ाते थे और कहते थे, 'क़ौम की ताक़त और वक़्त एक निहायत फ़ुज़ूल और बेमानी तहरीक के लिए सर्फ़ किए जा रहे हैं। मुल्क में बीसियों क़िस्म के टैक्स वसूल किए जाते हैं। नमक का टैक्स कोई बड़ा भारी टैक्स नहीं। अगर उसे मंसूख़ भी कर दिया गया तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। साठ हज़ार! सिर्फ़ साठ हज़ार, हालाँकि लाखों रुपया ऐश-ओ-इशरत में सर्फ़ हो रहा है।'

लेकिन जब उन्हें कोई बताता कि नमक के टैक्स का बार मुफ़लिस लोगों पर ज़्यादा पड़ता है और ग़रीबों के लिए साठ हज़ार रुपया साठ लाख के बराबर है तो वो एक फीकी हंसी हंसकर बे-ज़ारी से सर हिला देते।

वो सिर्फ़ नमक की तहरीक के ख़िलाफ़ हों, ये बात न थी। वो हर तरक़्क़ी पसंद तहरीक के ख़िलाफ़ थे। वो उन क़दामत पसंद लोगों में से थे जो ब्रिटिश राज को हिन्दोस्तान के लिए रहमत तसव्वुर करते हैं और सोचा करते हैं कि अगर ये राज न रहा तो हिन्दोस्तान में फिर अबतरी का दौर दौरा हो जाएगा।

सूबा भर के अख़बार और रिसाले उनका मज़ाक़ उड़ाया करते। अपने ग़पशप के कालमों में उस पर फब्तियां कसा करते। अंग्रेज़ी दानों में वो यस मैन और उर्दू वालों में 'जी हुज़ूरिये' के नाम से मशहूर थे। लेकिन उन्हें इस बात की शर्म न थी। बल्कि सरकार की ख़ुशनुदी हासिल करने में, इश्तिहारात लेने में, उनके हमअसरों के दिए हुए यही ख़िताबात उनके काम आते थे और सितम ज़रीफ़ी ये कि उनके अख़बार का नाम 'रहबर' था।

कांग्रेस की तरफ़ से शहर में नमक के क़ानून को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। एक अज़ीमुश्शान जलूस की तैयारियां हो रही थीं। प्रोग्राम मुरत्तिब हो चुका था। इतवार का दिन था और अख़बारों में चूँकि छुट्टी थी। इस लिए हर अख़बार ने अपने ज़मीमे निकालने का इंतिज़ाम कर रखा था और लोग बड़ी बेताबी से उनका इंतिज़ार कर रहे थे। ताकि सही प्रोग्राम से रुशनास हो सकें। कमला भी घर के काम काज से फ़ारिग़ हो कर अख़बार की मुंतज़िर थी।

वो पण्डित राधे शाम की आज़ाद ख़याल बीवी थी। वो उसे हमेशा 'रहबर' ही पढ़ने के लिए देते थे। वो दफ़्तर में चाहे कितने अख़बार मँगाएं। लेकिन घर उनमें से एक को भी न जाने देते थे और कमला हमेशा चाहा करती थी कि वो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखे, अपनी सहेलियों से जो वो सुनती थी, अगरचे उसका एक लफ़्ज़ भी अपने ख़ावंद के सामने ज़बान से न निकलने देती थी। लेकिन वो चाहती थी कि उसके ख़ावंद ये सब चापलूसी छोड़ दें। ख़ुशामद की सारी से ख़ुद्दारी की आधी भली, लेकिन अपने ख़ावंद के मुँह पर उसने कभी कुछ भी न कहा था।

चपरासी आकर 'रहबर' का ज़मीमा फेंक गया। इस दो वर्क़ के अख़बार में भी उन्होंने इस तहरीक के ख़िलाफ़ एक छोटा सा लीड लिख रखा था। रंज और ग़ुस्सा के मारे कमला ने अख़बार के पुर्ज़े पुर्ज़े कर दिए और उन्हें कोने में फेंक कर कोच में धँस गई। तभी उसके ख़ावंद, 'रहबर' के क़दामत पसंद एडिटर श्री राधे शाम कमरे में दाख़िल हुए। फटे हुए अख़बार के पुर्ज़ों को देखकर उन्होंने ज़रा तीखे लहजे में कहा, 'ये क्या बेहूदगी है?'

कमला चप कोच पर बैठी थी।

उन्होंने फिर गरज कर कहा, 'ये क्या बेहूदगी है।'

कमला अब के भी चुप रही, उसने सिर्फ़ एक-बार अपने ख़ावंद की तरफ़ आँख उठा कर देखा।

बरस ही पड़ने को तैयार बादल की तरह उसकी आँखें भरी हुई थीं।

राधे शाम आहिस्ता से उसके पास कोच पर बैठ गए। उन्होंने कहा, 'देख कमला, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये सब झगड़ा बिल्कुल नापसंद है, बाहर ही मेरी कम मुख़ालिफ़त नहीं होती जो घर में इस की ज़रूरत बाक़ी रह जाये।'

'आप मुख़ालिफ़त की वजह क्यों पैदा करते हैं।'

पण्डित राधे शाम ने फिर जोश से कहा, 'मैं हर फ़ुज़ूल तहरीक की तक़लीद नहीं कर सकता। मैं न आम लोगों की तरह दिमाग़ से आरी हूँ कि जो कोई कहे उसे मान कर अंधा धुंद उसकी तक़लीद करूँ, न मैं बेकार हूँ कि कुछ करते रहने के लिए हर तहरीक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। और न मुझे शोहरत की तमन्ना है कि अवाम को ग़लत रास्ते पर लगा कर अपनी लीडरी क़ायम रखूं।'

कमला ने चीख़ कर कहा, 'आप देश का कुछ फ़ायदा नहीं कर सकते तो देश भगतों को गालियां तो न दें। अपनी ख़ुदग़रज़ी को छुपाने के लिए कोई दूसरा बहाना आपके पास नहीं क्या?'

और दामन में मुँह छुपा कर वो रोने लगी।

राधे शाम हँसे, 'ख़ुदग़रज़ी!' ज़ेर-ए-लब उन्होंने कहा और फिर बोले, 'सादा-लौह अवाम को छोड़कर कौन ग़रज़मंद नहीं। सब अपनी अपनी ग़रज़ के लिए तहरीकों का फ़ायदा उठाते हैं। किसी को इज़्ज़त की तमन्ना है, किसी को शोहरत की। किसी को काम की ख़्वाहिश है किसी को नाम की, मुझे उनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर मैं क्यों मुफ़्त में अवाम को धोका दूं, जो मुनासिब समझता हूँ लिखता हूँ।'

कमला अब कुछ भी न कहना चाहती थी लेकिन रुक न सकी। उसने कहा, 'यूं क्यों नहीं कहते कि ऐश-ओ-आराम आपको इतना प्यारा है। ये बड़े बड़े कमरे, ये कुर्सियाँ-मेज़, ये काउच, ये क़ीमती कपड़े और ये सब ऐश-ओ-आराम के सामान आपको इतने अज़ीज़ हैं कि इसकी ख़ातिर आप अपने ज़मीर को फ़रोख़्त कर सकते हैं।'

'तो क्या मैं अकेला ही इन सबको इस्तिमाल करता हूँ, क्या तुम्हारे आराम के लिए मैं ये सब नहीं करता।' उन्होंने गरज कर कहा।

'मुझे इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं।' और वो उठकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ लम्हा तक मब्हूत से राधे शाम वहीं बैठे रहे। फिर वो हँसे और ज़ेर-ए-लब उन्होंने कहा, 'बेवक़ूफ़! और फिर...औरत!' और बेज़ारी से सर हिला कर वो उठे और बाहर चले गए।

'क़ानून नमक को...तोड़ दो!'
'क़ानून नमक को...तोड़ दो!'
'क़ानून नमक को...तोड़दो!'

और फिर, 'लंगोटी वाले की जय और बंदे मातरम।'

पण्डित राधे शाम बाज़ार के एक कोने में खड़े जलूस देख रहे थे। जैसे-जैसे जलूस गुज़रता जाता लोग दूकानों से उठकर, काम छोड़कर उसके साथ शामिल होते जाते। मर्दों-औरतों का एक बेपनाह हुजूम था। एक समुंदर था कि बहता बहाता चला जा रहा था।

सबसे आगे 'बाल भारत सभा' के लड़के थे। मासूमियत के नन्हे अवतार, छोटे छोटे झंडे लिये। 'क़ानून नमक...तोड़ दो।' के नारे लगाते जा रहे थे। उनके चेहरे जोश की वजह से सुर्ख़ हो रहे थे और उन पर एक जलाल बरस रहा था। थकावट की उन्हें परवा न थी। धूल की या धूप की उन्हें फ़िक्र न थी। बस एक ही धुन थी कि जब उनका 'नायक' ऊंची आवाज़ में कहे, 'क़ानून नमक' तो वो उछल कर झंडियां हिला कर उस से भी ऊंची आवाज़ में नारा लगाएं, 'तोड़ दो।'

वहीं खड़े खड़े राधे शाम ने महसूस किया। जैसे उनका भी दिल एक मासूम बच्चे के क़ालिब में चला गया है और वो उन बच्चों के साथ इस अफ़्सानी समुंदर में लहरों सा बहा जा रहा है, तभी वो चौंक पड़े।

एक टोली के आगे आगे एक शख़्स बेतरह उछल रहा था। चेहरा जोश से सुर्ख़ था। सर के बालों की, क़मीज़ के गिरेबान या आस्तीनों की, उसे कुछ भी चिंता न थी। जुनूनियों की तरह वो उछल कर और बार-बार वो सामने ख़ला में इशारा कर के कहता था, 'ओह की आया?' और सारी की सारी टोली चिल्ला उठती। 'इन्क़िलाब' और ये शख़्स शहर का मशहूर वकील था। एम.ए, एल.एलबी.।

पंडित जी के सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उनके रौंगटे खड़े हो गए और वो दूर तक उसे देखते रहे। उछल उछल कर यही नारा लगाते देखते रहे।

जब वो चौंके तो फ़िज़ा में लेडी वालंटियरों का गीत गूंज रहा था और बाज़ारों की छतों पर बैठी हुई औरतें उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला कर गाने लगी थीं:

'असीं चीन लवांगे
क़ानून नमक नूं तोड़ के। असीं चीन...'

पंडित जी की आँखें खुली की खुली रह गईं। सबसे आगे आगे, हाथ में क़ौमी झंडा उठाए कमला, उनकी अपनी बीवी गा रही थी। 'असीं चीन लवांगे' और सब उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला कर गा रही थीं, 'क़ानून नमक नूं तोड़ के।'

ख़्वातीन का जुलूस गुज़र गया। उसके बाद शहर के सरकरदा लीडर नमक बनाने का सामान उठाए चले आ रहे थे। छतों से और दूकानों से उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। उनके चेहरे मामूल से दुगुने मालूम होते थे।

और उनके बाद हज़ारों का हुजूम जैसे बहता हुआ चला जा रहा था। पंडित जी अपनी जगह से उतरे और हुजूम में शामिल हो गए।

तभी किसी ने ज़ोर से नारा लगाया,
'क़ानून नमक को'
सब बोले
'तोड़ दो।'

हुजूम की इस आवाज़ में पण्डित राधे शाम की आवाज़ भी शामिल थी लेकिन ये आवाज़ मुख़्तलिफ़ नहीं थी। अपने भाईयों की आवाज़ से हम-आहंग...एक आवाज़।

ग़ज़ल

■ शेख़ इब्राहीम ज़ौक़

लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले
अपनी ख़ुशी न आए न अपनी ख़ुशी चले

हो उम्र-ए-ख़िज़्र भी तो हो मालूम वक़्त-ए-मर्ग
हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले

हम से भी इस बिसात पे कम होंगे बद-क़िमार
जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले

बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे
पर क्या करें जो काम न बे-दिल-लगी चले

लैला का नाक़ा दश्त में तासीर-ए-इश्क़ से
सुन कर फ़ुग़ान-ए-क़ैस बजा-ए-हुदी चले

नाज़ाँ न हो ख़िरद पे जो होना है हो वही
दानिश तिरी न कुछ मिरी दानिश-वरी चले

दुनिया ने किस का राह-ए-फ़ना में दिया है साथ
तुम भी चले चलो यूँही जब तक चली चले

जाते हवा-ए-शौक़ में हैं इस चमन से 'ज़ौक़'
अपनी बला से बाद-ए-सबा अब कभी चले

अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएँगे
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएँगे

तुम ने ठहराई अगर ग़ैर के घर जाने की
तो इरादे यहाँ कुछ और ठहर जाएँगे

ख़ाली ऐ चारागरो होंगे बहुत मरहम-दाँ
पर मिरे ज़ख़्म नहीं ऐसे कि भर जाएँगे

पहुँचेंगे रहगुज़र-ए-यार तलक क्यूँ कर हम
पहले जब तक न दो आलम से गुज़र जाएँगे

शोला-ए-आह को बिजली की तरह चमकाऊँ
पर मुझे डर है कि वो देख के डर जाएँगे

हम नहीं वो जो करें ख़ून का दावा तुझ पर
बल्कि पूछेगा ख़ुदा भी तो मुकर जाएँगे

आग दोज़ख़ की भी हो जाएगी पानी पानी
जब ये आसी अरक़-ए-शर्म से तर जाएँगे

नहीं पाएगा निशाँ कोई हमारा हरगिज़
हम जहाँ से रविश-ए-तीर-ए-नज़र जाएँगे

सामने चश्म-ए-गुहर-बार के कह दो दरिया
चढ़ के गर आए तो नज़रों से उतर जाएँगे

लाए जो मस्त हैं तुर्बत पे गुलाबी आँखें
और अगर कुछ नहीं दो फूल तो धर जाएँगे

रुख़-ए-रौशन से नक़ाब अपने उलट देखो तुम
मेहर-ओ-मह नज़रों से यारों की उतर जाएँगे

हम भी देखेंगे कोई अहल-ए-नज़र है कि नहीं
याँ से जब हम रविश-ए-तीर-ए-नज़र जाएँगे

'ज़ौक़' जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला
उन को मय-ख़ाने में ले आओ सँवर जाएँगे

देशभक्ति का रास्ता पेट से होकर जाता है

■ संजय चावला

देशभक्ति के इस नवयुग में सब कुछ बदल रहा है — नारे, नज़ारे, यहाँ तक कि नाश्ते भी। अब केवल दिल से नहीं, देशभक्ति का रास्ता सीधा पेट से होकर जाता है। जयपुर के त्यौहार स्वीट्स के मालिक जैन साहब को ही देख लीजिए। हाल ही में हुए ओपरेशन सिन्दूर के बाद उनमें ऐसी देशभक्त भावना जागी कि उन्होंने अपनी दुकान की प्रसिद्ध मिठाइयों — मोतीपाक और मैसूरपाक — के नामों से 'पाक' शब्द को निकाल फेंका। अब वे गर्व से मोतीश्री और मैसूरश्री नाम से बिक रही हैं। मालिक जैन साहब का मक़सद निस्संदेह देशी घी की तरह शुद्ध है। लेकिन अफ़सोस, देशभक्ति की आँधी में वे भूल गए कि शब्दों के भी अर्थ होते हैं। अब अगर किसी शब्द की ध्वनि किसी दूसरे देश से मिलती-जुलती हो तो क्या हम उसे देशनिकाला दे देंगे? मैसूरपाक का 'पाक' कोई सीमा पार की साज़िश नहीं है। यह एक कन्नड़ शब्द है — जिसका अर्थ होता है 'पकाने की प्रक्रिया'। यह तो उस चाशनी का भी नाम है जो धीरे-धीरे उबलती है और मिठास बिखेरती है — जैसे कभी भारत की संस्कृति बिखरा करती थी। 19वीं सदी में मैसूर की शाही रसोई में काकासुर नामक बावर्ची ने इसका आविष्कार किया था। अब स्वर्ग में बैठा वह बेचारा सोच रहा होगा — 'मैंने मिठाई बनाई थी या राष्ट्रद्रोह?'

बहरहाल, नाम बदलने का यह राष्ट्रव्यापी अभियान नया नहीं है।

इतिहास गवाह है कि जब भावनाएँ उबलती हैं, तो सबसे पहले कढ़ाई में पकते हैं व्यंजन। अमेरिका में 9/11 के बाद एक सांसद ने फ्रेंच फ्राईस का नाम बदलकर फ्रीडम फ्राईस रख दिया था। वजह? फ्रांस ने इराक युद्ध का समर्थन नहीं किया था। अब ये कोई नहीं बताता कि फ्रेंच फ्राइज़ दरअसल बेल्जियम की उपज थीं — और उन्हें 'फ्रेंच' तो अमेरिकियों ने ही कहा था। यही हाल कैनाडा में हुआ, जब ट्रम्प ने वहाँ के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया। कुछ कैफे वालों ने अमेरिकानो कॉफी को कनाड़ानो कर दिया — भले ही वो कॉफी बीन्स न अमेरिका से आई थी, न कैनाडा से। तुर्की और ग्रीस ने भी 1974 के युद्ध में इसी तरह से मोर्चा खोला — टर्किश कॉफ़ी ग्रीस में ग्रीक कॉफ़ी बन गई। यह सब दर्शाता है कि जब तोप न चले, तो चम्मच चला दीजिए।

भारत में तो अब हर चाय, हर चटनी, हर चाशनी पर राष्ट्रध्वज लहराने की होड़ लगी है। हैदराबाद की कराची बेकरी को तो यह सफाई देनी पड़ी कि 'हमारा नाम चाहे जो हो, हमारे बिस्कुट पूरी तरह भारतीय हैं।' ये अलग बात है कि उनके मालिक विभाजन के बाद भारत आए थे। और अब सवाल उठता है — क्या हम पाकशास्त्र को भी श्रीशास्त्र कहेंगे? क्या पाकशाला को श्रीशाला? और पाकस्थली — यानी हमारा पेट — उसका क्या होगा? उसे भी किसी सरकारी योजना का नाम देना पड़ेगा क्या? पेटश्री योजना – 'जहाँ भी भोजन पचे, वहीं तिरंगा लहराए!'

इस देश में भोजन कभी केवल भोजन नहीं रहा। यह एक सामाजिक घोषणा रहा है — कि आप कौन हैं, किस ओर हैं, और किस थाली में खा रहे हैं। खाने पर प्रतिबंध, भोजन के नामों का संकीर्णकरण — यह सब केवल पेट की बात नहीं, पहचान की लड़ाई बन चुकी है।

कितनी विडम्बना है कि हम भूल रहे हैं — भोजन वह कला है जो जोड़ती है, बाँटती नहीं। कोई मिठाई किसी मुल्क की नहीं होती — वो उस स्वाद की होती है जिसे साझा किया जा सके। मैसूरपाक में न पाकिस्तान है, न कोई राजनीतिक षड्यंत्र — उसमें है तो बस बेसन, घी, और वो मीठा भाव जो हर त्योहार में बँटता है। मगर इस देश में आजकल भाव से ज़्यादा ब्रांड चलता है। शायद इसी लिए अब मिठाई भी प्रधानमंत्री श्री मिष्ठान योजना के तहत आएगी। और स्वाद से ज़्यादा मायने रखेगा नाम। इसलिए अगली बार जब आप किसी मिठाई का टुकड़ा मुँह में रखें, तो सोचिए — यह आपके स्वाद का सवाल नहीं, राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान है। क्योंकि भाई साहब, इस दौर में 'पेट' नहीं, 'पाक' ज्यादा संवेदनशील है।

कविता

अंडमान

■ शशांक शेखर

आदमी कितना निरर्थक जीव है
और आदमी के भी तो यहाँ
पितामह पुरुष हैं
इतने पुराने मानव , ये आदिवासी
क्या है इसने पुराना हमारा पास ?
जिसे संजो लिया जाए
कौन सा ग्रंथ कौन से ईश्वर हमारे
इनसे पुराने हैं ?
मिस्त्र के पिरामिड भी तो धूप सेक रहे
क्या इन आदिवासियों के
धूप से सिके हुए बदन से पुराने हैं ?

हम चले समुद्र के किनारे रोज़
और चल चलकर थके भी
फिर यहीं लेटकर आराम फ़रमा भी हुए
सच समुद्र के पास दवा है थकाने
और राहत देने की भी
मैं जब अपने समुद्री जहाज़ से
झाँककर बाहर देखता
उस वक्त जब हम टापुओं की सैर पर थे
मुझे लगता आखि़र हम कौनसे
कर्तव्य-पथ पर हैं
हम किस राह के पथिक हैं और क्या ही
योगदान है हमारा
लेश मात्र भी इनके जीवन में
मसलन हम ना रहें तो
इन टापुओं के जीवन पर क्या असर होगा
एक हरी चादर ओढ़े ये टापू
बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे रहते हैं
इंतज़ार में कि पानी पर सरकता
कोई जहाज़
उनसे आलिंगन करे ,
पर हम हर जगह रुकते नहीं
हम इनके बगल से
आहिस्ता से निकल जाते हैं
ना हम उनके ना वो हमारे नाम जानते हैं
मुझे याद है
जब मैंने देखा समुद्र की विराटता
और जिसका ना ओर नज़र आया
था ना छोर
कुछ था मेरे भीतर
जो पिघलना शुरू हुआ था
बहुत छोटा दुनियावी आदमी ही तो हूँ मैं
और ये समुद्र देवता है पुराणों का
और पुराणों से भी पुरानी
सभ्यता रच बस रही है यहाँ
कौन किससे पुराना है?
क्या पुरातन होना ही
सार्थकता का पैमाना है?
मैंने देखा जहाज़ में बैठे हुए समुद्र में
कहानियाँ, सभ्यता ,पुराण वेद, देवता,
मानव , जीव जंतु
सब विलीन हो रहे थे
दूर साहिल पर नज़र पड़ी अचानक
तो सूरज शाम के आगोश में
डूबने की तैयारी कर रहा था ।

■ (पेशे से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड।)

लघुकथा

इंजेक्शन

■ अरुण अर्णव खरे

रघु फिर साप्ताहिक हाट से निराश लौटा था। उसे जितनी उम्मीद थी, उससे बहुत कम दाम में सब्जियां बिकी थीं। हाट से लौटकर चुपचाप चारपाई पर लेट गया। फिर पत्नी से बोला– 'बड़ी मुश्किल से लागत निकल रही है। मेहनत का कोई मोल ही नहीं जैसे।'

'ननकू को तो बहुत फायदा हो रहा है, कल ही उसने शरबती को पायलें लाकर दी हैं', परबतिया ने उत्सुकता से रघु की ओर देखा।

'ननकू शहर से कोई इंजेक्शन लाया है जिसे लगाने से सब्जियों का वजन ढाई–तीन गुना बढ़ जाता है, इसलिए उसे मुनाफा हो रहा है।'

'आप भी ननकू से पूछकर दवा ले आओ बाजार सेज नहीं तो शहर जाके ठोकरें खानी पड़ेंगी', चिंतातुर परबतिया बोली।

पास बैठा पांच साल का बच्चा पंचम अचानक बोल पड़ा– 'बापू, माई सही बोल रही है, शहर से दो इंजेक्शन ले आना। एक सब्जी को लगाना और दूसरा मुझे, ताकि मैं जल्दी से बड़ा होकर आपका काम कर सकूं।'

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPapersPaid

सरकार के ग्यारह साल : लेखा-जोखा

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11 साल पूरे किए हैं, जिससे वे देश के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उनकी दृढ़ता और अपनी पार्टी के लिए चुनाव जीतने की क्षमता का प्रमाण है। हर सरकार में अच्छाइयां व खामियां होती हैं और राजग सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। मौजूदा सरकार मापदंडों पर निर्भर करती है।

कोई एक दृष्टिकोण कभी पूरी तरह सही नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत पर कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए थे, जिनमें प्रमुख वैज्ञानिक जयंत नारलीकर भी शामिल थे। जब तक कोई दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य न हो, हर दृष्टिकोण में कुछ सच्चाई होती है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए- यह गुण वर्तमान सरकार पिछले 11 वर्षों में विकसित नहीं कर पाई है।

नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11 साल पूरे किए हैं, जिससे वे देश के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उनकी दृढ़ता और अपनी पार्टी के लिए चुनाव जीतने की क्षमता का प्रमाण है।

हर सरकार में अच्छाइयां व खामियां होती हैं और राजग सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। मोदी की सरकार मापदंडों पर निर्भर करती है : एक विकासशील देश में सामान्य आर्थिक मापनीय आंकड़े केवल मात्रात्मक वृद्धि को दिखा सकते हैं। यदि स्कूल बनाए जाते हैं या सड़कें निर्मित की जाती हैं, तो स्कूल (संख्या में) या सड़कें (किलोमीटर में) मात्रात्मक रूप से बढ़ जाती हैं। हालांकि, सरकार के काम का आकलन करने के लिए लोगों के मानक अलग हैं, जो मात्रा पर आधारित नहीं होते और उसे 'सुशासन' कहा जाता है।

सुशासन उसे माना जाता है, जब देश में सभी के लिए बेहतर, मजबूत और न्यायसंगत व्यवस्था हो और व्यक्ति को यह संतुष्टि हो कि उसके परिवार का भविष्य और बेहतर होगा। मात्रात्मक आंकड़ों से शासन की गुणवत्ता का पूर्ण आकलन नहीं किया जा सकता। मेरे आकलन में, आज भारत वर्ष 2014 की तुलना में न तो सभी के लिए बेहतर, न ही अधिक मजबूत और न ही अधिक न्यायसंगत है। हालांकि, लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, पर लाखों और लोगों का जीवन अभी भी अनिश्चितता, गरीबी, बेरोजगारी और भय से प्रभावित है।

क्या भारत सभी के लिए बेहतर है

आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरुआत इस उद्देश्य से हुई थी कि भारत के विकास दर को बढ़ाया जाए। यूपीए के 10 वर्षों (2004-2014) में औसत जीडीपी वृद्धि दर 7.46 फीसद (पुरानी शृंखला) और 6.7 फीसद (नई शृंखला) थी। 2014-15 के बाद, विशेष रूप से 2019-20 के बाद, आधिकारिक आंकड़ों से वृद्धि दर के धीमे होने का पता चलता है। 2024-25 में भी केवल मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 के बाद से वास्तविक जीडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 6.1 फीसद रही और 2019-20 के बाद यह घटकर 5.1 फीसद हो गई। कृषि, उद्योग और विनिर्माण की दर में कमी दर्ज की गई है और ये सभी पांच फीसद से नीचे हैं। केवल सेवा क्षेत्र 5.4 फीसद की दर से बढ़ा है।

देश की विशाल जनसंख्या के बेहतर जीवन की कुंजी है प्रति व्यक्ति आय, न कि केवल कुल जीडीपी का आकार। यूपीए सरकार के दौरान प्रति व्यक्ति आय 10 वर्षों में दोगुना से अधिक बढ़ी, जो वास्तव में 2.64 गुना थी यानी 543 अमेरिकी डालर से 1438 डालर तक की वृद्धि हुई। जबकि, राजग सरकार के पहले 10 वर्षों में यह केवल 1.89 गुना बढ़ी यानी 1438 डालर से 2711 डालर तक और 11वें वर्ष में ही यह 2878 डालर तक दोगुनी हो पाई। इस लिहाज से भारत 196 देशों में 136वें स्थान पर है। भारत 20 वर्षों तक आठ फीसद की सतत विकास दर के लक्ष्य से काफी पीछे रह गया है, जो एक विकसित देश (प्रति व्यक्ति आय 14,000 डालर) बनने के लिए आवश्यक है।

क्या भारत न्यायसंगत देश बन पाया है

धनी और अति-धनी (शीर्ष 20%) तथा बहुत गरीब (निचले 20%) वर्गों के बीच बढ़ती असमानता के अलावा, भय और असुरक्षा की भावना व्यापक है। इसके अतिरिक्त, बहुसंख्यकवाद, सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष, नफरती भाषण व लेखन, खुली साठगांठ वाला पूंजीवाद, आपराधिक न्याय प्रणाली का पतन, संघीय ढांचे में गहरी दरारें और धीरे-धीरे बढ़ता अधिनायकवाद, इन सबके भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। दो उदाहरण पर्याप्त होंगे: एक- आयकर अधिनियम से लेकर धनशोधन रोकथाम अधिनियम तक के कानूनों का राजनीतिक लक्ष्यों के लिए हथियार की तरह प्रयोग। दो- अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना पर 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च करना, जबकि धन की भारी कमी से जूझ रही मुंबई की उपनगरीय रेल सेवाओं में 2014 से 2025 के बीच 29,970 लोग मारे गए और 30,214 घायल हुए।

क्या भारत अधिक मजबूत देश बना है

'मजबूत' का अर्थ मैं एकता, पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत व सहयोगात्मक संबंध, सुरक्षित सीमाएं, सक्षम सशस्त्र बल, विभिन्न देशों के साथ सौहार्दपूर्ण राजनयिक व व्यापारिक संबंध और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सम्मानजनक स्थिति से लेता हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और आपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कमजोरियां उजागर हुईं। न तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों (श्रीलंका, म्यांमा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव या मारीशस) में प्रतिनिधिमंडल भेजा, न ही इन देशों ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया। कई देशों ने आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को आतंक का प्रायोजक नहीं कहा। पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की बढ़त पर भी संदेह पैदा हुआ है।

अमेरिका ने क्वाड और आधारभूत समझौतों के बावजूद भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाए और भारत-पाकिस्तान को एक ही श्रेणी में रख दिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड और विश्व बैंक के निदेशक मंडल के 25 सदस्यों में से एक भारत के होने के बावजूद, दोनों निकायों ने आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बड़े ऋण की मंजूरी दी। भारत ने पाकिस्तान से चार दिवसीय संघर्ष मुख्य रूप से फ्रांस, रूस और इजरायली सैन्य साजोसामान से लड़ा। भारत मजबूत हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना हमने सोचा था।

देश की सारी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में केंद्रित है। सरकार की उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दिया जा सकता है तो असफलताओं की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। जब मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं भारतीय होने पर गर्व करता हूं? तो मेरा उत्तर है, हां। लेकिन जब मैं पूछता हूं, क्या मैं देश की शासन-प्रणाली से खुश हूं? तो मेरा उत्तर है, नहीं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं, जब भारत सभी के लिए एक बेहतर, अधिक मजबूत और न्यायसंगत देश बनेगा।

गरीबी की परतें

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> मुंबई के मरीन ड्राइव पर ही अति-गरीब मिलते हैं, तो यकीन करना मुश्किल है कि गरीबी देश में इतनी कम हो गई है। नापने वाले कौन हैं? और कैसे तय करते हैं कि गरीबी कितनी कम हुई है? गड़बड़ इसलिए भी लगती है कि 80 फीसद भारतीयों को जरूरत है मुफ्त राशन की और जब सरकारें खैरात बांटने की कोई नई योजना बनाती है, तो क्यों लंबी कतारें लग जाती हैं गरीबों की।

इत्तेफाक से जिस दिन अखबारों की सुर्खियों से मालूम पड़ा पिछले सप्ताह कि भारत में गरीबी इतनी कम हो गई है कि गरीबी रेखा के नीचे बहुत थोड़े लोग रह गए हैं। मुझे मरीन ड्राइव पर एक बच्ची मिली, इतनी छोटी और पतली थी कि जब उसने बताया कि उसकी उमर 12 साल है, तो यकीन करना मुश्किल था। उसके पांव नंगे थे और उसका गुलाबी रंग का कुर्ता-पजामा इतना मैला कि ऐसा लगा जैसे उसके पास कपड़ों का दूसरा जोड़ा न हो। हमसे उसने बातें इस उम्मीद से शुरू कीं कि शायद हम उसके लिए कुछ कपड़े और खरीद दें।

मैंने जब उससे पूछा कि वह मुंबई आई कहां से थी, तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले सोलापुर से आई थी मुंबई में 'कुछ पैसे कमाने'। इतनी दूर अकेली आई कैसे, मैंने पूछा, और टिकट के पैसे किसने दिए, तो उसने कहा, 'हम टिकट तो लेते नहीं हैं, बस आ जाते हैं'। कुछ और सवाल पूछे मैंने, तो पता लगा कि यह बच्ची फुटपाथ पर रातें गुजारती है उन लोगों के साथ जिनको मैं उनके बचपन से जानती हूं। कोई 15-20 साल पहले मैंने मरीन ड्राइव पर 'नाश्ता' नाम का कार्यक्रम शुरू किया था उन लावारिस बच्चों के लिए जिनकी सारी जिंदगी फुटपाथों पर गुजरती है।

इन बच्चों में से मेरी खास दोस्ती हुई सुरेखा और रूपा नाम की बच्चियों के साथ जो अब बड़ी हो गई हैं और जिनके अपने बच्चे भी अब फुटपाथ पर जीवन बिताते हैं। इनमें से कुछ बच्चों को मैंने एक निजी बाल आश्रम में डाल दिया था, जो एक पारसी संस्था चलाती है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर हैं, जिनको नौकरियां मिल जाती हैं इस महानगर में। अक्सर फुटपाथ पर ही उनका जीवन बीतता है। थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है फूल, खिलौने और चूड़ियां बेच कर। जो थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना सीख जाते हैं, उनके लिए भी नौकरी मिलना मुश्किल है। इसलिए कि फुटपाथ पर रहने वालों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर ही अति-गरीब मिलते हैं, तो यकीन करना मुश्किल है कि गरीबी देश में इतनी कम हो गई है। नापने वाले कौन हैं? और कैसे तय करते हैं कि गरीबी कितनी कम हुई है? कुछ गड़बड़ इसलिए भी लगती है कि 80 फीसद भारतीयों को जरूरत है मुफ्त राशन की और जब भी सरकारें खैरात बांटने की कोई नई योजना बनाती है तो क्यों लंबी कतारें लग जाती हैं गरीबों की। महाराष्ट्र चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीता कुछ महीने पहले, तो मेरी राय में सिर्फ उस लाडली बहना योजना के वास्ते। इसके जरिए गरीब औरतों को पंद्रह सौ रुपए मिलते हैं हर महीने। ऊपर से यह भी याद रखिए कि अनुमान लगाया जाता है कि भारत के तकरीबन 90 फीसद लोगों का आवास है एक कमरा, जिसमें पूरा परिवार रहता है। यह गरीबी नहीं तो क्या है?

रही बात देहातों की, तो हाल यह है कि मनरेगा से पैसा लेने के लिए करोड़ों लोग अपना नाम दर्ज करते हैं। ऐसा क्यों? कोविड के दौर में तो यह योजना न होती, तो शायद करोड़ों बेरोजगार लोग भूख से मरते। पिछले सप्ताह शायद आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि बिहार के एक गांव में पांच छोटे बच्चों को निर्वस्त्र कर रस्सियों से बांध कर गलियों में घुमाया एक दुकानदार ने, सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों ने उसकी दुकान से चाकलेट चुराए थे। यह गरीबी नहीं तो क्या है? महाराष्ट्र में जिस गांव से मेरा आना-जाना रहा है पिछले बीस बरसों से, वह आदिवासियों की एक बस्ती है, जिसमें टूटे-फूटे कचरे से बनी झुग्गियों में ऐसे लोग रहते हैं जो शायद जिंदा न होते, अगर उनको हर महीने मुफ्त राशन न मिलता सरकार से। यह समुंदर किनारे गांव है, जहां मुंबई के धनवानों ने अपने लिए आलीशान कोठियां बनाई हैं समुंदर की हवाओं का मजा लेने के लिए। कहना यह चाहती हूं मैं कि गरीबी नापने वाले विद्वान शायद जमीनी यथार्थ से बहुत दूर हैं। उनके आंकड़े बनते हैं ऊंचे सरकारी दफ्तरों में जहां गरीबी की बदबू तक नहीं आती है।

मैंने अपने जीवन में अति-गरीब लोग तब ही देखे, जब पत्रकार बनी। याद है मुझे कि ओड़ीशा के कालाहांडी में जब भुखमरी फैली थी, तो मुझे ऐसे बच्चे दिखे जिन्होंने महीनों से सिर्फ परिंदों का दाना खाया था। अनाज था ही नहीं। ये गांव निर्भर थे बरसात पर और उस साल बरसात जब नहीं हुई, तो बच्चे भूख से मरने लग गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी संवेदनहीन थी उस समय की कांग्रेस सरकार कि जब बच्चे मरने लगे, तो खिचड़ी बांटने के लिए लंगर खुला कालाहांडी शहर में, लेकिन खाना परोसा जाता था सिर्फ उन बच्चों को जो पांच साल से छोटे थे।

सच यह है कि हमारे शासक अभी तक समझे नहीं हैं कि गरीबी हटाने के असली जरिए क्या हैं। बड़ी-बड़ी योजनाओं के बदले अगर हर गांव में 'अक्षय पात्र' जैसी संस्थाओं को लंगर खोलने की इजाजत दी जाती है, तो बच्चे कम से कम भूखे नहीं सोते रात को। स्कूल अच्छे बनते देहातों में, तो पढ़-लिख कर बच्चे अच्छी नौकरियां हासिल करने के लायक होते। स्वच्छ पानी मिलता नलों में, तो बीमार न पड़ते और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होतीं और हर गांव में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अमीर, विकसित देशों में जरूरतमंदों के लिए खाना रोज बांटा जाता है गिरजाघरों से। भारत में सिर्फ गुरुद्वारे हैं जहां गरीब, बेघर लोगों को रहने-खाने के लिए जगह मिलती है। ये सुविधाएं हमारे हर मंदिर में क्यों नहीं मिलती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। उधर, हमारे शासक हैं जो गरीबी का दोष डालते हैं जातिवाद पर, यह भूल कर कि जाति जनगणना से गरीबी हटाने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

भारत की नई दृष्टि

संदर्भ

राकेश सिन्हा

> दुनिया के जाने-माने चिंतक फ्रेंज फेनो ने उपनिवेशवाद को विचार प्रणाली कहा है जो अपने शासितों को उसमें ढाल लेता है। लड़ाई विचार प्रणाली से मुक्ति की होती है। भारत में यह लड़ाई आसान नहीं है। इसका कारण वैकल्पिक परिभाषाओं को व्याख्यायित करने वालों की अल्पता है। ऐसे में नेतृत्व की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्यारह वर्षों के सफर का मूल्यांकन भारत में ही नहीं, दुनिया भर में विशेष कारणों से हो रहा है। सत्ता परिवर्तन तो लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव या लेबर पार्टियों के बीच या किसी अन्य देश में सत्ता हस्तांतरण क्षणिक हलचल पैदा करता है। क्योंकि, बदलाव का असर राजनीतिक व्यवहार एवं नीतियों तक सीमित रहता है, पर भारत में 2014 में सत्ता परिवर्तन का संदेश भिन्न था। स्वाधीनता के पश्चात भारत मैकालेवाद के संशोधित या परिष्कृत राह पर चल रहा था। मुगल एवं औपनिवेशिक कालों में सृजित सांस्कृतिक पहचान से भारत की मौलिकता दबी कुचली हुई थी। इसलिए 2014 का जनादेश आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों से कहीं अधिक भारत की पहचान और परिभाषा पर केंद्रित था। इसे कई बुद्धिजीवी नहीं पचा पाए। वे इस बदलाव को धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के आगे नहीं देख पाए। इसका कारण है। वे वैचारिक ठहराव के शिकार हैं। अपनी विचारदृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का साहस और इच्छाशक्ति दोनों नहीं होने से व्यक्ति, संगठन या विचार देर-सवेर काल वाह्य हो जाता है।

इससे इतर पश्चिम के समाजशास्त्र ने पिछले तीन सौ वर्षों में आलोचनात्मक दृष्टि विकसित की है। इसलिए वहां स्वार्थ है, पर ठहराव नहीं है। तभी तो यूरोप के बुद्धिजीवियों द्वारा मोदी सरकार का मूल्यांकन भारतीय बुद्धिजीवियों से अप्रभावित है। ब्रिटेन के अखबार 'द गार्डियन' ने 18 मई 2014 को संपादकीय में लिखा था- अंततः ब्रिटेन ने भारत छोड़ दिया। इसका निहितार्थ था कि मोदी की वैचारिक पृष्ठभूमि और उनका व्यक्तित्व गुलामी के सभी चिह्नों, संकेतों, मनोवैज्ञानिक प्रभावों और नकलची परिभाषाओं को मिटाने वाला साबित होगा, और पिछले ग्यारह वर्षों में यही हुआ।

आर्थिक विकास किसी राष्ट्र के लिए निश्चित तौर पर एक अनिवार्य पहलू होता है, परंतु जिस राष्ट्र की आयु को उसके राष्ट्रीय जीवन में उतार-चढ़ाव की अनगिनत घटनाओं, कालजयी नायकों की संख्या दर्शनों की विविधता को इतिहास की पुस्तकों में समेटना कठिन हो, उसको परिभाषित करना आसान नहीं होता है। भारत उसका उदाहरण है। हमारी यात्रा एक सभ्यता के रूप में शुरू हुई और प्रतिकूलताओं के बावजूद उसमें हजारों वर्षों में निरंतरता बनी रही। इसका कारण दर्शन प्रधान जीवन मूल्यों का होना है। भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है। समकालीन कालखंड उसी की अनुभूति करने-कराने की यात्रा है। दुनिया के जाने-माने चिंतक फ्रेंज फेनो ने उपनिवेशवाद को विचार प्रणाली कहा है जो अपने शासितों को उसमें ढाल लेता है। लड़ाई विचार प्रणाली से मुक्ति की होती है। भारत में यह लड़ाई आसान नहीं है। इसका कारण वैकल्पिक परिभाषाओं को व्याख्यायित करने वालों की अल्पता है।

ऐसे में नेतृत्व की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री ने ढाई हजार पूर्व के लिच्छवी, शाक्य और दसवीं शताब्दी के उत्तरमेरू शिलालेख को सामने रख कर अंतरराष्ट्रीय बैठकों में आठ फरवरी 2021 और 29 मार्च 2023 एवं 20 मार्च 2024 में भारत को लोकतंत्र की जननी बताने के विमर्श को आगे बढ़ाया। केपी जायसवाल की पुस्तक 'हिंदू पालिटी 1924' इस विषय पर श्रेष्ठ रचना है। वह भी पुस्तकालयों में धूल चाट रही है। मोदी के भाषणों में दर्शन व साहित्य के उपयुक्त उद्धरणों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर जमी बर्फ को पिघलाया। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण और जैन दर्शन आदि बौद्धिक विमर्श उपेक्षित रहे। वर्ष 2018 के भाषण में मोदी ने याज्ञवल्क्य, गार्गी और अष्टवक्र, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 15-17 फरवरी 2018 में अथर्वेद का 'मात भूमिः पुत्रोह प्रथिव्याष, अंतरराष्ट्रीय सोलर समिट में वेद में सूर्य के महत्त्व को रखा। उन्होंने कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की रचनाओं को बार-बार उद्धृत किया। इन सबने विरासत और वर्तमान के बीच की दूरी प्रायः समाप्त कर दी।

नवंबर 2014 में एक भाषण में राजधर्म की व्याख्या उन्होंने राजा रंति देव की पौराणिक कथा द्वारा की। जिसमें राज्य या स्वर्ग की इच्छा तक को नकारा गया। 'मन की बात' के सौवें अंक में वेद के श्रम मंत्र 'चरैवेति. चरैवेति' को उद्धृत किया, तो 2021 में संसद में उन्होंने वेद की ऋचाओं द्वारा लोकतंत्र का मर्म समझाया। जिसका अर्थ समावेशी होना है। भारतीय दर्शन-संस्कृति की प्रतिनिधि पुस्तकों को दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट करना सांस्कृतिक विरासत के प्रति आग्रह है। 2014 में जापानी सम्राट और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को भगवदगीता एवं बाइडेन को 'द टेन प्रिंसिपल आफ उपनिषद' (जो बटलर येट्स और पुरुहोति स्वामी द्वारा अनुवादित हैं) भेंट की।

प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय वांग्मय पर काम करने वालों को प्रोत्साहित किया है। चाहे राबर्ट गैफ्रिक द्वारा स्लोवक भाषा में अनुवादित उपनिषद हो या अब्दुल्ला एल बरौन द्वारा अरबी में रामायण या महाभारत का अनुवाद। पतंजलि के योग को 2014 में अज्ञातवास से निकाल कर मोदी ने वैचारिक हस्तक्षेप की यात्रा शुरू की जो जारी है। इसमें संकल्प, प्रतिबद्धता और उत्साह तीनों हैं। भारत में योग को हिंदू बहुमतवाद कह कर आलोचना की गई, तो तीन दर्जन मुसलिम राष्ट्रों सहित 175 देशों ने इसे भारत का सर्वोत्तम योगदान माना। यह दिखता है कि भारत में वैचारिक विद्वेष संयमित नहीं है। ग्यारह वर्ष नव मैकालेवाद के अंत और भारतीय अस्मिता के उदय की जीवंत कहानी है, जहां झंझावात भी है, विरोधाभास भी। यही है मोदी का भारतनामा।

विमान हादसे पर बहस

बाखबर

सुधीश पचौरी

> ड्रीमलाइनर के भयावह हादसे ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की 'अपराध कथा' को किनारे कर दिया। जबकि मेघालय पुलिस की शुरुआती जांच के बाद यह एक डरावनी कहानी की तरह खुलने लगी थी और दर्शकों को सोचने पर विवश करने लगी थी।

देखते ही देखते 241 और 29 यानी कुल 270 जिंदगियां खत्म! मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं। हम थरथराते दिल से देखते हैं कि एक हवाई जहाज उड़ता है फिर कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर गिरने लगता है। वह एक अस्पताल की इमारत से टकराता है और आग की ऊंची लपटें निकलती हैं।

जहाज का अगला हिस्सा इमारत में घुसा दिखता है। पहिए लटके दिखते हैं। सुरक्षाकर्मी सक्रिय हैं। प्रशासन सक्रिय है। हर चैनल में शोक बरपा है। हाहाकार मचा है। एंकर और संवाददाताओं के चेहरे उड़े हुए हैं। कहानी खुलती है कि उड़ते ही जहाज के इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। पायलट 'खतरा-खतरा' यानी 'मे-डे मे-डे' चिल्लाए। उसके बाद सब कुछ जलता, धूं-धूं करता नजर आया। 242 यात्रियों में से बचा एक व्यक्ति बोला कि उसका भाई नहीं बचा और वह बच गया, वह खुद पैदल चल कर अस्पताल की ओर जाता दिखा।

खबर आते ही प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर उन्हें तुरंत अहमदाबाद भेजते हैं। सब चिंतित और गंभीर दिखते हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते हैं। अस्पताल में आहतों से बात करते हैं। शाम की बहसों का एक बड़ा हिस्सा 'जिम्मेदार कौन' जैसे सवाल से उलझता है। कुछ के लिए 'निजीकरण' जिम्मेदार, तो कुछ के लिए 'एअर इंडिया' की खराब देखभाल जिम्मेदार। एक एंकर की नजर में एअर इंडिया के जहाजों की देखभाल कर रही तुर्किए की एक कंपनी जिम्मेदार है। उसे हैरत है कि एक शत्रु देश की कंपनी को क्यों लगाया हुआ है। कुछ विशेषज्ञ कहिन कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।

एक चर्चक कहिन कि इस दुर्घटना के बहाने एक एअरलाइन कंपनी को बदनाम करना ठीक नहीं है। टाटा ने हमेशा देश की सेवा की है। दुनिया की बहुत सी एअरलाइनें इसी तरह के 'ड्रीमलाइनर' उड़ाती हैं। यह बेहद मजबूत जहाज है और कि यह शायद दुनिया में किसी 'ड्रीमलाइनर' की पहली दुर्घटना है...। गनीमत कि यह दुर्घटना अगले दोपहर तक भी एक 'दुर्घटना' की तरह बताई जाती रही।

'ड्रीमलाइनर' के भयावह हादसे ने 'राजा रघुवंशी हत्याकांड' की 'अपराध कथा' को किनारे कर दिया। जबकि वह कहानी मेघालय पुलिस की शुरुआती जांच के बाद एक बेहद डरावनी कहानी की तरह खुलने लगी थी और यह दर्शकों को सोचने पर विवश करने लगी थी कि क्या कोई सद्यः विवाहिता अपने ही पति की हत्या की इतनी गहरी साजिश रच सकती है और शादी के सात दिन बाद हनीमून के बहाने भाड़े के हत्यारों की मदद से पति की निर्मम हत्या को अंजाम दे सकती है?

यह अपराध कथा इसलिए भी और भयानक लगती है कि इस हत्या की साजिश शादी से तीन महीने पहले ही रच दी गई थी। कहानी के अनुसार सोनम मंगली और राजा भी मंगली। सोनम ने सोचा कि राजा को निपटा दें, तो मंगल दोष खत्म। बाद में वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कराई गई। सोनम ने साफ कहा कि इसका अंजाम अच्छा न होगा...फिर योजना बनाई कि मेघालय जाकर हनीमून के बहाने उसे निपटाएंगे। भाड़े के तीन हत्यारे पहले ही मेघालय भेज दिए गए। प्रत्येक को पांच हजार अग्रिम दे दिए गए। फिर राजा से बीस हजार लेकर उन लोगों को दिए गए। जब भाड़े के हत्यारों ने राजा के अच्छे व्यवहार को देख मारने से मना किया, तो सोनम ने कहा कि बीस लाख दूंगी। एक ने राजा को चाकू मारा। उसने इस हमले का विरोध किया, तो पीछे खड़ी सोनम ने जोर से कहा 'मार दो' और आरोपियों ने कई बार चाकू के वार कर उसे खत्म कर दिया और गहरी खाई में फेंक दिया। उसके साथ ही खून से सनी बरसाती भी फेंक दी..., उसके बाद वह इंदौर आई। दो दिन तक राज कुशवाहा की सहायता से एक होटल में ठहरी। फिर गाजीपुर गई, जहां उसने अपने को 'नशा कराया गया' की तरह पेश किया। फिर एक ढाबे वाले से उसका मोबाइल लिया और अपने भाई को फोन किया। उसने यूपी पुलिस को बताया। तब उसको ढाबे से पकड़ा गया। राजा का शव भी पुलिस को कई दिन बाद मिला।

उधर, जैसे ही 'आपरेशन सिंदूर' के बाद आतंकवाद के विरोध में भारत का पक्ष दूसरे देशों में स्पष्ट करने गए सांसदों का दल वापस लौटा और प्रधानमंत्री उनसे मिले, वैसे ही कई विपक्षी सांसद विपक्ष के ही निशाने पर आ गए। एक चैनल के सर्वे ने बताया कि 88 फीसद लोगों ने माना कि सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजना प्रधानमंत्री का 'मास्टर स्ट्रोक' था।

फिर एक दिन जैसे ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजग के शासन के ग्यारह वर्ष की उपलब्धियों को एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए गिनाया तो विपक्ष को यह एकदम नहीं भाया। बहसों में सत्तापक्ष कहे कि सरकार हर मोर्चे पर सफल, तो विपक्ष कहे कि यह सरकार हर मोर्चे पर असफल!

उच्चस्तरीय जांच समिति

यह अपेक्षित ही नहीं आवश्यक था कि अहमदाबाद के भयावह विमान हादसे की सघन जांच के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की जाती। गृह सचिव की अध्यक्षता में ऐसी जो समिति गठित की गई है, उसे तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और यह सुझाव भी कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना रोकने के क्या उपाय किए जाएं। भारत के साथ विश्व समुदाय को स्तब्ध करने वाली इस दुर्घटना की जांच अन्य एजेंसियां भी करेंगी। इस जांच में विमान निर्माता कंपनी के साथ अमेरिकी और यूरोपीय जांच एजेंसियों की भी भागीदारी होगी। यह भी समय की मांग थी, क्योंकि यह दुर्घटना बहुत ही चकित करने वाली है। बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान जिस तरह हादसे का शिकार हुआ, उसे देखते हुए इस कंपनी को भी दुर्घटना के कारणों की तह तक जाना ही होगा। इसलिए और भी, क्योंकि एक तो भारत में इस कंपनी के और भी विमान हैं और दूसरे, उस पर अपने विमानों के निर्माण में सुरक्षा उपायों की अनदेखी के गंभीर आरोप लग चुके हैं। सरकारी से निजी कंपनी टाटा के हाथों में गई एअर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की गहन जांच के साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा और उनमें से एक यह भी है कि हमारे सभी प्रमुख हवाईअड्डे जिन जगहों पर स्थित हैं, वे चारों तरफ आबादी से घिरे हैं। इसके चलते किसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में आसपास की आबादी को भी क्षति पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। अहमदाबाद में ऐसा ही हुआ। यहां विमान के एक मेडिकल कालेज के हास्टल पर गिरने से वहां के मेडिकल छात्रों समेत कई लोग मारे गए। चारों ओर आबादी से घिरे हवाईअड्डों के आसपास विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उस तक सहायता पहुंचाने में भी बाधा पहुंचती है। विमान यात्रा को केवल इसलिए सुरक्षित बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद सरीखे हादसे विमानों से यात्रा के प्रति लोगों के मन में संदेह बढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि आज विमान यात्रा करना एक आवश्यकता बन गई है। देश में पिछले कुछ वर्षों में विमान यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ ही हवाईअड्डों की भी संख्या बढ़ रही है। स्पष्ट है कि डीजीसीए एवं एयरपोर्ट अथारिटी जैसी एजेंसियों को और सजग होना होगा। विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर रह-रहकर सवाल उठते रहते हैं। कम से कम सुरक्षा को तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बात केवल सुरक्षित विमान संचालन की ही नहीं, रेल और बस समेत आवागमन के अन्य साधनों को भी सुगम और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। यह एक तथ्य है कि अपने देश में रेल और सड़क हादसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है।

सुधारनी होगी स्थिति

राज्य में सरकारी चिकित्सा सेवा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे। चिकित्सकों, नर्सों और इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की बहाली भी की जा रही। फिर भी आमजन तक इसका पूरा लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। इस बिंदु पर विचार करने की जरूरत है। एक एम्स पटना में कार्यशील है। दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। नए भवन बनाए गए हैं। जांच की सुविधाओं को जनोपयोगी बनाने के प्रयास चल रहे हैं, ताकि गरीब तबके के मरीजों को निजी जांच केंद्रों में नहीं जाना पड़े। इसके बावजूद आम जन की परेशानी कम नहीं हो रही। कहीं बेड की कमी तो कहीं दवा की कमी तो कहीं चिकित्सकों की अनुपस्थिति, यानी साधारण व्यक्ति इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा। इन दिनों एम्स में उपचार कराना सहज नहीं। दूर दराज से आए मरीज दो-तीन दिन तक एंबुलेंस में ही अपने उपचार की बारी का इंतजार करते रह जाते हैं। इसके बाद भी यह जरूरी नहीं कि उन्हें भर्ती ले लिया जाए। ऐसे में व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने की जरूरत है। मरीजों को अक्सर कह दिया जाता है कि बेड खाली नहीं है। कुछ पैरवी-पहुंच की दरकार की बात करते हैं। सवाल उठाता है कि साधारण व्यक्ति कैसे यह अनुभव करे कि राज्य में चिकित्सा सेवा बेहतर हुई है।

> जब मरीज का सही समय पर उपचार ही नहीं हो पाए तो बेहतरी की सारी कवायद बेमतलब है

कह के रहेंगे — माधव जोशी

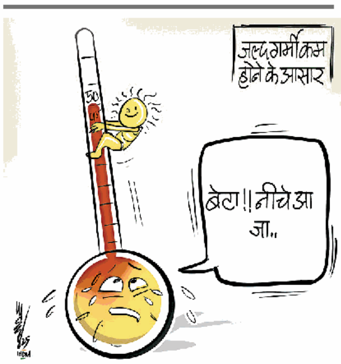

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या परमाणु हथियारों की दलील देकर इजरायल का ईरान पर हमला करना सही है?

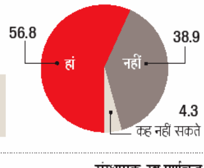

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ईरान-इजरायल युद्ध ने विदेश नीति के मोर्चे पर भारत की चुनौती बढ़ा दी है?

भारत-कनाडा रिश्तों में जमी बर्फ पिघली

कुशल मेहरा

कनाडा में सरकार की दिशा प्रधानमंत्री के रवैये से तय होती है और उसका अपने दल पर दबदबा होता है। लिबरल पार्टी में वही होगा, जैसा पीएम मार्क कार्नी चाहेंगे

अवधेश राजपूत

इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, भारतीय प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच रहे हैं। उन्हें कनाडा आने का कथित निमंत्रण न मिलने पर कांग्रेस ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय प्रधानमंत्री को जी-7 सम्मेलन में आमंत्रित न करना मोदी सरकार की कमजोर कूटनीति का प्रमाण है। इसके बाद जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मोदी को निमंत्रण दिया, तो कहा गया कि यह देर से दिया गया, पर आखिर देरी को कैसे परिभाषित किया जाएगा? भारतीय प्रधानमंत्री को जी-7 में भाग लेने के लिए निमंत्रण देने को लेकर कनाडा में भी सवाल उठे। इनका जवाब देते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था एवं सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के साथ कई आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है। मार्क कार्नी ने खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में तथाकथित भारतीय एजेंटों का हाथ होने के आरोपों की जांच से जुड़े प्रश्न पर कहा था कि कानूनी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यह समझा जाना चाहिए कि मार्क कार्नी का भारत समेत अनेक मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अलग रवैया है। इसका प्रमाण यह है कि भारत-कनाडा आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए एक-दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करेंगे।

मार्क कार्नी तब कनाडा के अंतरिम पीएम बने थे, जब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने रवैये के कारण जस्टिन ट्रूडो की फजीहत हो गई थी। उनकी ही पार्टी की ओर से उन पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव था। यदि वह प्रधानमंत्री बने रहते, तो लिबरल पार्टी बुरी तरह हारती। कनाडा-भारत संबंध बिगड़ने के लिए जस्टिन ही जिम्मेदार थे। वह अपने कार्यकाल में खालिस्तान समर्थकों को खुश करने में लगे रहे और तब तो ऐसा करना उनकी मजबूरी हो गई थी, जब अपनी अल्पमत सरकार चलाने के लिए वह खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के समर्थन के मोहताज हो गए थे। उन्होंने जगमीत और अन्य खालिस्तान समर्थकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकी निज्जर मामले में उन्होंने यह हास्यास्पद बयान दिया था कि उसकी हत्या में भारतीय एजेंटों के हाथ होने के "पुख्ता आरोप" मिले हैं। यह पहली बार था, जब किसी शासनाध्यक्ष ने प्रमाण नहीं, बल्कि आरोपों के आधार पर किसी देश को कठघरे में खड़ा किया हो और वह भी ऐसे शख्स की हत्या के मामले में, जो अवैध तरीके से कनाडा पहुंचा था और जिसे भारत में आतंकी करार दिया गया था। इसके बाद कनाडा-भारत संबंध बिगड़ने ही थे और वे बिगड़े भी।

जस्टिन ट्रूडो की जगह अंतरिम प्रधानमंत्री बने कार्नी परंपरागत राजनेता नहीं हैं। वह व्यवसायी रहे हैं और भारत से संबंधों समेत अन्य मामलों को अपनी तरह से देखते हैं। इसके संकेत तभी मिल गए थे, जब चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में खालिस्तानी झंडे नहीं दिखे। जस्टिन न सिर्फ खालिस्तान समर्थकों से घिरे रहते थे, बल्कि उनकी सभाओं में खालिस्तानी झंडे भी लहराते थे। चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री बने कार्नी के मंत्रियों में से एक जूनियर मंत्री को छोड़ अन्य के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह खालिस्तान समर्थकों का साथी है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, पर उन्हें खालिस्तान समर्थक नहीं कह सकते। मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण मिलने के पहले विदेश मंत्री जयशंकर और अनीता आनंद में बात हुई थी। कार्नी की जीत के बाद मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। इसी कारण इस कहानी में दम नहीं दिखता कि जी-7 के बाकी देशों ने जब दबाव डाला, तब कार्नी ने मोदी को निमंत्रण दिया।

अभी यह नहीं कह सकते कि मोदी की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के संबंध बहुत मधुर होने जा रहे हैं, पर इतना अवश्य है कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। यह भविष्य बताएगा कि वह कितनी पिघलती है? यदि कनाडा को भारत की जरूरत है तो उसे भी भारत की। यह कह सकते हैं कि कनाडा को भारत की ज्यादा जरूरत है, पर भारत को ऊर्जा सुरक्षा का जो स्रोत और अपने तकनीकी विकास के लिए जो दुर्लभ खनिज चाहिए, वे उसे कनाडा से आसानी से मिल सकते हैं। यदि दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आते हैं तो मौजूदा व्यापार दोगुना यानी 20 अरब डालर तक पहुंच सकता है।

कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की आबादी कुल आबादी का करीब आठ प्रतिशत है। यह सही है कि यहां खालिस्तान समर्थक सक्रिय हैं, पर उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। उनकी राजनीतिक सक्रियता का कारण उनकी ओर से कनाडा के राजनीतिक सिस्टम का दुरुपयोग किया जाना है। इसी कारण वे राजनीतिक दलों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। इस बार भारतीय मूल के कहीं अधिक सांसद चुनाव जीते हैं, पर भारत के लिहाज से अच्छी बात यह रही कि एनडीपी का खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह खुद चुनाव हार गया। वह एनडीपी का प्रमुख था। एनडीपी का वोट प्रतिशत भी 17.8 से गिरकर 6.3 पर आ गया। चूंकि एनडीपी न्यूनतम 12 सीटें भी नहीं जीत सकी, इसलिए उसने अपना आधिकारिक दर्जा भी गंवा दिया। इसी कारण जगमीत को पार्टी प्रमुख से हटना पड़ा। मार्क कार्नी बहुमत से थोड़ा ही पीछे हैं, इसलिए उन्हें एनडीपी के सात सांसदों की जरूरत नहीं। यह भी महत्वपूर्ण है कि कनाडा में सत्ताधारी दल की दिशा प्रधानमंत्री के रुख-रवैये से तय होती है और उसका अपने दल पर दबदबा होता है। फिर से सत्ता में आई लिबरल पार्टी में वही होगा, जैसा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहेंगे।

मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण मिलने के बाद से खालिस्तान समर्थक छोटे-बड़े और गुमनाम से संगठन पगलाए हुए हैं। वे धरना-प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। मोदी के कनाडा आगमन पर खालिस्तान समर्थकों को काबू में रखने के लिए कनाडा सरकार को सतर्क रहना होगा, पर भारत के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपनी कनाडा नीति को परिभाषित करे। मेरे लिए भारत सरकार की कनाडा नीति समझना कठिन है। मैं चाहूंगा कि कनाडा के मामलों में विदेश मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा हो।

(लेखक कनाडा मामलों के जानकार एवं पाडकास्टर हैं और वहां प्रवास भी करते हैं)

response@jagran.com

राइटर की फाइटर बनने की चाहत

हास्य-व्यंग्य

आलोक सक्सेना

कुछ लोग यह भी चाह रहे थे कि युद्ध में सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को खरोंच भी न आए

आपरेशन सिंदूर के दौरान मैं अपने जांबाज योद्धाओं के पराक्रम और शौर्य से गर्व से भरा हुआ था। मैं जांबाज फाइटर योद्धा तो नहीं, लेकिन लोग मुझे रंगबाज राइटर अवश्य कहते हैं। मैं राइटर से फाइटर बनने के लिए अपने योद्धाओं पर कुछ लिखना चाह रहा था। दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिए जाने की खबर आते ही मेरा मन विचलित हो उठा। दिल से आवाज आई, क्या अब दुश्मन अपने यहां आतंकियों को पालने और आतंकी गतिविधियों के नए-नए तरीके अपनाने से बाज आएगा? मेरा दिमाग बार-बार यही कह रहा था कि इस युद्ध से हम दुश्मन का सोच और उसका भूगोल बदलने में जरूर कामयाब होंगे।

मेरे दिमाग पर ड्रोन और मिसाइल की तरह अनेक प्रश्न तेजी से विचरण करने लगे। तभी एक संपादक मित्र के फोन ने सब संभाल लिया। वह कह रहे थे कि आपकी रचना...। मैंने उनकी बात पूरी होने के पहले अपना प्रश्न दाग दिया, 'कैसे बनते हैं जांबाज फाइटर योद्धा?' उत्तर मिला, 'सर्वप्रथम कैडेट बनने के लिए और देश की सुरक्षा-सेवा हेतु समर्पित होने का जज्बा होना चाहिए। उसके बाद वायुसेना में 'फ्लाइंग अफसर' के लिए सेलेक्शन की तैयारी करनी पड़ती है। सेलेक्ट हो गए तो कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। तब जाकर कोई बनता है जांबाज फाइटर वायुयोद्धा।' उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक पैदा हुई और याद आ गया कि कैसे लोग दुश्मन के क्षेत्र में दागी जाने वाली मिसाइलों की आवाज से तो खुश होते थे, लेकिन कुछ भारतीय इलाकों में 'ब्लैकआउट' की खबर आते ही चिंतित हो जाते थे और यह सोचने लगते थे कि उनके यहां भी ब्लैकआउट की नौबत आई तो कहीं अंधेरे में अंगुली में सुई न चुभ जाए। मैंने देखा था कि जो लोग दुश्मन को मटियामेट करने और कुचल देने को लेकर उतावले थे और पाकिस्तान के कब्जे वाली अपनी जमीन वापस लेने की रणनीति बता रहे थे, वही सिर पर अचानक सूखा पत्ता गिरने से डर जाते हैं और कई दिन तक उस पेड़ के नीचे से नहीं गुजरते। कुछ लोग यह भी चाह रहे थे कि युद्ध में सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को खरोंच भी न आए।

मैं अपने आप को किसी जांबाज फाइटर से कम नहीं समझ रहा था। तभी मेरी निगाह टीवी पर चल रहे समाचार पर गई। वहां गर्व से 'युद्ध-गाथा' सुनाते हुए बताया जा रहा था, 'दुश्मन ने अपना खाली विमान हमारे फाइटर प्लेन के आगे करते हुए हमारे फाइटर प्लेन पर पीछे से आक्रमण करके उसे मार गिराना चाहा, मगर हमारे योद्धाओं ने दुश्मन के फाइटर प्लेन को ही मार गिराया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित थे और सकुशल भारत की धरती पर लौट आए थे।' मैंने संपादक जी को फोन मिलाया और अपनी एक जिज्ञासा उनके सामने रखी। उन्होंने इसे यह कहकर शांत किया कि दुश्मन हमारे ड्रोन को हमारा प्लेन समझकर उसे गिराकर बहुत खुश हुआ, मोगैंबो की तरह, लेकिन वह नासमझ मूर्ख का मूर्ख ही रहा। आपरेशन सिंदूर में हमारे योद्धाओं को युद्ध में जाने और अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला, तो लोगों का जज्बा भी आसमान पर है। अपने देश के लिए कुछ नया कर दिखाने के जज्बे से उनका रोम-रोम भरा है। इसलिए हे मेरे मित्र, तू चिंता मत कर।

मेरा मन अब भी चिंतित था। मैंने प्रश्न किया, लेकिन कुछ लोग अचानक युद्ध थमने से खुश नहीं हैं। मेरे संपादक मित्र ने समझाया, 'इसे ऐसे समझो कि यदि किसी लेखक ने यह समझकर कहीं कोई रचना भेजी कि उसे तो तत्काल छाप दिया जाएगा और पाठक उसे कालजयी करार देंगे, लेकिन उसे प्रकाशन योग्य न समझा जाए तो जैसा उस लेखक को लगेगा, वैसा ही कुछ लोगों को भी लग रहा है। आप चिंतित न हों।'

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

तथ्य-कथ्य | **पश्चिम एशिया में भारतीयों की संख्या**

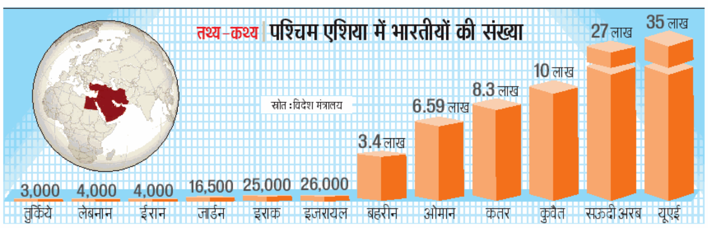

देश	संख्या
तुर्किये	3,000
लेबनान	4,000
ईरान	4,000
जार्डन	16,500
इराक	25,000
इजरायल	26,000
बहरीन	3.4 लाख
ओमान	6.59 लाख
कतर	8.3 लाख
कुवैत	10 लाख
सऊदी अरब	27 लाख
यूएई	35 लाख

ऊर्जा

पिता का त्याग

भारतीय संस्कृति में समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का वर्णन किया गया है। पिता को धार्मिक ग्रंथों में देवतुल्य माना गया है। इस धरती पर पिता से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ मार्गदर्शक नहीं है। पिता का संघर्ष, अनुभव और ज्ञान संतान को कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और स्नेह को पिता शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से प्रकट करता है। वह जीवनभर संघर्ष कर अपनी संतान के सुनहरे भविष्य की नींव रखता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पुत्र कितना भी निर्दयी स्वभाव का क्यों नहीं हो जाए, पिता उसके प्रति ममता और प्रेम को नहीं त्यागता, क्योंकि उसके लिए पिता ने कितनी ही विपत्तियां झेली होती हैं। पिता के हृदय में उसके लिए सदैव ममता और प्रेम ही अंकुरित होता है। इसीलिए पिता का विराट व्यक्तित्व स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि पिता में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए संतान को हमेशा पिता का सम्मान और आदर करना चाहिए।

जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उसके कंधे पर जनेऊ धारण कराया जाता है, जिसमें से एक धागा पितृ ऋण का प्रतीक है। यह धागा संतान को अपने माता-पिता के प्रति दायित्वों का बोध कराता है। पिता अपने संतान का मार्गदर्शन करते हुए उसके जीवन को सुदृढ़ बनाता है। पूरी दुनिया में केवल पिता ही है, जो अपनी संतान को अपने से भी श्रेष्ठ और सफल देखकर प्रसन्न होता है। पितृदिवस, पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पिता का योगदान और त्याग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने पिता के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष और बलिदान हमारे लिए अनमोल हैं।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

सहानुभूति वोट

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सभी विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भाजपा के भीतर भी इसके प्रभाव को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन भाजपा विपक्ष के इस हमले को भी सकारात्मक नजरिए से देख रही है। इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इससे नीतीश कुमार के समर्थकों का सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का अति पिछड़ों और महिलाओं के बीच एक बड़ा समर्थक वर्ग है। जाहिर है वे भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे और उनके आखिरी चुनाव को देखते हुए सहानुभूति में उन्हें वोट देने के लिए एकजुट हो सकते हैं। इसके पहले कई बड़े नेताओं के मामले में ऐसा देखा जा चुका है।

महाराष्ट्र हार की चुभन

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को भले ही छह महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार को भूल नहीं पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने छह महीने बाद एक लेख के जरिए महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियों के उन्हीं आरोपों को दोहराया है, जिनके जवाब चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है। हालांकि लेख में लगाए उनके आरोपों पर आयोग ने फिर से जवाब दिया। बाद में आयोग पर लिखित में जवाब न देने जैसे आरोप लगाए गए। इस पर आयोग ने लिखित में भी जवाब दिया। लोगों का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को धार देने में जितनी ताकत लगा रही है, उतनी यदि मतदाता सूची की गड़बड़ियों को खोजने के लिए लगाती तो शायद उसे चुनाव आयोग को घेरने के लिए कुछ पुख्ता सुबूत मिल जाते। यह देखना दिलचस्प होगा कि लिखित जवाब के बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र की हार पर कौन सा नया शिगूफा लेकर आती है या फिर उसे भूल कर नई जमीन तैयार करने में लगती है।

राजरंग

उड्डयन मंत्रालय

एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाई। सरकार की तरफ से यह पहला बयान आने वाला था। मंत्रालय के एक कमरे में 60 से ज्यादा कैमरे और उससे ज्यादा कैमरामैन और उससे भी ज्यादा पत्रकारों की ऐसी भीड़ जमा हुई जैसी मंत्रालय के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। सारे कर्मचारी जी-जान से लगे हुए थे। मंत्री जी के आगमन से ठीक पहले किसी की नजर उस कुर्सी पर गई, जहां वह बैठने वाले थे। यह क्या? यह कुर्सी तो बाकी अन्य कुर्सियों की ही तरह है। फिर जल्दी से दूसरी ऊंची कुर्सी मंगाई गई। तभी किसी ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का तो कोई बोर्ड ही बैकग्राउंड में नहीं है। जल्दी से बोर्ड मंगाया गया, कीलें मंगाई गईं, हथौड़ा लाया गया और उसे टांगा गया।

कोई भी सही

भाजपा के अध्यक्ष फलां हो सकते हैं... पार्टी हाईकमान इन पर दांव लगा सकती है... ये अध्यक्ष संगठन के लिए सबसे बेहतर होंगे...! महीनों से उत्साह के साथ चल रही ये अटकलें और आकांक्षाएं भी अब थकी-मांदी दिखाई दे रही हैं। जिस भाजपा मुख्यालय में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा कभी समीकरण तो कभी क्षमताओं का एंगल ढूंढ़कर होती थी, अब वहां का माहौल बदल चुका है। जैसे ही इस मुद्दे पर बात की जाती है तो अधिकतर का टका सा जवाब होता है-

जिसे बनाना हो पार्टी बना दे,
लेकिन अब जल्दी बना दे।

पोस्ट

युद्ध में यह नहीं गिना जाता कि किसने कितने हमले किए। गिना यह जाता है कि किसने अपने लक्ष्य हासिल किए। कई जनरल और नेता खोने के बाद ईरान के लिए इजरायल पर मिसाइलें दागना ही काफी नहीं है। उसे सैन्य लक्ष्य भी हासिल करना होगा।
हुसैन हक्कानी@husainhaqqani

रूस-यूक्रेन के बाद ईरान-इजरायल टकराव एक और उदाहरण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। आदित्य राज कौल @AdityaRajKaul

थल, नभ, जल... मौत कहीं भी आ सकती है। इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे वह आपका आखिरी दिन हो।
नवनीत मिश्र@navneetmishra99

डब्ल्यूटीसी फाइनल में आरंभ में आस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका की टीम पर हावी रही, पर चौथे दिन वह हार गई। टेस्ट क्रिकेट का यही रोमांच है कि आप राख से उठकर बुलंदी छू सकते हैं। यह टेस्ट क्रिकेट की विजय है। हार के जबड़े से जीत तक आने के लिए दक्षिण अफ्रीका को बधाई।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जनपथ

चाहें मरना-मारना नहीं शांति की बात,
एक देश है कर रहा दूजे पर आघात।
दूजे पर आघात चल रही आतिशबाजी,
दुनिया का हर मुल्क चाहता बनना गाजी!
बरस रही है आग सुनाई देतीं आहें,
किंतु शांति का पाठ सीखना वे ना चाहें।
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 64

****

एक्स से
आज भी 14 करोड़ बच्चे दुनिया भर में बाल श्रमिक हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने का वादा किया है। तो ये किसके बच्चे हैं? ये सिर्फ संख्या नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं- कैलाश सत्यार्थी/ नोबेल विजेता

गलवान की इस बरसी और पाकिस्तान से हुए संघर्ष की सीख क्या है? यही कि हमें पाक और चीनी सीमाओं पर एक साथ जंग लड़ने की मुकम्मल तैयारी करनी होगी। युद्ध-नीति का पुराना सिद्धांत है, जंग लड़नी हो, तो शत्रु के मुकाबले हरदम चाक-चौबंद रहना होगा। रूस-यूक्रेन, गाजा-इजरायल व इजरायल-ईरान के संघर्षों के बीच दुनिया तेजी से बदल गई है और ऐसे में इस पर अमल करना निहायत जरूरी है।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

गलवान : पांच बरस बाद

आजकल

शशि शेखर

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी को 15-16 जून, 2020 की रात तक कोई नहीं जानता था। उस रात वहां कुछ ऐसा हुआ, जिसने न केवल भारत और चीन के रिश्तों पर व्यापक असर डाला, बल्कि हमें अपनी सामरिक तैयारी व सीमा की सुरक्षा के जटिल मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने को भी प्रेरित किया।

आज गलवान हादसे की पांचवीं बरसी पर उन रक्त-रंजित लम्हों को याद करना जरूरी है।

याद करें। भारत और चीन के बीच 2013 से रह-रहकर तनाव की स्थिति बन जाती थी। 2017 में भी चीनी सैनिक विवादित क्षेत्र में घुस आए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में देर नहीं लगाई थी। इस तनाव को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष कई दौर की बातचीत के बाद पुरानी स्थिति बहाल करने पर राजी हो गए थे। इसी बीच गलवान घाटी में चीन ने एक निगरानी चौकी बना ली थी। भारतीय सेना की आपत्ति के बावजूद चीनी सैनिकों ने उसे तय समय-सीमा में खाली नहीं किया था। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में हमारे सैनिक जब वहां कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे, तो बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया।

सन् 1996 और 2005 की संधियों के तहत दोनों पक्षों के सैनिक झड़प की स्थिति में सांघातिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंसानी जिस्मों की सीधी टक्कर में संख्या बल का महत्व बढ़ जाता है। पहले से तैयार उन आततायियों के पास लोहे की कीलों से जड़े हुए डंडे, स्टील के रॉड और इस तरह की तमाम सामग्री थी, जो किसी भी शख्स की जान लेने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। हमारे सैनिकों ने जी-जान से मुकाबला किया, लेकिन वे लड़ाई की नीयत से वहां नहीं गए थे। नतीजतन, कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान इस 'हैंड टु हैंड फाइट' में शहीद हो गए।

भारतीय नागरिकों पर यह खबर शोक की भारी शिला की मानिंद टूटी। सवाल उठने लगे, सन् 1962 से 2020 के बीच गुजरे 58 वर्ष क्या तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं थे? सब जानते हैं कि चीन ने सोची-समझी साजिश के तहत 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया। उसके बाद से बीजिंग वहां की जनसंख्या में गैर-तिब्बती लोगों का दखल बढ़ाता रहा है। 1980 के दशक के बाद उसने निरंतर भारतीय सीमा से सटे इलाकों में सैनिक छावनियां, हवाई पट्टियां और हेलीपैड बनाने शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि भारत सोया पड़ा था। हम भी तैयारी कर रहे थे, परंतु रफ्तार बहुत धीमी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता सम्हालते ही इसको जबरदस्त तवज्जो देनी शुरू की। सीमा तक चौड़ी सड़कें, सीमावर्ती इलाकों में ट्रेन नेटवर्क की स्थापना के अलावा सीमावर्ती चौकियों को मजबूत किया। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल पर भी अतिरिक्त ध्यान देना इसी दौर में शुरू हुआ। यह सच है कि तमाम तैयारियों के बावजूद हमें चीन तक पहुंचने के लिए अभी कई वर्षों की दरकार है। इसके बावजूद बीजिंग के दरबारियों में खलबली मचनी शुरू हो गई थी। गलवान से पहले डोकलाम का विवाद इसलिए जान-बूझकर खड़ा किया गया था। समझौते के बाद गलवान जैसी हरकत शायद हमें रोकने की कवायद थी।

क्या वे सफल रहे?

यकीनन नहीं। नई दिल्ली की हुकूमत ने हिम्मत नहीं हारी और न ही आपा खोया। आनन-फानन में 68,000 जवान, 90 संहारक टैंक और बड़ी संख्या में दूसरे जरूरी हथियार वहां तैनात किए गए। नई दिल्ली के हुक्मरां जानते थे कि इतना पर्याप्त नहीं है। चीन के दो लाख से ज्यादा जवान 'वेस्टर्न थियेटर कमांड' में तैनात थे और उनका समूचा लाव-लश्कर दूर नहीं है।

हम जानते हैं कि भारत और चीन की सीमा कुल जमा 3,488 किलोमीटर लंबी है। हालांकि, चीन इसे सिर्फ 2,000 किलोमीटर बताने पर तुला रहता है, लेकिन इससे हमारे रद्दे-

अमल पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे रणनीतिकार स्पष्ट थे कि इतने बड़े इलाके में अगर हम कारगर गश्त नहीं कर सकते, तो वे भी पूरे तौर पर सक्षम नहीं हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर हमारे सैनिकों ने थाकुंग चोटी सहित तमाम दुर्गम और बर्फीले स्थानों पर कब्जा जमा लिया। इन स्थानों का रणनीतिक लाभ तय था। हम ऊंचाई पर थे और घाटी में मौजूद चीनी सैनिक हमारे सीधे निशाने पर। चीनी भूल क्यों गए थे कि 1984 से ही हमारे पास दुर्गम स्थानों पर जमे रहने की पर्याप्त ट्रेनिंग है। इसी साल हमारी फौजों ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाया था।

तब से अब तक पाकिस्तान इस मुद्दे पर बस दांत किटकिटाकर रह जाता है। चीन ने जब से अपना 'बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव' शुरू किया है, तभी से उसकी बुरी नजर लद्दाख के तमाम इलाकों पर पड़नी शुरू हो गई है। वह हमसे तिजारत तो बढ़ाना चाह रहा है, पर कब्जाई जमीन से पांव पीछे नहीं खींचना चाहता। बहरहाल, गलवान हादसे पर लौटते हैं।

ऊंचे स्थानों पर भारत के कब्जे से चीन को जबरदस्त धक्का लगा था। इससे उसके वार्ताकारों का मनोबल टूटा और हमें भी बातचीत की मेज पर अपनी बात जोरदार तरीके से रखने का अवसर हासिल हुआ। चार सालों की सघन बातचीत के बाद आमने-सामने जमे सैनिक वापस लौट गए हैं, लेकिन संबंध में खटास कायम है। इस झड़प ने कूटनीति और राजनय के तरीकों पर भी असर डाला। पहले ऐसे संघर्षों को सुलझाने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की हुआ करती थी। इस बार दोनों तरफ से सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। इस प्रक्रिया से निष्कर्ष तक पहुंचने में देर भले ही लगी हो, परंतु सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सैनिकों से अधिक संवेदनशील कोई और नहीं हो सकता।

मुझे यकीन है कि भारतीय जनरल साहिबान ने सोच-समझकर ही फैसला किया होगा।

बीजिंग का सत्ता-सदन हमारे बारे में क्या सोचता है, इसकी एक झलक पिछले महीने भारत-पाक संघर्ष के दौरान पुनः दिखाई दी। इस दौरान चीन ने खुल्लमखुल्ला पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान के बाद से उसने पाकिस्तान को न केवल घातक हथियार दिए हैं, बल्कि पाक अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया है। कुछ लोग मानते हैं कि लद्दाख और पूर्वोत्तर स्थित पीएलए के 'सैनिक थिएटर्स' में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की भी आमदरफ्त है।

गलवान की इस बरसी और पाकिस्तान से हुए संघर्ष की सीख क्या है?

यही कि हमें पाक और चीनी सीमाओं पर एक साथ जंग लड़ने की मुकम्मल तैयारी करनी होगी। युद्ध-नीति का पुराना सिद्धांत है, जंग लड़नी हो, तो शत्रु के मुकाबले हरदम चाक-चौबंद रहना होगा। रूस-यूक्रेन, गाजा-इजरायल व इजरायल-ईरान के संघर्षों के बीच दुनिया तेजी से बदल गई है और ऐसे में इस पर अमल करना निहायत जरूरी है। किंवदंती बन चुके चीन के महान सैन्यशास्त्री सून जू ने ठीक कहा था- 'विजेता समर में उतरने से पहले ही जंग जीत चुके होते हैं, जबकि पराजित योद्धा युद्धक्षेत्र में लड़ाई जीतने की कोशिश करते हैं।'

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

इजरायल-ईरान युद्ध भड़का तो भुगतेगा पूरा एशिया

आज से मस्कट में ईरान-अमेरिका परमाणु-वार्ता का छठा दौर शुरू होने वाला था, लेकिन तेहरान ने शनिवार को ही इस वार्ता को बेमानी बता दिया। इस टकराव में इजरायल के पीछे अमेरिका है, तो ईरान के पीछे रूस और चीन खड़े हैं, यानी महाशक्तियों का छद्म युद्ध शुरू हो चुका है।

जी जी द्विवेदी | मेजर जनरल (रिटायर्ड) एवं प्रोफेसर

शुक्रवार की सुबह इजरायली सेना ने जिस तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को अपना निशाना बनाया और बैलिस्टिक मिसाइलों व हवाई सुरक्षा के केंद्रों पर हमले किए, उसके बाद तो यह तय था कि ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले होंगे और रात ढलते-ढलते ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछारें कर दीं। हालांकि, ज्यादातर हमलों को इजरायली सुरक्षा तंत्र ने नाकाम कर दिया, मगर कई मिसाइलें अपने लक्ष्य पर गिरीं, जिनसे शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक तीन की मौत और 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है।

सवाल उठता है कि हमले की यह नौबत आई ही क्यों? दरअसल, अमेरिका और इजरायल को यह यकीन हो चला था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचता जा रहा है और उसके पास जितनी सामग्री है, उसे देखते हुए वह कुछ ही दिनों में कम से कम 15 बम बना सकता है। इजरायल काफी लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पैनी नजर रखता आ रहा है, क्योंकि वह जानता है कि यदि एक बार तेहरान के हाथ यह जन-संहारक हथियार लग गया, तो उसके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार इस चुनौती का सार्वजनिक इजहार कर चुके हैं। इजरायल की यह पुरानी रणनीति है कि खतरा महसूस हो, तो दुश्मन को मजबूत होने से पहले ही नख-दंतहीन कर दिया जाए।

वैसे भी, हरेक सैन्य कार्रवाई के दो लक्ष्य होते हैं- सैन्य और राजनीतिक। इजरायल के हमले का लक्ष्य था- ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना और अपने इस उद्देश्य में वह काफी हद तक कामयाब हो गया है। खुद ईरान के प्रवक्ता ने फोर्डो परमाणु केंद्र के नुकसान की बात मानी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निदेशक राफेल ग्रोसी ने भी पुष्टि की है कि तेहरान ने उन्हें फोर्डो के अलावा नतांज और एसफहान परमाणु केंद्रों के आस-पास भी हमले की सूचना दी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा नुकसान पहुंचा है। शनिवार दिन भर ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमलों की सूचनाएं आती रहीं।

शनिवार दोपहर को इजरायल ने अपनी कार्रवाई में मारे गए ईरान के नौ परमाणु वैज्ञानिकों की बाकायदा सूची जारी की, तो वहीं तेहरान ने अपने दो शीर्ष सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की बात मानी। उसने इजरायली हमलों में 100 से अधिक ईरानी नागरिकों के मारे जाने का भी आरोप जड़ा। जाहिर है, ऐसी सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय असर पड़ता है। चूंकि क्षेत्रीय व मजहबी राजनीति में अरब के कई देश ईरान के विरोधी रहे हैं, इसलिए तेहरान चाहेगा कि वह इन आंकड़ों के सहारे दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में लामबंद कर सके। अब इस कोशिश में वह कितना कामयाब होगा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर अरब देश अभी तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। वे ईरान का समर्थन नहीं कर रहे, तो उसका विरोध भी नहीं कर रहे।

निस्संदेह, नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान गाजा नहीं है और उसे धकेलना आसान नहीं होगा। लगभग नौ करोड़ की आबादी के साथ ईरान के पास 10 लाख की एक बड़ी फौज है। फिर उसकी अर्थव्यवस्था और कूटनीति को तेल भंडारों का बड़ा सहारा हासिल है। यही नहीं, उसके पास सेजिल और इमाद ऐसी मिसाइलें हैं, जो 2,500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इस दायरे में पूरा इजरायल आ जाता है। ईरान को तीन दुर्दांत आतंकी संगठनों हमास, हूती और हिज्बुल्ला का भी पूरा साथ हासिल है।

इसीलिए ईरान पर इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू ने न सिर्फ दुनिया के मित्र शासनाध्यक्षों को फोन करके इस लक्षित कार्रवाई की जानकारी दी, बल्कि उन्होंने ईरान के लोगों से भी अपील की कि वे अपने तानाशाह निजाम को उखाड़ फेंकें, जो दशकों से उन्हें बंधक बनाए हुए है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का नाम लेकर कहा है कि अब अगर ईरान ने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया, तो तेहरान के लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेहरान जलेगा। तेल अवीव ने स्पष्ट कर दिया कि लक्ष्य हासिल करने तक वह चैन से नहीं बैठेगा।

साफ है, जो हालात दिख रहे हैं, उनमें इस टकराव के जल्दी थमने के आसार नहीं दिख रहे। ईरान ने पश्चिमी गठबंधन के देशों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी देश इजरायल पर ईरानी हमलों को विफल करने में शामिल हुआ, तो फारस की खाड़ी और लाल सागर में तैनात उसके नौसैनिक जहाज और इस क्षेत्र के उसके सारे ठिकाने ईरानी प्रतिक्रिया की जद में होंगे। आज से मस्कट में ईरान-अमेरिका परमाणु-वार्ता का छठा दौर शुरू होने वाला था, लेकिन तेहरान ने शनिवार को इस वार्ता को बेमानी बता दिया। बताने की जरूरत नहीं कि इस टकराव में इजरायल के पीछे अमेरिका है, तो ईरान के पीछे रूस और चीन खड़े हैं, यानी महाशक्तियों का छद्म युद्ध शुरू हो चुका है।

बहरहाल, दो देशों के बीच संघर्षों या युद्धों की सफलता अब बहुत हद तक वायु सेना की क्षमता पर निर्भर करती है। इस मोर्चे पर इजरायल ईरान से काफी मजबूत स्थिति में है, फिर उसे अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली का भी भरपूर सहयोग हासिल है। इसलिए एक-दूसरे पर जवाबी हमले का यह दौर यदि लंबा खिंचा, तो ईरान को अधिक दुश्वारियां पेश आएंगी। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक-ऊर्जा संबंध हैं, तो इजरायल हमारा भरोसेमंद साथी है, जिसके साथ हमारे कई रक्षा समझौते हैं, बल्कि दोनों देश आर्थिक सहयोग की कई परियोजनाओं पर साथ काम कर रहे हैं।

भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी शांतिकामी देश यही कामना करेगा कि इस टकराव का जल्द से जल्द अंत हो, खासकर एशिया की तरक्की के लिए यह बहुत जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

वो लम्हा

सी डोनाल्ड बेटमैन
विमानन वैज्ञानिक

विमान दुर्घटना का एक विरल गवाह

वह बालक खुद को रोक न सका, जैसे ही स्कूल में दूसरी घंटी बजी, वह अपने एक साथी के साथ कक्षा से निकल भागा। दोनों बच्चे ऐसे दौड़े, मानो उड़कर पहुंच जाना चाहते हों। यह उम्र ही ऐसी होती है, मन जहाज से भी तेज उड़ता है। कुछ ही देर में दोनों बच्चे दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच गए।

तब द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था। विध्वंस की दर्दनाक खबरों से अखबार सने रहते थे। हवाई जहाजों का इस्तेमाल सफर के लिए कम और युद्ध के लिए ज्यादा हो रहा था। कनाडा में भी अक्सर आसमान से यान तेजी से गुजरते थे और कोलाहल गूंज उठता था। एक दिन ऐसा ही कोलाहल गुजर रहा था, पर तभी बहुत तेज धमाके के साथ सेना के दो विमान टकरा गए थे, उनका मलबा जमीन पर आ गिरा था। फिर क्या था, देखने वालों का तमाशा लग गया। जिसे देखो, वही देखने दौड़ा जा रहा था।

पास ही चल रहे स्कूल में एक बच्चे का मन भी मचल उठा। पता नहीं, पास से विमान कैसा दिखता है और उसमें भी आपस में टकराए विमान कैसे दिखते हैं? वह आठ वर्षीय बालक खुद को रोक न सका, जैसे ही स्कूल में दूसरी घंटी बजी, उसे मौका मिल गया, वह अपने एक साथी के साथ चुपचाप कक्षा से निकल भागा। दोनों बच्चे ऐसे दौड़े, मानो उड़कर पहुंच जाना चाहते हों। यह उम्र ही ऐसी होती है, मन जहाज से भी तेज उड़ता है। कुछ ही देर में दोनों बच्चे दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच गए थे। दुर्गंध का आलम था। विमान के टुकड़े दूर-दूर तक फैले थे और कुछ अधजले हिस्से सुलग रहे थे। वह बालक हादसे के मंजर को देर तक निहारता रहा। दिलो-दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे, पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि विमान आखिर आपस में क्यों टकरा गए? क्या उन्हें आपस में टकराने से रोकने के प्रबंध नहीं थे?

वहां जमा लोगों की बातों को भी वह बालक ध्यान से सुन रहा था, पर लोगों के बीच चर्चा सामान्य किस्म की थी। लोग बस यही सुनने-सुनाने में लगे थे कि किसने क्या देखा, कैसे देखा? कोई तो बस यही बताने में लगा था कि दुर्घटना के समय वह क्या कर रहा था? बहरहाल, लोगों के आम सवालों से अलग उस बालक को सिर्फ यही खास सवाल मथ रहा था कि विमानों की ऐसी दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है? इसी सवाल से परेशान वह स्कूल पहुंचा था। तीसरी घंटी बजी ही थी और वह धीरे से कक्षा में घुस रहा था, पर शिक्षक ने पकड़ लिया। शिक्षक ने डांटते हुए कहा कि स्कूल से ऐसे भागने की वजह से तुम्हें दंड मिलेगा। बालक ने कहा, सर, आप दंड देंगे, तो दंड मैं कुछ दिन बाद भूल जाऊंगा, पर विमान दुर्घटना हमेशा याद रहेगी।

शिक्षक समझदार थे और शायद उनके भी मन में इच्छा थी कि काश, कक्षा लेने का झमेला न होता, तो वह भी स्कूल से भागकर दुर्घटना को करीब से देख आते। ऐसे में, चतुर शिक्षक ने बालक को दंड सुनाते हुए कहा, तुम्हारे लिए दंड यही है कि जो तुम वहां देखकर आए हो, उसे कागज पर लिखकर दिखाओ।

बालक ने जो देखा था, उसे खूब मन लगाकर लिख डाला। हादसे की दास्तान लिखते हुए भी उसे यही सवाल मथता रहा कि क्या उन्हें टकराने या दुर्घटना से रोका जा सकता था? पहले देखना और उसके बाद उसे लिखना, दोनों ही दिलो-दिमाग में बस गए। मन ही मन में उसने ठान लिया कि वह ऐसा यंत्र विकसित करेगा, जिससे विमान दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

अपने सपने के अनुरूप उसने बड़े होकर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और एक विमानन कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ही वर्षों में विमानन उद्योग में उनकी पहचान बन गई। लोग जानने लगे कि सी डोनाल्ड बेटमैन नाम के एक इंजीनियर हैं, जिनका मकसद ही विमानन क्षेत्र को सुरक्षित बनाना है। फ्लाइट सेफ्टी के अनेक यंत्र और उपाय वह लगातार विकसित करते चले गए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कामयाबी 1960 के दशक के अंत में मूल ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम (जीपीडब्ल्यूएस) के आविष्कार के साथ दुनिया के सामने आई। यह तकनीक पायलट को किसी सामने आने वाली चीज से टकराने से पहले ही सचेत कर देती है और बचने-संभलने का मौका देती है।

विमान क्षेत्र प्रणाली, हेड-अप डिस्प्ले, गति नियंत्रण, स्टॉल चेतावनी प्रणाली, स्वचालित विमान उड़ान नियंत्रण प्रणाली और वजन-संतुलन प्रणाली से संबंधित 40 से अधिक अमेरिकी व 80 विदेशी पेटेंट के मालिक बेटमैन को सुरक्षित विमान सेवा का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। बेटमैन किसी भी आविष्कार के बाद रुके नहीं, आविष्कार की गुणवत्ता सुधारने में लगे रहे।

दुनिया में कहीं भी कोई विमान दुर्घटना होती थी, तो बेटमैन (1932-2023) बारीक से बारीक सूचनाएं दर्ज करते थे और समाधान सोचते थे। विमानों की दुनिया में सर्वाधिक लोगों की जान बचाने का श्रेय वैज्ञानिक बेटमैन को दिया जाता है। आज दुनिया में कहीं कोई दुर्घटना होती है, तो अनायास बेटमैन याद आते हैं और लगता है कि वह होते, तो दुर्घटना का गहराई से अध्ययन करके कोई न कोई बचाव यंत्र जरूर बनाते।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

साहित्य मन माने की बात

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

हिंदी में कुछ भी हो सकता है। यहां दो लाइन लिखने वाला भी बड़ा लेखक कहलाता है, पूरी किताब लिखने वाला भी बड़ा लेखक कहलाता है और दो-चार या दस-बीस किताबें लिखने वाला भी बड़ा लेखक कहलाता है। और तो और, संकलनकर्ता भी बड़ा लेखक कहलाता है। इसीलिए हिंदी में सभी लेखक बड़े लेखक कहलाते हैं, यहां कोई लेखक छोटा नहीं होता।

ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हिंदी में बड़े का न कोई फिक्स मानक है, न कोई तयशुदा पैमाना। यह हिंदी का जनतंत्र है, समाजवाद है और उससे भी आगे का साम्यवाद! यहां न छपने वाला, छपकर भी न बिकने वाला बड़ा लेखक है और हजारों में बिकने वाला भी बड़ा लेखक है। एक कविता लिखने वाला भी वरिष्ठ कवि है और दर्जनों संग्रह लिखने वाला भी। आप एक कहानी के लेखक हैं, तब भी प्रेमचंद, गोर्की, मोपासां, ओ हेनरी, चेखव से आगे के लेखक हैं। आपने एक उपन्यास लिखा है, तब भी उपन्यास सम्राट हैं, दस लिखे हैं, तो भी उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट और आख्यान सम्राट हैं।

हिंदी में इन दिनों आप कुछ भी हो सकते हैं। आपके आगे प्रेमचंद भी पानी भरते हैं। आप ही कथा गुरु हैं, आप ही सबसे बड़े किस्सागो। आप ही *कथासरित्सागर* हैं, आप ही *तिलिस्म-ए-होशरुबा* हैं, आप ही अलिफ लैला की कहानी हैं, साहित्य के असली मानक हैं।

हिंदी में इतनी प्रतिभाएं बरस रही हैं कि संभाले से भी नहीं संभल पा रहीं! साहित्य के मानकों को तय करने वाले आलोचकों की सारी सीटें खाली पड़ी हैं। यह रही शुक्ला जी वाली सीट, वह रही रामविलास जी वाली सीट, यह खाली पड़ी है नामवर जी वाली सीट- सभी आपके इंतजार में हैं। आपके लिए तरस रही हैं। आप बस कृपा करें। जिस पर भी चाहें, तशरीफ रखें, सारी सीटें आपकी हैं, आप ही के लिए बनी हैं।

हिंदी का सब कुछ आपके हाथ है। आप ही हिंदी साहित्य के मालिक हैं। ट्रस्टी हैं। आप ही अखिल हिंदी साहित्य के परमानेंट अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, बीज वक्ता, टीज वक्ता, खीज वक्ता और लीज वक्ता हैं। आप ही बेस्ट सेलर हैं। आप सीजन के 'टॉप टेन' में से एक हैं। आप लिखें न लिखें, बिकें न बिकें, साहित्य में टिकें न टिकें, लेकिन पूरे आत्म-विश्वास से घोषित कर सकते हैं कि आप ही इस वक्त के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक हैं। आप ही 'ट्रेंड सेटर' हैं। आपके ऐसे दावों का प्रमाण मांगने वाला कोई नहीं। हिंदी में आप अपने बारे में जो चाहे, हांक सकते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकते हैं।

अगर कोई सत्यवादी आपसे पूछ ही ले कि आपके दावे का आधार क्या है? आपको 'बेस्ट सेलर' बताने वाला डाटा कहां है? किसने तैयार किया है? अगर आप टॉप के हैं, तो 'रॉयल्टी' कितनी मिलती है? आपका बैंक बैलेंस क्या है? प्रकाशक का डाटा क्या है? जब आपने इतना कमाया, तो प्रकाशक ने कितना कमाया? अगर आप ऐसे फालतू के सवाल करते हैं, तो आप उस लेखक से ईर्ष्या करते हैं और उसके दुश्मन हैं। आप उसकी कीर्ति से जलते हैं।

अपना हिंदी साहित्य ऐसा ही है। इतने आलोचक हो गए, इतनी आलोचना हो गई, लेकिन साहित्य के कोई पक्के मानक नहीं बने। पश्चिम में बेस्ट सेलर्स का कोई मान्य मानक भले हो, हिंदी में नहीं है, न हो सकता है, क्योंकि यहां अब भी यही माना जाता है कि साहित्य को एक डाटा में 'रिड्यूस' नहीं किया जा सकता। वह तो एक भाव है, विचार है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति है। इस भाव और विचार का कोई भाव नहीं लगाया जा सकता!

साहित्य तो होता ही निजी (सब्जेक्टिव) है, तो मानक भी सब्जेक्टिव होंगे। अपने गोस्वामी जी कह गए हैं, *निज कवित्त केहि लाग न नीका! सरस होउ अथवा अति फीका!* साहित्य इसी भाव से बनता है। *भ्रमरगीत* में गोपियां उद्धव से कहती हैं- *उधो मन माने की बात*, इसी तर्ज पर कहा जा सकता है, 'साहित्य मन माने की बात'!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

मोदी सरकार में गिरती महंगाई

देश में महंगाई के स्तर को लेकर पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी दल जिस प्रकार का सरकार विरोधी विमर्श खड़ा करते रहे हैं उसे महंगाई के ताजा आंकड़ों ने निर्मूल साबित कर दिया है। इसका मतलब यह निकलता है कि देश की अर्थव्यवस्था सही पटरी पर चल रही है और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की मांग यथा पूर्व रहने के बावजूद महंगाई नहीं बढ़ रही है। खुदरा वस्तुओं के महंगाई स्तर का विगत मई महीने में 2.82 प्रतिशत रहने का अर्थ यह है कि गरीब आदमी की पहुंच से खाद्य वस्तुएं दूर नहीं हुई हैं और वह अपना जीवन-यापन अपेक्षाकृत सुविधाजनक तरीके से कर रहा है। बाजार में खाद्य वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं जो यह बताता है कि मांग व आपूर्ति में संयम भी बना हुआ है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में महंगाई के स्तर के घटने के बहुआयामी अर्थ होते हैं। इससे बैंक की ब्याज दरों पर भी असर पड़ता है और बहुमूल्य धातु सोने के दामों पर भी असर पड़ता है। भारत में बैंक की ब्याज दरों में पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने कमी की है जो कि इसी अपेक्षा पर आधारित थी कि महंगाई की दरों में कमी आयेगी। रिजर्व बैंक पिछले एक साल में एक प्रतिशत के लगभग ब्याज दरें घटा चुका है जिसका असर व्यापक तौर पर पड़ता है खासकर बैंकों से लिये गये ऋण पर कम ब्याज देना पड़ता है। मई महीने में मुद्रा स्फीति की दर 2.82 प्रतिशत रही है। यह दर पिछले छह वर्षों में सर्वाधिक कम है। यह दर आर्थिक विशेषज्ञों की अपेक्षा से भी कम रही है क्योंकि विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई की दर तीन प्रतिशत के आसपास रहेगी।

आमतौर पर विकसित देशों में महंगाई की दर दो से तीन प्रतिशत के बीच रहती है परन्तु भारत जैसे विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश में यह दर रहना बताता है कि अर्थव्यवस्था के मानक वर्तमान विश्व आर्थिक परिदृष्य में अपने उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। भारत में विकास वृद्धि की दर छह प्रतिशत से ऊंची आंकी जा रही है जो सकल विश्व के विकसित व विकासशील देशों के मुकाबले उच्च स्तर पर है। मगर इससे यह भी पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों से विरोधी राजनैतिक दल जिस तरह सरकार के विरुद्ध महंगाई के बढ़ते स्तर को लेकर मुहीम चला रहे थे वह हकीकत से दूर थी।

आमतौर पर विकसित देशों में महंगाई की दर दो से तीन प्रतिशत के बीच रहती है परन्तु भारत जैसे विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश में यह दर रहना बताता है कि अर्थव्यवस्था के मानक वर्तमान विश्व आर्थिक परिदृष्य में अपने उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। भारत में विकास वृद्धि की दर छह प्रतिशत से ऊंची आंकी जा रही है जो सकल विश्व के विकसित व विकासशील देशों के मुकाबले उच्च स्तर पर है। मगर इससे यह भी पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों से विरोधी राजनैतिक दल जिस तरह सरकार के विरुद्ध महंगाई के बढ़ते स्तर को लेकर मुहीम चला रहे थे वह हकीकत से दूर थी। पिछले छह वर्षों में 2019 से लेकर अब तक मई महीने में सबसे कम 2.82 प्रतिशत महंगाई रहने का मतलब है कि राजनैतिक दलों की मुहीम तथ्यों के मुकाबले राजनीति से ज्यादा प्रेरित थी। खास कर चुनावों के मौके पर बढ़ती महंगाई को एक मुद्दा बनाया जाता था। जबकि सभी जानते हैं कि चुनावों के अवसर पर बाजार में रोकड़ा धन की आवक अधिक होने से उसका असर खाद्य वस्तुओं के दामों पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

2024 में हुए लोकसभा चुनाव के अवसर पर यह महंगाई दर चार प्रतिशत के आसपास थी। मगर इसके बाद सरकार ने इस तरफ कड़े कदम उठाये जिनका परिणाम सकारात्मक रहा। फरवरी 2019 में महंगाई की दर मौजूदा 2.82% के करीब रही थी। इसके बाद इसमें इजाफा होता रहा और बीच में यह 5 प्रतिशत से भी ऊपर निकल गई मगर इस मोर्चे पर सरकार सदैव सतर्क रही और उसने बाजार में माल की सप्लाई में कमी नहीं होने दी। हालांकि कई मौकों पर सरकार के सामने माल की आवक कम होने के अवसर भी आये। इसके बावजूद सरकार ने सप्लाई के संरक्षणात्मक ढांचे को सक्रिय करके यह कमी पूरी करने के प्रयास किये। विगत अप्रैल महीने में थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.2% के करीब था। बाजार में माल की प्रचुर मात्रा होने की वजह से खुदरा बाजार में वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ सके। अब अर्थ शास्त्री यह कयास लगा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में महंगाई और भी ज्यादा कम होगी। खास तौर पर अक्तूबर महीने तक इसमें नीचे गिरने का क्रम बना रहेगा। इसी महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अत: बिहार जैसे गरीब राज्य में सत्ताधारी दलों भाजपा व जनता दल (यू) को इस मोर्चे पर राहत मिल सकती है और विपक्ष महंगाई के मोर्चे पर राज्य सरकार को नहीं घेर सकेगा।

बेशक भारत खाद्य तेलों का भारी मिकदार में आयात करता है मगर इस मद में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भावों में नरमी का माहौल बना है और उसका असर घरेलू बाजार पर भी सीधा पड़ा है। खाद्य तेलों के भावों में पिछले कुछ अर्से से नरमी देखी जा रही है। यही हालत दालों व अन्य साग-सब्जियों के भावों को लेकर भी बनी हुई है। अब वर्षा ऋतु का प्रारम्भ होने वाला है और देखना होगा कि मानसून किस प्रकार का रहता है क्योंकि खरीफ की फसल की बुवाई का समय भी निकट है। यदि मानसून बेहतर रहता है तो बाजार पर इसका सकारात्मक असर रहेगा और महंगाई दबी रहेगी। मोदी सरकार के लिए वर्तमान वर्ष 2025 शुभ कहा जायेगा क्योंकि इस वर्ष में इसे न केवल चुनावी सफलता मिली है बल्कि महंगाई के मोर्चे पर भी इसका हाथ ऊपर रहा है।

इन हादसों की आखिर किस...

गीता पाढा

चारों तरफ सिसकियां और दुख भरी किलकारी है,
इस विमान हादसे ने छीन ली जिदंगियां कितनी सारी हैं,
इन हादसों की आखिर किस पर जिम्मेदारी है,
उन झुलसे शरीरों से लाशें पहचान में नहीं आ रही हैं!!

ट्रम्प को कब जवाब देगी सरकार

नई दिल्ली, (भाषा): कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा पिछले 34 दिनों में 13 बार किया है, लेकिन सरकार इस बारे में कब बोलेगी।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आज राष्ट्रपति ट्रंप 79 साल के हो गए हैं। 10 मई, 2025 और 13 जून, 2025 के बीच 34 दिनों में, उन्होंने तीन अलग-अलग देशों में 13 अलग-अलग मौकों पर सार्वजनिक रूप से ढिंढोरा पीटा कि उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार के मुद्दे का उपयोग करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है। निस्संदेह, उन्होंने दोनों देशों की समान रूप से प्रशंसा की।'' उन्होंने सवाल किया, ''सरकार कब बोलेगी?'' भारतीय सशस्त्र बलों ने छह मई की देर रात 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था।

काम से काम रखते नड्डा

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

भाजपा शासित एक प्रमुख राज्य के एक नामचीन नेता जी भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। आदत के मुताबिक नड्डा उनसे बेहद गर्मजोशी से मिले, आवभगत की, चाय-नाश्ता कराया और फिर आने का सबब पूछा। तब उस भगवा क्षत्रप ने नड्डा से कहा जैसा कि

'आप देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में किस कदर उठा-पटक चल रही है, एक-दूसरे के पैर खींचे जा रहे हैं, इससे बेहतर तो यह होगा कि मैं केंद्र की यानी कि दिल्ली की राजनीति करूं। सो, संभव हो तो इस बार मुझे आप पार्टी के केंद्रीय संगठन में एडजस्ट कर दें।' नेता जी की पूरी बात सुनने के बाद नड्डा ने उनसे बेहद विनम्रता से कहा-नया अध्यक्ष आने दीजिए, फिर ही कुछ हो सकता है।

ममता का अल्पसंख्यक प्रेम उफान पर

ममता बनर्जी सियासत की माहिर खिलाड़ी हैं, उन्हें भलीभांति इस बात का इल्म है कि अपने कोर वोट बैंक को कैसे विरोधियों की नाक तले एकजुट रखना है। भले ही बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी हो, पर ममता ने सियासी बिसात पर शह-मात की नई रणनीति बुननी शुरू कर दी है। सबको, खास कर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को चौंकाते हुए ममता ने 10 जून को विधानसभा पटल पर ओबीसी-ए और ओबीसी-बी नामजद कर पिछड़ी जातियों की नई सूची सामने रख दी, इन सूचियों में 76 नई जातियों को जोड़ा गया है, इसे मिला कर ओबीसी सूची में कुल जातियों की संख्या अब 140 तक पहुंच गई है।

बीजेपी शुरूआत से ही ममता प्रायोजित इन सूचियों का विरोध करती आई है, क्योंकि इन 140 में से जातियों के 80 तो सिर्फ मुस्लिम समूहों से जुड़े हैं। हालांकि बीते वर्ष जब यह मामला

कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचा था तो कोर्ट ने इस सूची में से 113 जातियों को बाहर कर दिया था, तब सूची में सिर्फ 66 जातियां रह गई थीं। पर अब ममता सरकार ने कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए हटाई गई 113 जातियों में से 76 को फिर से इस सूची में जोड़ दिया है जिससे कि यह सूची 66 से बढ़ कर अब 140 जातियों की हो गई है। इन 76 नई जातियों में 51 ओबीसी-ए (अति पिछड़ा) और 25 नाम ओबीसी-बी सूची से संबंद्ध कर दिए गए हैं। खूब हो-हल्ला मचने के बाद यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां अगले महीने इस मामले पर सुनवाई होनी है। भाजपा का आरोप है कि ममता यह सारी कसरत बस एक खास धर्म को खुश करने के लिए कर रही हैं, जो उनका कोर वोट बैंक भी है।

बिहार चुनाव हंग असेम्बली की ओर?

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है, सो चाहे संसाधन हो, टीम मैनेजमेंट या जमीनी स्तर की तैयारियां भगवा पार्टी फिलवक्त सबसे आगे बनी हुई है, पर जहां तक चुनावी नतीजों की बात है वहां संशय अब भी बरकरार है। पिछले दिनों भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वहां के अपने एक व्यवसायी नेता को चुनाव पूर्व सर्वेक्षण की एक महती जिम्मेदारी सौंपी, माना जाता है कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर इस कंपनी की ओर से एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण करवाया गया, सूत्रों की मानें तो अकेले इस सर्वे

का खर्च साढ़े छह से सात करोड़ रुपयों के बीच आया। पर इस सर्वे के नतीजों से भगवा पेशानियों पर बल पड़ गए हैं।

सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि भले ही बिहार के शहरी इलाकों में भाजपा का ग्राफ अच्छा दिख रहा है, पर ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में एनडीए गठबंधन को राजद, कांग्रेस व माले से कड़ी टक्कर मिल रही है, यहां मुकाबला लगभग बराबरी का है। सर्वे रिपोर्ट जदयू के संभावित प्रदर्शन पर भी सवालिया निशान लगा रही है और कह रही है कि नीतीश के अपने कोर वोटर ही उससे छिटक रहे हैं, यहां तक कि इस बार राज्य की महिला वोटरों में भी जदयू व नीतीश को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा। वहीं एनडीए में शामिल छोटे-छोटे दल जैसे मांझी की हम, या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मंच भी कोई खासा उम्मीद नहीं जगा पा रही। सो, इस सर्वे रिपोर्ट में दावा हुआ है कि इस दफे बिहार में हंग असेम्बली आ सकती है।

नई रोशनी की तलाश में चिराग

बिहार चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के मुखिया चिराग पासवान की तैयारियां देखते ही बनती हैं। उनके एक करीबी नेता का दावा है कि इस चुनाव में चिराग अपना सर्वस्व झोंकने की तैयारी में हैं, चुनाव लड़ने के लिए काफी पहले से पैसा जुटाया जा रहा है, सूत्रों का दावा है कि अकेले चिराग का चुनावी बजट 200 करोड़ रुपयों के आसपास का हो सकता है, जिसमें से 20-25 करोड़ रुपए तो उनके मीडिया मैनेजमेंट पर खर्च हो सकता है।

चिराग अपनी पार्टी के कम से कम 40 से 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियों में हैं, सूत्र बताते हैं कि उनके हर कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अपनी ओर से 3 करोड़ रुपयों का फंड दे सकती है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चिराग दूध के जले हैं, इस बार वे छाछ भी फूंक-फूंक कर पी रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका मकसद भले ही नीतीश की सीटें कम करने का रहा हो, पर

इस चक्कर में वे अपनी जंग भी हार गए थे, उनका एकमात्र उम्मीदवार ही तब चुनाव जीत पाया था जबकि उन्होंने 137 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस बार पवन वर्मा ने उनकी मुलाकात नीतीश से करवा दी, नीतीश ने चिराग को भरोसा दिलाया है कि इस बार दोनों एक-दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे। सो, नीतीश भी चाहते हैं कि चिराग कम से कम 40 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। मांझी व कुशवाहा के लिए भी भाजपा 10-10 सीटें छोड़े और खुद भगवा पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ें। पर भाजपा को नीतीश का यह फार्मूला फिलहाल स्वीकार्य नहीं।

...और अंत में

सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए विदेश जाने वाला था तो देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम राहुल गांधी के खासमखास गौरव गोगोई से मिले थे और उनके समक्ष यह दुखड़ा रोया था कि 'राहुल ने जो कांग्रेस सांसदों की लिस्ट पीएम मोदी को भेजी थी उसमें न तो उनका यानी कि कार्ति का (जो कि एक लोकसभा सांसद हैं) और ना ही उनके पिता पी. चिदंबरम (राज्यसभा सांसद) के नाम शामिल हैं।'

इस पर गौरव ने कार्ति को समझाते हुए कहा कि 'पीएम ने कौन सी राहुल जी की लिस्ट पिक कर ली, राहुल जी ने कहां शशि थरूर या मनीष तिवारी जैसों के नाम भेजे थे? उन्हें जिन्हें चुनना होता है मोदी 'आउट ऑफ वे' जाकर उनका चुनाव कर लेते हैं, सो प्लीज ऐसे में राहुल जी को दोष देना बंद कर करिये।'

दुर्घटनाग्रस्त विमान के इंजन में अहम समय के दौरान ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई थी : अरूप राहा

कोलकाता, (पंजाब केसरी): पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा (सेवानिवृत्त) ने शनिवार को दावा किया कि 12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुए एअर इंडिया के विमान के इंजन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चरण में ऊर्जा बाधित हो गई थी और उसे ठीक करने का कोई समय नहीं था। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे ईंधन में मिलावट, तथा सॉफ्टवेयर और नियंत्रण प्रणालियों में गड़बड़ी।

राहा ने कुछ लोगों द्वारा जताई गई तोड़फोड़ की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि सभी तरह की अटकलों से बचना चाहिए और नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए।

अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रही एअर इंडिया की उड़ान एआई171 गुरुवार को सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर की इमारतों से टकरा गया, जिससे विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई, तथा जमीन पर भी कई अन्य

लोग मारे गए।

पूर्व वायुसेना प्रमुख ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका पर आईसीसी के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ''यह बहुत दुखद और हृदय विदारक है। इतने सारे लोग एक साथ मारे गए। अभी यह कहना बहुत मुश्किल है कि क्या गलत हुआ है।''

उन्होंने कहा, ''निश्चित रूप से ऊर्जा में कमी आई और एक महत्वपूर्ण चरण में... आप जमीन से हवा में उड़ रहे हैं, आपकी ऊंचाई कम है। संभलने का कोई समय नहीं था। और इंजन की शक्ति में कमी के परिणामस्वरूप विमान रुक जाएगा... (विमान) फिर बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। और यही हुआ था।''

वायुसेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के इंजन 'धकेलते' हैं और एक साथ दोनों इंजनों की ऊर्जा बाधित होना बहुत दुर्लभ है - ''शायद एक अरब मामलों में एक''।

राहा ने कहा कि यह कहना कठिन है कि कहां गलती हुई। उन्होंने अन्य संभावनाओं के बारे में भी बात की। राहा ने कहा-सॉफ्टवेयर में कोई समस्या हो सकती है, नियंत्रण (प्रणाली) में कुछ समस्या हो सकती है, ईंधन में संदूषण हो सकता है... लेकिन मैं तोड़फोड़ की बात पर विश्वास नहीं करता। ऊर्जा आपूर्ति बंद हो जाना किसी गड़बड़ी का संकेत है। उन्होंने कहा-जब तक डीजीसीए और सरकार की अन्य एजेंसियां जांच पूरी नहीं कर लेतीं, हमें कोई बेबुनियाद दावा नहीं करना चाहिए।

वायुसेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बोइंग 787-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण पक्षी का टकराना हो सकता है। राहा ने कहा, ''उनकी अपनी ही कंपनी के व्हिसलब्लोअर द्वारा शिकायतें की गई थीं। मुझे लगता है कि उनकी जांच होनी चाहिए।'' इससे पहले आईसीसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विमान इंजन का निर्माण देश में ही करने की वकालत की।

मुंबई से सीधी उड़ान न मिलने पर अहमदाबाद के रास्ते ब्रिटेन जाने का फैसला परिवार पर पड़ा भारी

मौत यूं भी बुलाती है...

मुंबई, (पंजाब केसरी): लंदन के एक होटल में प्रबंधक के रूप में काम करने वाले जावेद अली सैयद अपने परिवार के तीन सदस्यों के साथ अपनी बीमार मां से मिलने भारत आए थे लेकिन मुंबई से सीधी उड़ान न मिलने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के रास्ते लंदन जाने का फैसला किया और यह उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई।

मुंबई के मलाड ईस्ट से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश नागरिक जावेद अली, अपनी पत्नी मरियम (35) और दो बच्चों ज़ैन (छह) व अमानी (चार) के साथ एअर इंडिया के उस विमान में सवार थे, जो बृहस्पतिवार दोपहर उड़ान भरने के तुरंत बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीमार मां को देखने के लिए जावेद अपने परिवार के साथ पिछले सप्ताह भारत आये थे। जावेद की मां को दिल की बीमारी है और उनका उपचार यहां जारी है।

जावेद 11 वर्ष पहले ब्रिटेन गए थे, जहां उनकी मुलाकात मरियम से हुई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। उन्होंने बाद में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली और लंदन के केंसिंग्टन में बस गए। मरियम लंदन के मशहूर लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर 'हैरोड्स' में ब्रांड एंबेसडर के तौर पर काम करती थीं, जबकि जावेद बेस्ट वेस्टर्न केंसिंग्टन ओलंपिया होटल का प्रबंधन करते हैं।

जावेद के चचेरे भाई सऊद मेमन ने बताया, "वे (जावेद का परिवार) लंदन में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे।"

जावेद के छोटे भाई इम्तियाज अली ने बताया, "वे अपनी मां का इलाज कराने और परिवार के साथ ईद-उल-अजहा मनाने के लिए यहां आए थे। चूकि उन्हें मुंबई से कोई सीधी उड़ान नहीं मिल पाई, इसलिए वे वापस लंदन जाने के लिए अहमदाबाद चले गए।"

विमान दुर्घटना के बाद, इम्तियाज और उनके चाचा शवों की पहचान करने में अधिकारियों की मदद करने के लिए डीएनए नमूने लेकर अहमदाबाद गये हैं।

इम्तियाज ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद परिवार का भारत लौटना दुखद रहा और उन्हें अहमदाबाद जाने के जावेद के फैसले पर अफसोस है। इम्तियाज के मुताबिक, जब तक उन्हें जावेद और उनके परिवार के सदस्यों के अवशेष नहीं मिल जाते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे।

जलवायु परिवर्तन, बड़ा अलर्ट

अर्जुन चोपड़ा

यह सच है कि आज वैश्विक स्तर पर मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम का पूरी दुनिया में एक साथ बदलाव चिंता पैदा करता है। भारत में इसका असर भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन कृषि और हैल्थ के साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इस जलवायु परिवर्तन के तौर पर भारत में विशेष रूप से पश्चिमी विक्षोम अर्थात् वैस्टर्न डिस्टरबर्टसेंस बनता है, जिस कारण तेज हवाएं, तूफान, बारिश अचानक होने लगती हैं। इसी साल मई महीने में हमने उत्तर भारत विशेष रूप से दिल्ली में इस प्रभाव को देखा और झेला है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े-बड़े जलवायु सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानवीय विकास के तहत पृथ्वी पर प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम घातक निकल रहे हैं। सारा साल जिस अंटार्टिका पर बर्फ जमी रहती है, वह समय से पहले पिघल रही है। दुनिया के नक्शे पर देखो तो जंगल कट रहे हैं। परिणाम सबके सामने हैं। अमेरिका में 20-20 दिन तक जंगलों में आग लगती रही, जिससे तापमान बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के तापमान में वृद्धि हो रही है। सागर का स्तर बढ़ रहा है। मौसम की प्रकृति में असाधारण परिवर्तन किसी अनिष्ठता का संकेत दे रहा है। अत: यह एक अलर्ट है। हमें संभल जाना चाहिए।

वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है जलवायु के मापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे तापमान, वर्षा या हवा, जो लम्बे समय तक - दशकों या उससे अधिक समय तक - बना रहता है। यह एक ऐसा शब्द है जो पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन का वर्णन करता है। पृथ्वी के इतिहास में इसकी जलवायु कई बार बदल चुकी है, जिसमें हिमयुग से लेकर लम्बे समय तक गर्मी की स्थिति जैसी घटनाएं शामिल हैं। इस कड़ी में साक्ष्यों से पता चलता है कि वर्तमान तापमान वृद्धि हिमयुग के बाद होने वाली औसत तापमान वृद्धि की दर से लगभग दस गुना अधिक तेजी से हो रही है। भारत और विश्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुआयामी हैं, जो कई क्षेत्रों और क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रमुख चिंताओं में से एक है खाद्य सुरक्षा। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को जटिल तरीकों से प्रभावित करता है।

जलवायु परिवर्तन फसल की पैदावार को प्रभावित करता है क्योंकि फसल की पैदावार कच्चे माल पर निर्भर करती है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है, जिससे

फसल की वृद्धि और उत्पादकता प्रभावित होती है। इससे कीटों के आक्रमण की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। वर्ष 2100 तक वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री टैम्परेचर की वृद्धि भी वर्तमान कृषि प्रणालियों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। राजस्थान में टिड्डी दल का उल्लेख यहां जरूरी है।

वर्षा में बढ़ती अनिश्चितता के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित सूखे और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से, कृषि योग्य तटरेखाएं जलमग्न हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि भारत में अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित हो जाएगी, जिससे बार-बार सूखा और बाढ़ आएगी। वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, जिससे भारत में मरुस्थलीकरण में भारी वृद्धि होगी। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

भारत में बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि का नुकसान होगा। इसका एक प्रमुख उदाहरण हाल के दशक में जम्मू और कश्मीर में आने वाली लगातार बाढ़ है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य हिमालयी ग्लेशियरों में आई इस बाढ़ का सबसे अधिक खामियाजा भुगतेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बाढ़ आने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परतें नष्ट हो जाएंगी। इससे उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल भोजन का पोषण मूल्य कम होगा, बल्कि ग्रीनहाउस गैसें भी निकलेंगी, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देंगी।

यह भी सच है कि भारत की तटरेखा काफी लम्बी है, जो बढ़ते समुद्री स्तर और जलमग्न तटीय कृषि योग्य भूमि से प्रभावित होगी। इससे भारत की समुद्री खाद्य प्रणाली को भारी नुकसान होगा। वैज्ञानिकों की नजर में जलवायु परिवर्तन से जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और जलीय आवासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे-जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, उसमें जैविक रूप से घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसका असर उसमें रहने वाली समुद्री प्रजातियों पर पड़ता है। वहीं पानी के तापमान में वृद्धि के साथ, रोगजनकों और आक्रामक प्रजातियों में वृद्धि होती है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ की लुप्त होती चट्टानों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सतही जल का तापमान बढ़ने से शैवालों की वृद्धि होती है, जो समुद्री प्रजातियों के जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों पर निर्भर होते हैं।

भारत पर प्रभाव नजर आ रहे हैं। भारतीय जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। पूरे देश में मीठे पानी के संसाधनों में उल्लेखनीय कमी आई है। भारत लगातार गंभीर सूखे और बाढ़ का सामना कर रहा है। हाल के दशक में जम्मू और कश्मीर राज्यों में बाढ़ की अधिकता देखी गई है तथा महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र गंभीर जल संकट और सूखे का सामना कर रहा है। हिमालय के ग्लेशियरों के सिकुड़ने के कारण, बारहमासी नदियाँ अपना मार्ग बदल रही हैं, जिससे बाढ़ आ रही है और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो रहा है। पिघलते ग्लेशियरों के कारण जलविद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। सब जानते हैं कि जब समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ता है, तो वह क्षेत्र की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत को नष्ट करके कृषि को नष्ट कर देता है।

समुद्री जल मिट्टी में लवणता की एक परत भी जोड़ता है, जिससे कृषि करना कठिन हो जाता है। यह भी सत्य है कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने से अंतर्देशीय मीठे जल संसाधनों के लवणीकरण का खतरा बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर भारत और विश्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुत गहरे और बहुआयामी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शमन रणनीतियों, अनुकूलन उपायों और तकनीकी नवाचारों को शामिल करते हुए सबको विचार करना होगा तभी इस बड़े खतरे का सामना किया सकता है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारत में अतिधनाढ्य और आम जनता की आय का अंतर काफी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, पाकिस्तान जैसे उभरते अनेक देशों की तुलना में कम रहा, लेकिन अब वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब के आंकड़ो से पता चलता है कि भारत में असमानता तेजी से बढ़ी है और अब वैसे स्थिति में है जैसी औपनिवेशिक काल में थी। हमें इस रुझान को तत्काल रोकना होगा।
कौशिक बसु, अर्थशास्त्री@kaushikcbasu

अस्थिरता के दौर में सिद्धांत

प्रतिबद्धता

भारत डोगरा

हाल के समय में विश्व में अस्थिरता बहुत बढ़ गई है। विश्व के सबसे जाने-माने अनेक देश और उनके बड़े नेता बहुत अस्थिरता भरा व्यवहार कर रहे हैं। इससे दुनिया में समस्याएं बढ़ रही हैं। इसकी कुछ अन्य देशों पर प्रतिक्रिया यह हो रही है कि स्थितियां देख कर जो अधिक लाभ वाली नीति लगे वही अपना लो। ऐसे दौर में कम ही लोग बचे हैं जो सिद्धांतों और सिद्धांत पर चलने की अधिक बात करें। फिर भी यह जोर देकर कहने की जरूरत है कि अस्थिरता के इस दौर में सही सिद्धांत का चुनाव और इन सिद्धांतों के लिए अपनी प्रतिबद्धता ही सबसे उचित राह है।

अवसरवादी तव तरह-तरह के अनिश्चय और उठापटक में भटकते ही रहेंगे जबकि सही सिद्धांतों के मार्गदर्शन को अपनाने वाले सही अर्थों में प्रगति भी कर सकेंगे और उनका अपने में और अपनी राह में गहरा विश्वास भी बना रहेगा। हमारे देश के मूल सिद्धांत क्या होने चाहिए? हम सही सिद्धांतों का चुनाव कैसे करें? यह सिद्धांत कुछ हद तक हमें अपने संविधान से प्राप्त हुए हैं और कुछ हद तक हमने इतिहास के सबसे प्रेरणादायक पृष्ठों, व्यक्तित्वों और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों से ये सिद्धांत प्राप्त किए हैं। एक बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें अपने देश और समाज में सभी से समान व्यवहार, सम्मान का व्यवहार करना है तथा धर्म, जाति, रंग, नस्ल, क्षेत्रीयता, लिंग आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। हमारे सभी धर्म, सभी जातियां, सभी क्षेत्र और प्रांत एक ही बगीचे के बहुत सुंदर फूल हैं और उन सभी का हमें एक जैसा ख्याल रखना है। किसी से भी न तो अन्याय होना चाहिए और न ही भेदभाव। बात सिर्फ कहने की नहीं है और सिर्फ कानून की नहीं है, हमारी असली सफलता यह होगी कि सभी लोग वास्तव में गहराई से यह अहसास करें कि उनके साथ कोई भेदभाव या अन्याय नहीं है।

हां, इतना जरूर है कि यदि किसी समुदाय से इतिहास के पृष्ठों में अन्याय हुआ है तो, उसे सामाजिक-बराबरी तक पहुंच पाने के अवसर तब तक देने चाहिए जब तक यह समानता प्राप्त नहीं हो जाती है और पूर्ण समाज की गरिमा इसी में है कि इस समानता की स्थिति तक सबकी सहमति से पहुंचा जाए। जिस समाज में सभी को समान अवसर मिलेंगे उसी समाज की प्रतिभाएं सबसे अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसी तरह जिस समाज में महिलाओं को प्रगति के समान और भरपूर अवसर मिलेंगे, वह समाज भी प्रगति में आगे रहेगा।

इस समानता को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष ध्यान यह रखना होगा कि धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, लिंग आदि के आधार पर किसी के विरुद्ध कोई भी हिंसा न हो। सांप्रदायिक, जातिगत और महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समानता को भी निरंतरता से आगे बढ़ाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक समानता एक दूसरे की पूरक हैं। हालांकि आर्थिक विषमताओं को हमें कई स्तरों पर कम करना है, पर एक बड़ी बात यह है कि जो सबसे निर्धन हैं या सबसे कठिन स्थिति के लगभग 15 से 20 प्रतिशत लोग हैं, उनकी स्थिति को शीघ्र से शीघ्र और टिकाऊ तौर पर बेहतर करने के प्रयास पर अधिक ध्यान दिया जाए। दूसरी ओर शीर्ष पर जो सबसे धनी हैं, हमें उनकी समृद्धि से प्रसन्नता है पर किसी को भी अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र पर एकाधिकार और अत्यधिक नियंत्रण की स्थिति पर नहीं आना चाहिए।

मध्यम स्तर के व्यवसायों और छोटे व्यवसायों को प्रगति के बेहतर अवसर मिलने चाहिए। देश और दुनिया की बढ़ती जरूरत है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम निरंतरता से प्रयासरत रहें और इसे अधिक प्राथमिकता प्रदान करें। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी एकता और मिल कर कार्य करने की क्षमता हमें बहुत रचनात्मक और खूबसूरत उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सोच के लिए गहरी प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। समय पर चुनाव करवाने और लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेने मात्र से ही कोई देश या समाज सही अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं हो जाता है, अपितु लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता तो कई स्तरों पर निरंतरता से मजबूत करने की जरूरत है और लोकतांत्रिक भावना को सही अर्थों में अपनाने की जरूरत ऊपरी तंत्र से गांव-गांव तक हर जगह है। लोकतंत्र की मजबूती से ही विश्वास जन-जन में उत्पन्न होता है कि हर तरह की समस्याओं का समाधान अमन-शांति की राह पर संभव है और इस आधार पर ही अमन-शांति के लिए प्रतिबद्धता हर स्तर पर मजबूत होती है जो हिंसा से त्रस्त दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि है। लोकतांत्रिक भावना का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि अनेक उपलब्धियों के बावजूद हमारे समाज में और तंत्र में जो भी कमियां रह जाएं या कभी कोई गलती हो जाए तो उस पर खुले माहौल में चर्चा करने और इस आधार पर शीघ्र ही भूल-सुधार की बेहतर संभावनाएं समाज में और तंत्र में बनी रहें। समाज में समरसता व सहयोग आगे बढ़ना चाहिए और एक-दूसरे के साथ प्रेरणादायक माहौल में उपलब्धियां प्राप्त करने का माहौल गांव और मोहल्ले के स्तर पर बने रहना चाहिए।

सभी तरह के नशे के दूर करने के लिए भी समाज में निरंतरता से प्रयास होने चाहिए। इन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता यदि समाज और देश में बनेगी तो निश्चय ही हम अच्छी प्रगति कर सकेंगे और विश्व की निगाहें हमारी प्रगति पर और हमसे सीखने पर होंगी। यह सिद्धांत जहां हमें अपने संविधान से भी प्राप्त होते हैं और हमारे इतिहास के सबसे बड़े प्रेरणादायक व्यक्तियों के संदेश भी इसी दिशा में रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बास, शहीद भगत सिंह-ये आजादी की लड़ाई के ऐसे महान नेता थे जिनके कुछ मतभेद हो सकते हैं पर इन सभी सिद्धांतों को इन सभी ने बहुत महत्त्व दिया।

अब सबसे बड़े समाज-सुधारकों की बात करें तो बाबा अंबेडकर, ज्योतिबा और सावित्री फुले ने भी इनको महत्त्व दिया। इतिहास के पृष्ठों में कुछ पीछे जाएं तो संत कबीर, गुरु नानक, गरीब नवाज ने भी ऐसी राह दिखाई। अतः देश में जो भी लोग इन महान व्यक्तित्वों को सही अर्थों में बहुत सम्मान देते हैं, वे भी इनके इस संदेश से सीखते हैं और इन सिद्धांतों को अपनाते हैं। इसके बावजूद इन सिद्धांतों को सही तरह से मिला कर एक भली-भांति समग्रीकृत राह निकालने का जो कार्य है, उसमें कई बार कठिनाई आ जाती है। अतः जरूरी है कि मौजूदा स्थितियों के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सोचा-सुलझी समग्रीकृत राह पर ऐसी प्रगति करे जो टिकाऊ और विश्वसनीय हो।

हां, इतना जरूर है कि यदि किसी समुदाय से इतिहास के पृष्ठों में अन्याय हुआ है तो, उसे सामाजिक-बराबरी तक पहुंच पाने के अवसर तब तक देने चाहिए जब तक यह समानता प्राप्त नहीं हो जाती है और पूर्ण समाज की गरिमा इसी में है कि इस समानता की स्थिति तक सबकी सहमति से पहुंचा जाए। जिस समाज में सभी को समान अवसर मिलेंगे उसी समाज की प्रतिभाएं सबसे अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसी तरह जिस समाज में महिलाओं को प्रगति के समान और भरपूर अवसर मिलेंगे, वह समाज भी प्रगति में आगे रहेगा। इस समानता को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष ध्यान यह रखना होगा कि धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, लिंग आदि के आधार पर किसी के विरुद्ध कोई भी हिंसा न हो। सांप्रदायिक, जातिगत और महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए

मीडिया को प्रिय है विश्व युद्ध

मीडिया

सुधीश पचौरी

साक्षात युद्ध में किसी युद्धरत देश का क्या हाल बनता है और उसके 'जन धन' की कितनी हानि होती है? इस कड़वे सत्य के प्रति न हमारा मीडिया सजग नजर आता है न उसके एंकर या रिपोर्टर ही! वे शायद यह भी नहीं जानते कि आज कोई भी देश चाहे भी तो युद्ध को नहीं जीत सकता यानी हर युद्ध देशों के 'गले की हड्डी' बन जाता है

रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही हमारे कई हिन्दी चैनल हर रोज कहते कि अब होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध...होने वाला है परमाणु युद्ध...इस युद्ध को एक बरस से अधिक हो गया लेकिन अब तक नहीं हुआ कथित 'परमाणु युद्ध' या 'विश्व युद्ध'। रोज गोले बरसते। हमारे कई चैनलों के रिपोर्टर भी 'कीव' पर होते हमले लाइव कवर करते लेकिन अब तक नहीं हुआ परमाणु युद्ध, नहीं छिड़ा 'विश्व युद्ध'!

ऐसे ही पिछले बरस एक दिन 'हमास' ने अचानक इस्राइल के उत्सवरत निरीह नागरिकों पर हमला कर हजार से अधिक लोगों को मार दिया। जवाबी हमले में इस्राइल ने हमास के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हजारों लोग मारे गए। इसको भी एक साल से अधिक हो गया लेकिन अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। हमारे कई चैनल बार-बार कहते दिखते कि अब हुआ परमाणु युद्ध, विश्व युद्ध।

पिछले दिनों जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 'पहलगाम' में दर्जनों निरीह सैलानियों का धर्म पूछ कर उनकी निर्मम हत्याएं कर दीं और जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को 'आपरेशन सिंदूर' के जरिए नष्ट कर दिया, उससे कुछ पहले तक कई पाकिस्तानी नेता डराते रहे कि उनके पास एटम बम है। वो भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं...चैनल भी इस धमकी को बढ़ा-चढ़ा कर बताते रहे लेकिन जब भारत की सेना ने 'आपरेशन सिंदूर' सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और एकतरफा सीजफायर घोषित कर दिया तो भी कुछ न हुआ और तब से अब तक कुछ न हुआ।

इसी तरह अभी जब इस्राइल ने ईरान के 'नतांस' स्थित परमाणु ठिकानों पर मिसाइलों से हमला करके उनको नष्ट कर दिया तो भी हमारे कई चैनल कहने लगे कि अब हुआ तीसरा युद्ध, कि अब हुआ परमाणु युद्ध...अब होगा तीसरा विश्व युद्ध...। ईरानी नेता ऐलान करने लगे कि हम इस्राइल को छोड़ेंगे नहीं...इस्राइल का नामोनिशान मिटाके रहेंगे...फिर यह तक खबर आने लगी कि ईरान के 'नतांस' इलाके में स्थित परमाणु ठिकानों पर इस्राइली हमले के कारण वहां स्थित 60 फीसद 'यूरेनियम' भडार में 'रिसाव' हो गया है। एक प्रकार की 'परमाणु धूल' उड़ने लगी है जो ईरान के आसपास के कई देशों जैसे कुवैत आदि तक हवा के साथ फैल सकती है और इसे ठीक करने में ईरान को बरसों लग जाएंगे...कुछ युद्ध एक्सपर्ट एक हिन्दी चैनल पर यह तो बताते रहे कि अब ईरान बरसों तक परमाणु प्रदूषण से बचने में ही लगा रहेगा लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि अब 'तीसरा युद्ध' शुरू हो सकता है...तो भी वही चैनल इस कहानी के शीर्ष पर मोटे अक्षरों में लिखे दिखाता रहा कि 'ईरान इस्राइल युद्ध, अब पक्का तीसरा युद्ध'! यानी युद्ध विशेषज्ञों का सारा विश्लेषण एक तरफ लेकिन चैनलों द्वारा कल्पित 'आसन्न विश्व युद्ध' एक तरफ!

सच! 'टीवी' तिल का ताड़ बनाने वाला माध्यम है। वह जरा सी बात को फैला कर 'बड़ी बात' की तरह पेश करने में माहिर है क्योंकि अपने टीवी ने अपने लिए 'यथार्थवादी मुहावरा' चुनने की जगह 'अतिश्योक्ति वाला' मुहावरा ही चुना है। इसीलिए किन्हीं दो देशों में अचानक 'गोला गोली' चलने लगते हैं तो उसके अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक कारणों में जाए बिना ऐसे चैनल सीधे 'तीसरे विश्व युद्ध' की 'कल्पना' करने लगते हैं और उसे ही दर्शकों को बीच बेचने पर तुल जाते हैं। चूंकि आज के नई पीढ़ी के 'दर्शकों' और 'एंकरों रिपोर्टरों' ने भी कोई साक्षात् युद्ध अपनी आंखों से नहीं देखा। इसलिए वे साक्षात् युद्ध के आइडिया से ही उत्तेतित होते हैं और जनता को 'युद्धोन्मादी' और 'युद्धप्रिय' बनाते रहते हैं। अपने चैनल कल्पित युद्ध को भी ओटीटी फिल्म की तरह दिखाने के आदी हैं।

एक साक्षात युद्ध में किसी युद्धरत देश का क्या हाल बनता है और उसके 'जन धन' की कितनी हानि होती है? इस कड़वे सत्य के प्रति न हमारा मीडिया सजग नजर आता है न उसके एंकर या रिपोर्टर ही! वे शायद यह भी नहीं जानते कि आज कोई भी देश चाहे भी तो युद्ध को नहीं जीत सकता यानी हर युद्ध देशों के 'गले की हड्डी' बन जाता है। फिर भी कई चैनल आए दिन 'तीसरी लड़ाई' की आशंका जताते रहते हैं और शायद इसी तरह हमें युद्ध की विभीषिका से निरपेक्ष बना कर हमें उसका उपभोक्ता बनाने के चक्कर में रहते हैं। अमेरिका ने 'इराक युद्ध' को सीधे 'युद्ध भूमि' से लाइव प्रसारित कर युद्ध के 'ग्लोबल बाजार' को खोल दिया है। शायद अपने चैनल भी इसी अवसर की तलाश में हैं, जो किसी तर्क से सही और मानवीय नहीं कहा जा सकता।

विकास के पथ पर सरपट देश

मोदी सरकार

शिवप्रकाश

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद की स्थिति, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने, आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण को विश्व के सम्मुख रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश की एकजुटता को प्रकट करने का कूटनीतिक सराहनीय प्रयास रहा

मोदी मोदी सरकार 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 'संकल्प से सिद्धि' अभियान चला रही है। इसके तहत संपूर्ण देश में मोदी सरकार की सफलता पर प्रेस वार्ताएं, प्रदर्शनी, विचार संगोष्ठी, जनसभाएं एवं ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सोशल मीडिया द्वारा योजनाओं की जानकारी एवं अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो रहा है। चाणक्य नीति में कहा गया है, 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते'। शास्त्रों की चर्चा भी तभी संभव है जब राष्ट्र सभी प्रकार से सुरक्षित हो। इसी कारण विद्वानों ने शक्ति को ही शांति का आधार बताया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' अपनी कविता 'क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो' इस सिद्धांत को ही प्रतिपादित करते हैं।

भारतीय जनसंघ ने अपने 1964 के पटना अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते हुए मांग की थी कि भारत को परमाणु बम बनाने के सभी प्रयत्न करने चाहिएं। 'सिद्धांत एवं नीतियां' नामक दस्तावेज में भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने की बात थी। प्रस्ताव प्रतिपादन करते समय कहा गया था कि हमारे आराध्य सभी देवी-देवता धर्म संस्थापना के लिए शस्त्रधारी हैं। इसलिए भारत माता भी परमाणु बम धारी होनी चाहिए। इसी नीति का अनुसरण करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1999 में पोखरण परमाणु विस्फोट कर विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया था। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद देश अपने हितों की सुरक्षा करने में समर्थ बने इस प्रकार की नीति पर चला। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी का उदाहरण है।

ग्यारह वर्ष के सफलतम कालखंड में विदेशों से शस्त्र खरीद ही नहीं, हमने स्वयं आत्मनिर्भर होने के मंत्र को भी पहचाना है। अब हम भारत में उन्नत एवं आधुनिक स्वदेशी शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। स्वदेशी विमान वाहकपोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रुस्तम यूएवी ड्रोन का डीआरडीओ द्वारा लखनऊ में निर्माण, रूस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, टाटा-डसाल्ट के साथ राफेल के मुख्य भाग का हैदराबाद में हम निर्माण करने वाले हैं। रक्षा उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 174% की वृद्धि हुई है। रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46529 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 127265 करोड़ रुपये का हुआ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 नवम्बर, 2021 को झांसी में कहा था कि 'भारत अपनी रणनीतिक व सुरक्षा आवश्यकताएं अन्य देशों पर निर्भर होकर पूरा नहीं कर सकता... सरकार निरंतर 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में प्रयासरत है।' रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति के कारण अब हम खरीदने अर्थात आयात करने वाले देश नहीं, बेचने वाले अर्थात निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। 2004 से 2014 अर्थात 10 वर्षों में हमने 4312 करोड़ का निर्यात किया। आयात में 21% की कमी करके 11 वर्षों में निर्यात में 34% की वृद्धि करने में देश सक्षम हुआ है। आज हम 80 से अधिक देशों में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्वदेशी शस्त्रों की सफलता को देख कर विश्व में हमारे शस्त्रों की मांग भी बढ़ गई है।

प्रत्येक प्रकार की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 2 सितम्बर, 2022 को कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नये ध्वज का अनावरण किया, जिसमें औपनिवेशिक 'सेंट जॉर्ज क्रॉस' को हटा कर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित अष्टकोणीय प्रतीक को स्थान दिया गया। इसमें अशोक स्तंभ, लंगर और नौसेना का आदर्श वाक्य 'शं नो वरु णः' अंकित है, जो भारत की समुद्री विरासत और आत्मगौरव का प्रतीक है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने, आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण को विश्व के सम्मुख रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश की एकजुटता को प्रकट करने का कूटनीतिक सराहनीय प्रयास है। भारत को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ये प्रयास देश की जनता में यह विश्वास जगाने में सफल हुए हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। यकीनन उनके नेतृत्व रक्षा क्षेत्र में नित नये कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

क्या गरीबी-मुक्त भारत का संकल्प हो रहा पूरा!

उपलब्धि

रवि शंकर

भारत में विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में काफी ज्यादा कमी देखी गई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 में 27.1 प्रतिशत की अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घट कर मात्र 5.3 प्रतिशत रह गई है। जीहां, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 साल के शासन के बाद देश को अच्छी खबर मिली है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। विश्व बैंक ने हाल में अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित करते हुए इसे 2.15 डॉलर प्रति दिन से बढ़ा कर तीन डॉलर प्रति दिन कर दिया है। इस नये मानक के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घट कर 75.24 मिलियन हो गई है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों के बारे में बताती है।

विश्व बैंक की यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि नीति, प्रयास और जनसहभागिता से गरीबी जैसी चुनौती को मात दी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार नागरिकों की वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रभावी रही है। निस्संदेह, इसने सबसे गरीब तबके के लोगों की आय बढ़ाने में मदद की है। जाहिर तौर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिजली, शौचालयों और आवास तक इस तबके की पहुंच बढ़ाने जैसी पहल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में योगदान दिया है, जिसका नतीजा सामने है। लेकिन जहां हम गरीबी उन्मूलन में मिली सफलता पर आत्ममुग्ध हैं वहीं समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि भारत में शीर्ष एक प्रतिशत लोगों की संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। वे लोग देश की चालीस फीसदी संपत्ति नियंत्रित करते हैं। ये असमानताएं हैं, जिन्हें अवश्य ही दूर किया जाना चाहिए।

बहरहाल, भारत में बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी सफलता मिली है। संघीय सरकार वाले इतने बड़े, विविधतापूर्ण देश में नीति निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए पीएम मोदी ने कई मौकों पर कठोर परिस्थितियों के बावजूद समय पर निर्णय और नीतियों को लागू करके 1.4 बिलियन लोगों के विकास के लिए अपने समर्पण का उत्तरदायित्व निभाया है। फिर भी असमानता, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी जैसी लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में भारत के विकास की गाथा तभी लिखी जा सकती है, जब हम असमानता की खाई पाटकर गरीबी को कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। यह तभी संभव है जब सरकार की कल्याणकारी नीतियां न केवल उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालें, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाएं। आर्थिक कल्याणकारी नीतियों का मकसद मुफ्त की रेवड़ियां बांटना न होकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। खैर, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकारी पहलों, आर्थिक सुधारों और सेवाओं तक सबकी पहुंच से ही गरीबी दिन-ब-दिन तेजी से घट रही है।

राजा की हत्या और वायरल न्याय

बेवफाई

प्रियंका सौरभ

राजा रघुवंशी की हत्या एक नवविवाहित पत्नी सोनम द्वारा प्रेमी के साथ मिल कर हनीमून के दौरान की गई क्रूर साजिश थी। यह घटना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे और सामाजिक मूल्यों की गिरावट का प्रमाण है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्टों ने संवेदना के स्थान पर स्त्री-द्वेष को बढ़ावा दिया है। इस घटना ने यह उजागर किया कि पुरुष भी रिश्तों में शिकार हो सकते हैं, पर हर महिला को दोषी ठहराना भी खतरनाक है। जरूरत है भावनात्मक शिक्षा, विवेकपूर्ण विवाह निर्णय और सोशल मीडिया पर अनुशासन की। 'शादी हुई 11 मई को, 20 को हनीमून, 23 को हत्या, 2 जून को शव, 9 जून को गिरफ्तारी'-यह आंकड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक नवविवाहित पति की मौत और एक स्त्री के प्रेम, छल और अपराध के बीच बहते खून की कहानी है। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे समाज में आ रही मानसिक गिरावट और रिश्तों की ट्रैजेडी का आईना है। लेकिन इस बार घटना की तरह, उसका 'सोशल मीडिया ट्रायल' उससे भी ज्यादा वीभत्स निकला। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी-नामों में प्रेमी-युगल सा अहसास, पर कहानी में विष घुला हुआ था। 11 मई को विवाह हुआ, 20 मई को दोनों मेघालय गए, 23 को पति लापता, और 2 जून को गहरी खाई में उसका शव बरामद। 9 जून को पत्नी सोनम और उसके तीन साथियों की गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ एक 'दुर्घटना' नहीं, बल्कि 'पूर्व-नियोजित हत्या' थी। इस मामले में जितनी क्रूरता हत्या में थी, उससे कहीं अधिक निर्ममता समाज की प्रतिक्रियाओं में देखने को मिली।

'फूहड़ औरत', 'सभी औरतें धोखेबाज होती हैं', 'शादी से डर लगने लगा है', जैसी टिप्पणियां, वायरल पोस्टों के जरिए पूरे स्त्री समाज को कठघरे में खड़ा कर रही हैं।

सवालः अपराध किसका है? महिला का या स्त्रीत्व का?

क्या सोनम की करतूत के लिए हर औरत दोषी है?

क्या राजा की मौत सिर्फ एक प्रेमी के छल की कहानी है, या एक समाज की विफलता भी?

रिश्तों की हत्या में केवल खंजर नहीं होता-झूठ, लालच, डर, दिखावा और दोहरे संबंध भी हत्यारे होते हैं। लेकिन जब किसी महिला द्वारा अपराध होता है, तो उसे सिर्फ 'एक आरोपी' नहीं, बल्कि 'पूरे लिंग की प्रतिनिधि' मान लिया जाता है। सवाल यह है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को मार दे, तब समाज 'पुरुषों को दोष मत दो' कहता है, लेकिन जब एक महिला पति को मारती है, तब 'सब औरतें ऐसी ही होती हैं' कह कर स्त्रीत्व को कलंकित किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें घटना की टाइमलाइन दी गई है, और अंत में स्त्रियों को सावधान करने की बात कही गई है। इस पोस्ट को हजारों लाइक्स, शेयर और व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या यह न्याय की लड़ाई है, या वायरल ट्रेंड की भूख? जिस समाज में लोग किसी की मौत पर भी व्यूज और फॉलोअर्स के लिए स्टोरी बनाते हों, वहां संवेदनाएं पोस्ट की कैप्शन में दफन हो चुकी हैं। 'इंस्टा पर इंसाफ' का ट्रेंड धीरे-धीरे कानून, विवेक और मर्यादा को कुचल रहा है। यह घटना हमें यह भी बताती है कि पुरुष भी रिश्तों में शिकार हो सकते हैं। हर बार महिलाएं ही पीड़िता नहीं होतीं-कई बार वे शोषक भी हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर महिला को शक की निगाह से देखें, हर प्रेम को झूठा मानें या शादी को व्यापार कह दें।

पुरुषों के प्रति हो रही हिंसा, धोखा या हत्या पर चर्चा होनी चाहिए-

लेकिन बिना स्त्रीविरोध की जहरीली भाषा के।

रिश्तों का रेडिकल पुनर्मूल्यांकन जरूरी है

इस घटना ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर किया है किः क्या विवाह सिर्फ दिखावा बन कर रह गया है? क्या भावनात्मक निष्ठा अब इंस्टाग्राम स्टेटस पर टिकी है? क्या हम इतने खोखले हो गए हैं कि प्यार अब हत्या का मुखौटा बन जाए? शादी अब 'सेरेमनी' जयादा, और 'समझदारी' कम बनती जा रही है।

लोग सात फेरे ले तो लेते हैं, पर सात दिन भी भरोसा निभा नहीं पाते। -समाज की दिशा बदलनी होगी

इस घटना को एक 'मिम' या 'हॉट न्यूज' बना देना आसान है। लेकिन इससे हमें इन गहरी बातों पर ध्यान देना होगा। स्कूलों में 'इमोशनल लिटरेसी' को भी स्थान मिलना चाहिए। शादी से पहले पारिवारिक जांच से ज्यादा, चरित्र और मानसिकता की जांच होनी चाहिए। अपराधी स्त्री हो या पुरुष, उसकी जाति, लिंग, धर्म से ऊपर उठ कर न्याय होना चाहिए। संवेदनशील मामलों में अफवाहें न फैलाएं। पोस्ट से अधिक पोस्टमार्टम सच बोलता है। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मौत एक त्रासदी है-लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी है हमारी प्रतिक्रिया। क्या हम उस हत्या से दुखी हैं, या उस पर रील बनाने को उत्साहित? सोनम ने अपराध किया-इसका कानूनी रास्ता तय है। लेकिन उसका नाम लेकर हर महिला को 'फूहड़', 'धोखेबाज' और 'हत्या की मशीन' बताना, हमें समाज के तौर पर शर्मिंदा करता है।

'शादी हुई 11 मई को, 20 को हनीमून, 23 को हत्या, 2 जून को शव, 9 जून को गिरफ्तारी'-यह आंकड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक नवविवाहित पति की मौत और एक स्त्री के प्रेम, छल और अपराध के बीच बहते खून की कहानी है। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे समाज में आ रही मानसिक गिरावट और रिश्तों की ट्रैजेडी का आईना है। लेकिन इस बार घटना की तरह, उसका 'सोशल मीडिया ट्रायल' उससे भी ज्यादा वीभत्स निकला। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी-नामों में प्रेमी-युगल सा अहसास, पर कहानी में विष घुला हुआ था। 11 मई को विवाह हुआ, 20 मई को दोनों मेघालय गए, 23 को पति लापता, और 2 जून को गहरी खाई में उसका शव बरामद

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 297
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

कोई ध्यान नहीं देता मुंडाओं पर जो वियतनाम से 4000 से ज्यादा वर्ष पूर्व अपने साथ नये प्रकार के चावल, गन्ना, पान, बांस आदि लाए थे। हम सिर्फ आर्यों की बात करते हैं, जो 3500 वर्ष पहले आए...तो गुजरात या हरियाणा की बात चलती है, तमिलनाडु या त्रिपुरा या उड़ीसा की नहीं।

देवदत्त मिश्र, धर्म मर्मज्ञ@devduttmyth

संस्कृति

प्रेम प्रकाश

अस्मिता का विवेक और हेरिटेज टनल

देश में नब्बे के दशक में जब अस्मितावादी राजनीति का जोर बढ़ा तो उसके दूरगामी फलित को समझने में बड़ी चूक हुई। यह राजनीति सामाजिक अन्याय के खिलाफ महज एक प्रतिक्रिया से ज्यादा आज अपने अतीत से बड़ी मुठभेड़ साबित हो रही है। यह मुठभेड़ भारत जैसे देश में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका अतीत सभ्यता के विकास के उत्स तक की यात्रा कराता है। आज अगर अपनी पहचान और गौरव की ललक देश-समाज में बढ़ी है तो इसका प्रतिबिंबन सरकारों के विवेक में भी दिखता है। दिलचस्प है कि इस साल अकेले जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, वह बिहार है। बिहार में बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करें तो यह प्रतिबिंबन साफ पहचान में आता है।

दिलचस्प है कि बिहार के चुनाव के केंद्र में इस बार नीतीश राज के दो दशक की उपलब्धियां और साख हैं। पूरे प्रदेश को छोड़ अकेले पटना की बात करें तो विरासत से विकास का साझा हर जगह बदलाव के नये स्थापत्य के रूप में खड़ा दिखता है। सभ्यता द्वार, ज्ञान भवन, बापू टावर से लेकर नवनिर्मित बिहार संग्रहालय तक हर जगह बिहार अपने स्व की पहचान के साथ अपने सांस्कृतिक वैभव को नये सिरे से लोगों के सामने रख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नये बने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले निर्माणाधीन हेरिटेज टनल को लेकर खासे उत्साहित हैं। डेढ़ किलोमीटर का यह अंडरग्राउंड टनल अपने आर्टिफैक्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, यह देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में पहली बार है, जब कोई क्षेत्र अपने अतीत के वैभव को लेकर इस तरह की जागृति का परिचय दे रहा हो। खास तौर पर ऐसी जागृति अगर बिहार जैसे सूबे में दिख रही है तो यह देश में विकास और नवनिर्माण को नये सिरे से परिभाषित कर रही है। निश्चित तौर पर यह परिभाषा रातोंरात नहीं गढ़ी गई है। बीते दो दशक की राजनीतिक स्थिरता ने इसमें विशेष रूप से बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाई है। बिहार के इस उदाहरण का फलक बड़ा है, और इससे इतिहास बोध को लेकर विमर्श के कई मुहाने एक साथ खुलते हैं।

गौरतलब है कि मौजूदा सदी के दो-ढाई दशक में देश में जिस तरह की राजनीतिक-सामाजिक स्थिति बनी है, उससे अतीत और इतिहास की मिट्टी पलटते हुए अपनी पहचान को सुदृढ़ देखने की मनोदशा स्वाभिवकता में तब्दील हुई है। ऐसे में इतिहास लेखन और इतिहास दृष्टि को लेकर बात भी नये सिरे से करने की जरूरत है। सवाल है कि इतिहास के पुर्नेखन और साक्ष्यों के पुनर्परीक्षण के जरिए हम अपने अतीत बोध को किसी नये और वैकल्पिक सांचे में गढ़ रहे हैं या फिर औपनिवेशिक मानसिकता से लैस लीक पर ही आगे बढ़ रहे हैं।

यह भी कि इतिहास लेखन में व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की आशंका बनी रहती है। इस बात से कहीं इनकार नहीं कि भारत का प्रचलित आधुनिक इतिहास विदेशी आक्रांताओं, अंग्रेजी शासन और वामपंथी विचारधारा से जुड़े इतिहासकारों की देन है। भारत की संपन्नता और वैभव उन्हें आकर्षित करता था। इसी तरह अंग्रेजों की औपनिवेशिक दृष्टि में ईसाई धर्म को लेकर उनका परम भाव सबसे अहम रहा। अपने धर्म को उन्होंने तकरीबन मानवता और मानव सभ्यता के बरक्स खड़ा कर दिया। भारत में पुराने शिक्षा संस्थानों से लेकर शासन पद्धति और कानूनों में आज भी यह छाप नजर आती है। इस दौर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उसके 'स्व' से रणनीतिक तौर पर विमुख किया गया।

बात करें वामपंथी इतिहासकारों के उदय और खास तौर पर आजादी के समय और उसके बाद सरकारी संस्थानों में उनके प्रभावी होने की तो ऐसे लोगों ने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग पाश्चात्य दृष्टि से ही किया। इसके लिए उन्होंने

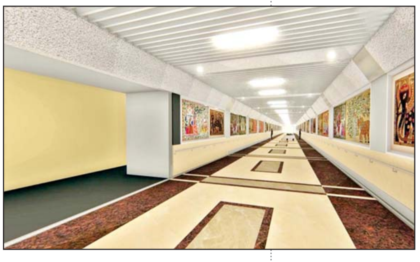

भारतीय चिंतन को घटिया तक साबित किया ताकि नई प्रस्थापनाएं लोगों के मन-मस्तिष्क को घेर सकें। इस बाबत कार्ल मार्क्स का कथन खासा रोचक है, 'ब्रिटिश भारत में चाहे कितने भी निर्दयी रहे हों, भारत के लिए समाधान केवल उसके पश्चिमीकरण में ही है, जो विजेता यूरोपीय श्रमिक वर्ग के द्वारा ही संभव है।' इतिहास लेखन और उसके बोध को लेकर इन तमाम स्थितियों के बीच बात वर्तमान चिंताओं की करें तो आज हम पूर्व के अन्याय और ज्यादतियों से निकलने की बजाय उसकी छाया में खड़े होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। यह निहायत बचकानी स्थिति है।

दरअसल, अपने इतिहास में अपने 'स्व' की खोज के लिए हमें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। इस दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण नाम है इतिहासकार डॉ. धर्मपाल का। उनकी लिखी एक छोटी सी पुस्तिका है-भारतीय चित्त, मानस और काल। इसमें डॉ. धर्मपाल वैसी तमाम मानसिकता से मुक्त होने की दरकार सामने रखते हैं, जो हमें अतीत के गौरव से दूर करती है। डॉ. धर्मपाल द्वारा इकट्ठा किए गए ब्रिटिश दस्तावेज से साबित होता है कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा। मसलन, 1822-25 के मद्रास प्रेसीडेंसी में किए गए सर्वे के अनुसार, उस समय वहां 11,575 स्कूल और 1,094 कॉलेज थे। इनमें क्रमशः 1,57,195 और 5,431 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। इन दस्तावेज में जातिगत बनावट के बारे में भी हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं, जिनके अनुसार तमिल-भाषी क्षेत्र में निम्न जातियों से संबंधित 70 से 80 फीसद विद्यार्थी थे, उड़िया क्षेत्र में 62 फीसद, मलयालम-भाषी क्षेत्रों में 54 फीसद और तेलुगू क्षेत्रों में 50 फीसद थे। यही बात तकनीकी ज्ञान के बारे में भी लागू होती है।

उत्तर प्रदेश के अतिरंजी-खेड़ा में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होता था और 18वीं शताब्दी तक बढ़िया किस्म का इस्पात बनाया जाता था। उस समय प्रति वर्ष उच्च कोटि का इस्पात बनाने वाली कम-से-कम दस हजार ऐसी भट्टियां थीं, जो साल में बीस टन तक इस्पात तैयार करती थीं। उस दौर में चेचक के इलाज के लिए टीकाकरण (इनोक्युलेशन) तक किया जाता था और प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अंग मरम्मत भी की जाती थी। सुश्रुत के सदियों बाद 18वीं शताब्दी तक यह विद्या मौजूद थी। यह तथ्य भारतीय सिविल सेवा के एक अफसर डा. बैरी द्वारा पूना में उनके द्वारा देखे गए एक ऑपरेशन के वर्णन से उजागर होता है।

गौरतलब है कि इतिहासकार डॉ. धर्मपाल ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश प्रशासन से जुड़े अफसरों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के रिकार्ड ब्रिटिश संग्रहालयों से खोज कर, ब्रिटिश-पूर्व भारतीय इतिहास का एक छिपा हुआ पक्ष सामने लाए। वर्तमान इतिहास लेखन में भारतीय दृष्टि की स्थापना के लिए इसे उपयोग में लाया जाना चाहिए। यह विवेक देश के विद्वत समाज के बीच विकसित होना चाहिए कि विरासत के साथ विकास का विजन भी तभी रंग दिखाएगा, जब हम इतिहास लेखन की प्रक्रिया का लक्ष्य और कंपास 'स्व' की खोज पर स्थिर करेंगे। ■

अपने इतिहास में अपने 'स्व' की खोज के लिए हमें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। इस दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण नाम है इतिहासकार डॉ. धर्मपाल का। उनकी लिखी पुस्तिक है-भारतीय चित्त, मानस और काल। इसमें डॉ. धर्मपाल वैसी तमाम मानसिकता से मुक्त होने की दरकार सामने रखते हैं, जो हमें अतीत के गौरव से दूर करती है। डॉ. धर्मपाल द्वारा इकट्ठ किए गए ब्रिटिश दस्तावेज से साबित होता है कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा

पिता की बदलती भूमिका

भारतीय समाज में पिता को अक्सर वह व्यक्ति माना जाता था, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखता है। वहीं मां की जिम्मेदारी रसोई से लेकर परिवार की सेवा तक घर के अंदर सीमित रखी गई। भारतीय संस्कृति में माता को पूजनीय माना गया और उनकी मेहनत, त्याग और बलिदान की गाथाएं पीढ़ियों से गूंजती रही हैं। हालांकि, आज यह परिभाषा तेजी से बदल रही है। आज का पिता न केवल आर्थिक स्तंभ है, बल्कि भावनात्मक समर्थन, लैंगिक समानता का समर्थक और घरेलू जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदार भी है। वहीं महिलाएं भी घर से बाहर समाज, राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में भागीदार बन रही हैं। फिर भी, इस बदलाव के बीच पिता की उपेक्षा एक हकीकत है।

आधुनिक पिता अब केवल परिवार का आर्थिक रक्षक नहीं है। बच्चों का दोस्त, मार्गदर्शक और भावनात्मक सहारा बन रहा है। बच्चों के साथ समय बिताता है, उनकी भावनाओं को समझता है, और उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करता है। पिता अब लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक भी हैं। बेटियों को खेल, विज्ञान या तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहित करते हैं, और बेटों को घर के कामों में भाग लेना सिखाते हैं। साथ ही, घरेलू जिम्मेदारियों में सक्रिय हैं-खाना बनाने से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने तक।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 62% शहरी पिता घर के कामों में नियमित रूप से योगदान करते हैं। यह बदलाव न केवल परिवारों में समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन उनकी मेहनत और योगदान को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। पिता को परिवार का 'मजबूत आधार' मान कर उनकी भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को अनदेखा कर दिया जाता है। यह अपेक्षा कि 'पिता को हमेशा मजबूत रहना चाहिए' उनके लिए अदृश्य बोझ है। समाज में अवधारणा है कि, जो महिलाएं घर परिवार संभालती हैं, कड़ी मेहनत सिर्फवो करती हैं। बाकी मर्द जो कमा कर घर आता है, उनकी मेहनत कम होती है। भारतीय पिता अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। 'मर्द को दर्द नहीं होता' जैसी रूढ़ियां उन्हें अपनी कमजोरियों या तनाव को छिपाने के लिए मजबूर करती हैं। पिता से अपेक्षा की जाती है कि न केवल आर्थिक जिम्मेदारियां निभाएं, बल्कि भावनात्मक रूप से उपलब्ध हों, घर के कामों में मदद करें और बच्चों की परवरिश में सक्रिय रहें। यह तभी संभव है जब महिलाएं भी आर्थिक जिम्मेदारी में बराबरी की जिम्मेदार और हिस्सेदार बनें।

फादर डे जैसे अवसर भी मदर डे की तुलना में कम उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। भारतीय पिता को कानूनी एवं सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तलाक या पारिवारिक विवादों में पिताओं को अक्सर बच्चों की कस्टडी या भावनात्मक रिश्ते में कम प्राथमिकता दी जाती है। पिता की उपेक्षा का असर न केवल उन पर, बल्कि परिवार और समाज पर भी पड़ता है। जब पिता की भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा किया जाता है, तो वे तनाव, अवसाद या अलगाव के शिकार हो सकते हैं। इससे परिवार में संवाद की कमी और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। बच्चे भी पिता के साथ गहरे भावनात्मक रिश्ते से वंचित रह सकते हैं, जो उनके विकास पर असर डालता है। समाज में भी पिता की अनदेखी लैंगिक रूढ़ियों को और मजबूत करती है, जिससे पुरुषों के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना और मुश्किल हो जाता है।

फिर भी, समाज में अपनी जगह बनाने का सबसे मजबूत पक्ष पिता होता है। हम पिताओं के योगदान को न केवल सराहें, बल्कि उनकी भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को भी समझें। ऐसा समाज बनाएं जहां पिता को न केवल 'मजबूत', बल्कि 'संवेदनशील' और 'सम्मान' के रूप में भी देखा जाए क्योंकि पिता भी उतने ही पूजनीय हैं, जितनी कि मां।

प्रस्तुति : अम्बिका कुशवाहा अम्बी ■

'कौन लीपे गोबर आंगन, कौन जलाए तुलसी बाती'

देश की प्रसिद्ध संस्था 'ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' ने बीती 6 जून को आभासी बहुभाषी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉ. सरोजिनी प्रीतम की अध्यक्षता में गोष्ठी की गई। उनकी कविता की ये पंक्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं-जब से गाय सी कन्या/घर में आई है/सभी उसे नोच नोच कर खाते हैं।' उन्होंने काव्य गोष्ठी को सफल बताया और कहा, संस्था के साथ जुड़े हुए दक्षिण से उत्तर तक के साहित्यकारों ने अपनी-अपनी आंचलिक भाषा में काव्य प्रस्तुत कर एकात्मकता का दृश्य साकार कर दिया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैदराबाद चैप्टर की संयोजक डॉ. अहिल्या मिश्रा ने आयोजन को सफल करार देते हुए भारत में फैलती अशांति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कविता सुनाई-'कौन लीपे गोबर आंगन, कौन जलाए तुलसी बाती'।

कार्यक्रम की प्रस्तावना, संचालन और आभार संस्था के महासचिव डॉ. शिव शंकर अवस्थी ने जताया। उनकी कविता थी-'मेरी तमन्नाओं का नगर बस जाता अगर, अच्छे बच्चों के सर होता ताज, ऐसे लोगों का होता राज।' कार्यक्रम में हिन्दी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, गुजराती, कन्नड़ और अन्य भाषाओं में कवियों ने प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम की शुरुआत पंजाबी भाषा की कविता से करते हुए 'डॉ. सुदेश भाटिया विद्यासागर', दिल्ली ने हालिया पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर प्रहार करते हुए कहा, 'आज स्वर्ग दे विच किन शोर मचाया, धरम दा पता पुछ पुछ मारदे जांदे।' गुरु प्रताप शर्मा उमरेड ने 'इश्क मेरा आजादी', नेहा कौशिक ने 'एक छोटी सी चिड़िया', आर पार्वती, चेन्नई ने हिन्दी में 'दर्द', डॉ. सी जे प्रसन्न कुमारी, तिरुवंतपुरम ने मलयालम में बसंत के मौसम की बहार और फूलों का जिक्र किया तो अंजलि अवस्थी, दिल्ली के सकारात्मक बोल थे-'पड़ाव भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठहराव उपरांत पुनः गतिशीलता के लिए'। डॉ. आशा मिश्रा 'मुक्ता', हैदराबाद की-'सायकल' दूर गांव की सड़क पर चली', 'शिप्रा मिश्रा', चंपारण ने स्त्रियों को प्रवासी बताते हुए पूछा कि 'उन्हें तथागत की उपाधि क्यों नहीं मिलती', युवा 'चंदा जी' के बोल थे-'वक्त थोड़ा ही बचा हंसने-हंसाने के लिए' और 'ऋता शेखर 'मधु', बेंगलुरू ने वोटरों को जाग्रत करने का प्रयास कुंडलियों के माध्यम से यूं किया-'याद रहे हर बार सही सांसद लाना है, जो करता है कुछ काम उसे ही लाना है।'

पुष्पन आशा रिक्कुनू ने मलयालम भाषा में 'अंडेड्योरानो' शीर्षक से, पूर्णिमा एस ने तमिल को अमृत भाषा के रूप में बताया। प्रदीप गौतम 'सुमन', रीवा ने गीत 'तुमको अपना बनाना चाहा', राम वल्लभ गुप्त इंदौरी ने 'कैसा लोकतंत्र', 'बड़ी पार्टियां', 'जनता बगले झांके' आदि कई रूपक गढ़े। वहीं, मधु पाटोदिया, नागपुर की यथार्थ सत्य 'मेरी अपनी कहानी' के बोल थे-'रसोई बोली मेरा सब काम निराला, कुआं बोला मेरे जल को सजा ले, सीप में बदल मोती सा क्लेवर ले।'

केरल से पी बी रमादेवी ने 'हिन्दी' में शीर्षक 'धरती काया', वीए वर्गीज ने मलयालम में 'मणिपुर के आंसू' कविता में गांधारी, पांचाली के उदाहरण दिए, प्रो. हरीश अरोड़ा, दिल्ली ने 'दहलीज' के माध्यम से 'खोजो पानी की आवाज', गीता विजय कुमार, केरल ने आशावादी कविता में कहा-'धरती में हम साथ साथ रह सकते हैं', श्रीदेवी, चेन्नई ने अपनी कविता 'बाबुल का आंगन' के माध्यम से नारी की चाहत को प्रस्तुत किया-'कुछ पल और ठहर जाते'। इसके बाद अरुण कुमार पासवान की सुंदर पंक्तियों 'इकरो इकरो मकान' के उपरांत कुमारी किरण ने 'हमारा पर्यावरण' के माध्यम से गायब होती कूक और कोयल का प्रश्न उठाया, सुजाता दास, भिलाई ने नये तीन आपराधिक बदलाव के नियमों की काव्य व्याख्या की, जेसी बतरा, मेरठ ने 'सिरामि', मुल्तानी में, प्रभा मेहता, नागपुर ने गुजराती में 'हम समुद्र हो जाएं', बालकृष्ण महाजन का हास्य व्यंग्य-'विश्व पर्यावरण' मंत्री को बुलाया गया एक पौधा लगाया गया' तो मुकेश अग्रवाल, दिल्ली का सिंदूरी आसमान शीर्षक गीत-'हर्षित कर देते हैं अचानक आए काले बादल, ढक लेते हैं उसको/दिनकर का अंत नहीं होता'।

नरेंद्र सिंह परिहार, नागपुर 'घेवर मिर्च सा प्यार', डॉ. श्याम मनोहर सिरोठिया, बेंगलुरु से 'मैंने तो गीतों की रचना कर दी/तुमने मेरे गीतों को प्राण दिया है' की सुंदर अभिव्यक्ति के बाद पूरी महफिल का जिस गीत के बोलों ने सर्वाधिक ध्यान खींचा और काव्य गोष्ठी का समापन जिनके माध्यम से किया गया, वे थे प्रो. युवराज सिंह 'युवा', आगरा के बोल-'जल रहा है जिगर, तप रहा है बदन, प्यार करते हो तो सबको बता दीजिए।'

कार्यक्रम में देश भर के तमाम अंचलों से 63 कवियों ने नाम दर्ज कराए थे लेकिन कई कवि समय मर्यादा के कारण अपनी कविताएं और रचनाएं सुना नहीं सके। हर दो महीने में आभासी काव्य गोष्ठी के आयोजन का वादा करते हुए सफल गोष्ठी का आभार डॉ. अवस्थी ने किया। डॉ. अवस्थी ने संदीप शर्मा और बछौतिया जी का आभार व्यक्त किया।

प्रस्तुति : अविनाश ■

राग रंग

आलोक पराड़कर

मोबाइल के युग में छायांकन

कला की दुनिया में छायांकन को शामिल करने को लेकर पहले से ही हिचक रही है। अब जब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, और वह छायाकार बन चुका है, यह हिचक और बढ़ गई है। तकनीक की इतनी दखल के बाद किसी छायाचित्र को कलाकृति की तरह देखा जाना चाहिए या नहीं, मोबाइल फोन के आने से छायांकन की दुनिया में क्या बदलाव आए हैं, क्या ये सकारात्मक बदलाव हैं, इन बदलावों को किस रूप में लिया जा रहा है, सुविधा बढ़ी है तो क्या गुणवत्ता घटी है, क्या छायाचित्र केवल अभिलेखीकरण के माध्यम बनते जा रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों से हमारा सामना होता है।

प्रसिद्ध छायाकार अनिल रिसाल सिंह की प्रदर्शनी इन दिनों जब लखनऊ में चल रही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का गवाह रही रेजीडेंसी पर आधारित चित्रों की इस प्रदर्शनी के दौरान ये सवाल भी खूब उठे। वास्तुशिल्प को अपने खास अंदाज में प्रस्तुत कर उसे एक नया रूप दे देने वाले अनिल रिसाल सिंह ने स्वीकार किया कि प्रदर्शनी में शामिल बड़ी संख्या में छायाचित्र मोबाइल फोन से लिए हुए हैं। प्रदर्शनी के दौरान जब इन सवालों पर संवाद भी हुआ तो खुद सिंह के अतिरिक्त मनोज छाबड़ा, संदीप कुमार जैसे समाचार पत्रों से जुड़े वरिष्ठ छायाकार, इमामबाड़ा पर कई छायाचित्र प्रदर्शनियां कर चुके आजेश जायसवाल, मोबाइल फोटोग्राफी पर लंबे समय से काम कर रहे कला एवं शिल्प महाविद्यालय के अतुल हुंडू, छायाकार संजय जैन, रंगकर्मी गुंजन जैन के साथ ही कला के कई छात्र-छात्राओं ने शिरकत की। मुख्यतः इस बात पर सहमति रही कि मोबाइल के आ जाने से छायाचित्रण न सिर्फ आसान हो गया है, बल्कि नई-नई सुविधाएं मिल रही हैं।

अनिल रिसाल सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने बड़ी संख्या में मोबाइल फोन से छायाचित्र लिए हैं, और उन्हें इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया है। संदीप कुमार ने कहा कि अपने पेशेवर कार्यों के लिए मुझे कैमरा ही पसंद रहा है। अतुल हुंडू ने मोबाइल फोटोग्राफी की तकनीक पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में कहा गया कि तकनीक को रोका नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर ही कलात्मकता के सफर पर चलना चाहिए लेकिन यंत्र और तकनीक से अधिक व्यक्ति का दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है, जो उसे विचार में परिवर्तित करता है। आयोजकों की ओर से संदीप गोयल एवं राकेश कुमार मौर्य ने भी विचार रखे।

सिनेप्स कला दीर्घा में प्रदर्शित अनिल रिसाल सिंह के छायाचित्रों को देख कर लगता है कि किस प्रकार वे संयोजन का अपने छायाचित्रों में सुंदरता से इस्तेमाल करते हैं, और दृश्य का पुनर्सृजन कर देते हैं। अमूर्त के प्रसिद्ध चित्रकार प्रभाकर कोलते ने कभी कहा था, 'हम उस प्रकृति को क्यों बनाएं जो हमारे आसपास है और जिसे बहुत सारे लोग बनाते आए हैं, हमें तो अपनी नई दुनिया सृजित करनी है'। छायाचित्रों में यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया को ही इसमें दर्ज करते हैं, लेकिन अनिल रिसाल सिंह के छायाचित्रों को देख कर लगता है कि वे दृश्य का पुनर्सृजन कर रहे हैं। वे मानते भी हैं कि कल्पनाशक्ति और कैमरे की आंख से देखने और उन्हें दर्ज करने के साथ चीजें बदल जाती हैं। अपनी कल्पना से, संयोजन से, प्रकाश और छाया के उपयोग से अनिल रिसाल सिंह साधारण चीजों को भी असाधारण बना देते हैं। उन्होंने लंबे समय तक भूदृश्यों को अपने छायाचित्रों का विषय बनाया लेकिन इधर काफी समय से अपना विषय उन्होंने 'फार्म और कलर' बना रखा है। इसके लिए जहां जयपुर का जंतर मंतर उनका प्रिय रहा है वहीं लखनऊ का रेजीडेंसी भी उनका विषय बनता रहा है। रेजीडेंसी के कुछ चित्र कुछ समय पूर्व जब एक कला उत्सव में प्रदर्शित किए गए थे तो उधर से गुजर रहे प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास ठिठक कर रुक गए थे और बहुत देर छायाचित्रों को देखते रहे।

अनिल रिसाल सिंह के रेजीडेंसी के छायाचित्रों में जहां संयोजनों का विशेष महत्त्व है वहीं कुछ खास रंग भी अपनी पहचान बनाते हैं। मटमैले धूसर रंगों के बीच हरियाली और रोशनी उम्मीद की तरह आती है, तो बार-बार चटख लाल रंग हमें इन खंडहरों में दर्ज स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी तो सुनाता ही है, युद्ध का प्रत्याख्यान करते हुए प्रेम का संदेश भी देता है। ■

कैनवस

जय त्रिपाठी

वॉश कला के 'सुख'वीर

कला में प्रत्येक कलाकार की स्वतंत्रत प्रक्रिया में कल्पना का विशेष प्रभाव होता है। फिर भी चित्र में भाव या विचार को आदर्शवाद के साथ व्यक्त करना,कलाकार का दर्शन है। कलाकार अपनी कल्पना एवं अनुभव से दृष्टिकोण को महत्व देते हुए एक निश्चित आधार पर आकर गढ़ता है। पूर्व से ही आदर्श की यहीं कल्पना कलाकारों को नवीन प्रयोग द्वारा ही नहीं, वरन प्राचीन परंपरा के स्वरूप में नए रूपाकारों में गढ़ने को प्रेरित करती रही है। परम्परा के इसी रूप, रंग और रेखाओं के प्रयोग से यदि कलाकृति में भाव व रस का आनंद हो, तो वह आनंदित करती है। इस आनंदमयी कला को हम 111 वर्ष पूर्व में 14 जुलाई 1914 को उ. प्र. में जन्मे समकालीन वॉश कला के हस्ताक्षर रहे, मूर्धन्य कलाकार सुखवीर सिंघल की श्रेष्ठतम कृतियों में देख सकते हैं।

वॉश कला तकनीक में सिद्धहस्त प्रो. सुखवीर सिंघल के एकल चित्रों कि प्रदर्शनी, कलात्मक कला की श्रेष्ठता व्यक्त करती है। यह वॉश कला में उनके रंग और रेखाओं की विशेषज्ञता या उच्च ज्ञान को भी दर्शाता है। जिसे इस कलाकार ने अपने रचनात्मक दृष्टिकोण एवं सजृन की गहराई एवं कुशल प्रयोग से वॉश तकनीक में चित्रित किया है। उनकी अद्भूत कला दृष्टि को देखकर यह समझ आता है, कि यदि चित्रांकन कौशल से किया जाए तो कला सुंदर होगी। देश के वरिष्ठ कलाकार की कृतियों में हमें संसार के जड़ चेतन को चित्रित करती, सभी वह आकृतियां दिखती हैं जिसे संघल जैसा कलाकार उन्ही जड़ चेतन के संदर्भ में चित्रित करता है जो कि सार्वभौमिक सत्य की अनुकृति को प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा भी है कला सत्य की अनुकृति है। यदि अपने भावों की क्रिया को रंगों, रूपाकारों या रेखाओं कि लयात्मता द्वारा इस प्रभाव से अभिव्यक्त किया जाए कि देखने वाले में सुनने का भी भाव उत्पन्न हो जाए तो उसको कलाकार सुखवीर सिंघल की वाश कला में महसूस किया जा सकता है।

तैंतीस वर्षों कें एक लम्बे अरसे बाद यानि तीन दशक बाद इस महान चित्रकार की वॉश शैली में निर्मित 38 कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी देखकर अचरज भी होता है कि इतने लंबे अतंराल के बाद एक प्रभावित करती प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक 'द साइलेंट कैनवस स्पीक अगेन' प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शनी का वरिष्ठ चित्रकार जतिन दास, कला समीक्षक उमा नायर एवं कवि प्रयाग शुक्ल ने विधिवत उद्घाटित किया। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्सी कि कला दीर्घा में 17 जून तक चलने वाली प्रदर्शनी में सिंघल के वाश चित्र देखकर अनुभूति होती है कि कला यतार्थ का आनंद है।

सुखबीर सिंघल की कला, भाव चित्र का प्रमाण है। भाव का प्रदर्शन आकृतियों की भंगिमा से ही होता है। उन भावों की महत्ता पर सूक्ष्मता से विचार कर उन्होनें अपने चित्रों में प्रतीकात्मक रंग, सूक्ष्म बनावट और परतदार कई मानव आकृतियों को अलग -अलग भाव भंगिमाओं में चित्रित किया है, यह हम चित्रों में देख सकते हैं। रूपाकारों में रेखा, रंगो तथा आकारों को इस रूप में चित्रित किया है कि जहां भाव का पक्ष और उसके आंतरिक रूप को कलाकार की आत्म अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। कलाकार ने शारीरिक स्थितियों में परिवर्तन के द्वारा अपने हृदय भावों को प्रदर्शित किया है।

बालकाल से चित्रकला और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकार सुखवीर का कला में प्रवेश तब हुआ जब असहयोग आन्दोलन में गिरफ्तारी से बचने हेतु लोगों की सलाह पर लखनऊ एक मित्र के पास पहुंचे और फिर लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स। प्रो. ए.के. हल्दर और सुविख्यात कलाकार अबनिंद्रनाथ टैगोर से कला का विधिवत ज्ञान प्राप्त करके, बंगाल स्कूल की परंपरा पर आधारित वाश पद्धति को उन्होनें अपनी कला में जीया। समकालीन कला में आज जैसे भी प्रयोग हो रहे हैं या उसे कलाकार कुछ अधिक व्यापक अर्थो में करने लगे हैं किंतु जैसे इन प्रयोगों को केवल रचनात्मक तथा उसके मूल्यांकन के प्रयासों तक ही सीमित नही रखा जा सकता है। वैसे ही सुखवीर सिंघल भी भारतीय चित्रकला पद्धति को जीवित रखने और समृद्ध बनाने वाले सचेतक कलाकारो में से एक थे। प्रदर्शनी की क्यूरेटर प्रियम चंद्रा बताती हैं कि यह एकल प्रदर्शनी उनके नाना जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। ■

https://t.me/AllNewsPapersPaid

एक पिता सौ से ज्यादा स्कूल शिक्षकों से भी बढ़कर होता है।
-जॉर्ज हर्बर्ट

भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय राखाल दास बनर्जी को जाता है। हालांकि, कोलोनियल कॉन्सपिरेसी के तहत उनको वैश्विक स्तर पर वह सम्मान नहीं मिला, जो जॉन मार्शल और एलेक्जेंडर कनिंघम जैसे यूरोपीय पुरातत्वविदों को मिलता है। बीते महीने इस असाधारण जीनियस की पुण्य तिथि थी, जो 95 साल पहले अल्पायु में दुनिया छोड़ कर चले गए।

मोहनजोदड़ो का आवारा मसीहा

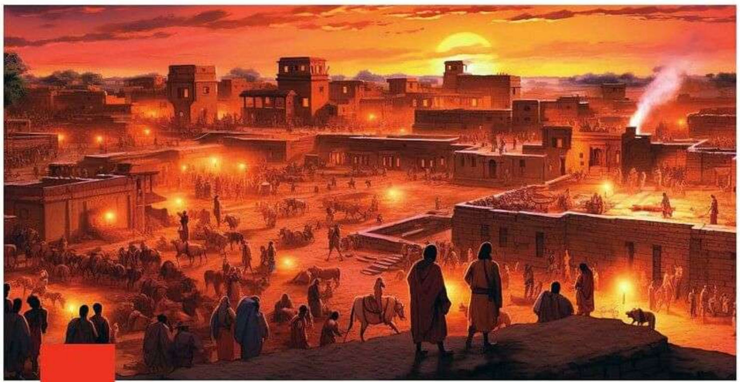

दुष्यंत
लेखक और फिल्म प्रोफेसर

बीते महीने भारतीय पुरातत्व इतिहास के एक अनोखे नायक की पुण्यतिथि थी, जो 95 साल पहले अल्पायु में ही दुनिया छोड़कर चले गए। उनका योगदान कॉलोनियल कॉन्सपिरेसी के बादलों में छिपा चांद है, जो आज तक पूरा नहीं चमका। सबसे पहले उन्हें भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो को खोजने वाले नायक के रूप में याद किया जा सकता है। पर मुझे लगता है कि यह परिचय नाकाफी है। मैं इसके लिए उन्हें सबसे पहले नहीं, बाद में याद करना चाहूंगा। बहरामपुर के संत का मोहनजोदड़ो का आवारा मसीहा होना एक नायक की दुखांत कथा है, जिसमें असाधारण मेधा और महत्वाकांक्षा, एक जीनियस का सनकीपन और महागाथा का धूसर कोलाज भी है। उनका बचपन सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा के आसपास गुजरा। फिर इतिहास पढ़ाने की पहली नौकरी भी बगल के कस्बे के पीजी कॉलेज में ही मिली। तो पुरातत्व और सिंधु सभ्यता के लिए अलग-सा ही आकर्षण बन गया। यह ख्याल ही रोमांचक था कि पुरातात्विक खोजों की प्रक्रिया कितनी दिलचस्प होती होगी!

हालांकि, हम ऐसे समाज में रहते हैं, जहां अतीत को ठीक से जानने, खोजने की न फुर्सत है, न पर्याप्त धन ही। यह अंग्रेजों का जमाना था। कनिंघम और जॉन मार्शल नाम के दो अंग्रेज अफसरों ने भारत में पश्चिमी तरीके से पुरातत्व की खोज शुरू की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) का जन्म भी हुआ और विकास भी। एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल और राखालदास बनर्जी का रिश्ता दो जीनियस-गुरुजी-शिष्य या बॉस-अधीनस्थ का रिश्ता है, जिसमें कभी-कभी कॉलोनियल कॉन्सपिरेसी थियरी की गंध भी महसूस की जा सकती है, बहुत लोगों ने की भी है। उस रिश्ते में बौद्धिक टकराव भी हैं, महत्वाकांक्षाओं का कॉकटेल भी है। *इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज* के 20 सितंबर, 1924 के अंक में मुख्य खोजकर्ता के रूप में जॉन मार्शल ने फर्स्ट पर्सन में इस सभ्यता की घोषणा दुनिया के सामने की, जबकि तब तक जॉन मार्शल ने खुद सिंधु सभ्यता के एक भी स्थल को अपनी आंखों से नहीं देखा था। मतलब वाहवाहियां एक अंग्रेज को मिल रही थीं, काम उसके अधीनस्थों ने किया था, जिसमें आरडी बनर्जी के साथ दयाराम साहनी शामिल थे। और इस बड़ी खोज के आयाम भी कई होने ही थे। एक आयाम यह भी है कि एएसआई का भारत और बर्मा (म्यांमार) में खोदाई का सालाना बजट, जो 1923-24 में बारह हजार रुपये था, इस सभ्यता की खोज की घोषणा के बाद 1924-25 में 80 हजार करने का निर्देश दिया गया था, बाद के वर्षों में खोज और खोदाई के लिए ढाई लाख रुपये का विशेष अनुदान भी दिया गया। इतिहासकार नयन जोत लाहिड़ी अपनी किताब *फाइंडिंग फॉरगॉटन सिटीज* के आखिरी अध्याय में लिखती हैं कि भारतीय पुरातत्व अब रोमांच भरे नए चरण में पहुंच गया था, जिसमें बड़े अभियान और भरपूर बजट प्रमुख थे। क्या बनर्जी की खोज का आजादी के आंदोलन से कोई रिश्ता बना था? मोहनजोदड़ो पर 1926 के *लरकाना गजट* में कहा गया, 'इस खोज का सौंदर्य प्राचीन भारत का गौरव गान करता है और इस ऐतिहासिक वक्तव्य के सत्य को प्रमाणित करता है कि प्राचीनकाल में भारत एक महान और शक्तिशाली देश था। भारत की प्राचीनकालीन महानता के इस प्रमाण की रोशनी में ब्रिटेन को उसे अपने से बेहतर नहीं, तो कम से कम बराबर समझते हुए सम्मान से व्यवहार करना चाहिए और उसे तुरंत आजाद कर देना चाहिए।' वर्ष 1922-23 में वह इतना बड़ा काम कर रहे थे और 1924 में उनका स्थानांतरण एएसआई के ईस्टर्न सर्कल में कर दिया गया। यही वह तथ्य है, जो कॉन्सपिरेसी थियरी को जमीन देता है। प्रचंड प्रतिभा के धनी पुरातत्वविज्ञानी को भ्रष्टाचार के इल्जाम में यह सजा दी गई। उन्हें उनके प्रिय काम से अलग कर दिया गया। कितनी कुंठा, कितना अवसाद झेला होगा कि चालीस की उम्र होने से पहले ही उन्होंने एएसआई से सेवानिवत्ति का फैसला किया और बीमार होकर 45 का होते-होते दुनिया से चले गए। उससे पहले उन्होंने इतिहास की दर्जनों किताबें, ऐतिहासिक उपन्यास ही नहीं लिखे, प्राचीन लिपियों को पढ़ने में भी बड़ी लकीर खींच गए।

कलकत्ता के *अमृत बाजार पत्रिका* और *स्टेट्समैन* ने पत्रकारिता की कमाल मिसाल कायम की है। बानगी स्वरूप, एक संपादकीय में बनर्जी को बाद की खोदाई से दूर किए जाने की तीखी आलोचना की गई, वहीं जॉन मार्शल को अनभिज्ञ, तुच्छ बुद्धि वाला और प्रचार का भूखा बताया और काम पर अधिक ध्यान देने की फटकारनुमा सलाह भी दी गई। वेस्टर्न सर्कल में रहते हुए बनर्जी पर धन के दुरुपयोग, खोदाई अनुदान का कार्यालय के फर्नीचर खरीदने के लिए उपयोग करने और अत्यधिक यात्रा व्यय करने के आरोप लगे थे। इससे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। अक्तूबर 1925 में बनर्जी ने मध्य प्रदेश में एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ का दौरा किया, जहां चौंसठ योगिनी की पत्थर की एक मूर्ति गायब हो गई। उन पर चोरी का आरोप लगाया गया, उन्होंने इसमें शामिल होने से इन्कार किया और जांच शुरू की गई। मूर्ति कलकत्ता में बरामद हुई, तो उनके खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया, लेकिन इस विवाद के कारण 1927 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें निर्दोष पाया गया। एएसआई छोड़ने के बाद, बनर्जी एक प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे, लेकिन भव्य जीवनशैली के कारण उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतिहासकार ताप्ती गुहा ठाकुरता ने एक जगह उल्लेख किया है कि बनर्जी ने अच्छे भोजन, घोड़े की गाड़ियों और दोस्तों पर खुले हाथ से खर्च किया। 1928 में वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाए गए, पर 45 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। राखालदास बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद, इतिहासकार और विद्वान थे। बनर्जी ने अपने अल्प जीवन में विभिन्न लिपियों में प्राचीन और मध्यकालीन 80 अभिलेखों का संपादन किया तथा ऑस्ट्रेलियाई और अफगान मूल के सिक्कों को पढ़ा। उन्होंने भारतीय इतिहास और पुरातत्व पर कई शोधपत्र और पुस्तकें प्रकाशित कीं, जिनमें *द ओरिजिन ऑफ द बंगाली स्क्रिप्ट* और *हिस्ट्री ऑफ इंडिया* आदि शामिल हैं। उन्होंने 1910 में कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में सहायक के रूप में काम शुरू किया। 1911 में वह एएसआई में सहायक अधीक्षक बने। 1917 में उन्हें पश्चिमी सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने पहाड़पुर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर खोदाई की। स्वतंत्र प्रकृति के कारण ब्रिटिश अधीक्षकों के साथ उनके संबंध जटिल रहे थे। कांग्रेस की स्थापना वाले साल में जन्मे बालक की मनःस्थिति अंग्रेजों के लिए अलग तो रही ही होगी। आज भी, बनर्जी इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं, पर उनके योगदान को ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में कम आंका गया है। फिर भी मोहनजोदड़ो की खोज आने वाली पीढ़ियों और पुरातत्वविदों को प्रेरित करेगी, जिससे उनकी विरासत बनी हुई है।

> अक्तूबर 1925 में, बनर्जी ने मध्य प्रदेश में एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ का दौरा किया, जहां चौंसठ योगिनी की पत्थर की एक मूर्ति गायब हो गई। उन पर चोरी का आरोप लगाया गया, उन्होंने इसमें शामिल होने से इन्कार किया और जांच शुरू की गई। इस विवाद के कारण 1927 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें निर्दोष पाया गया।

पिता होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है

निक्की मार्टिन
साथ में एलेना मेरेंडा

पिता होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अमूमन मांएं घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती ही हैं, पिता भी घर पर रहकर अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है। अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए अध्ययन में 48 प्रतिशत पिताओं और 52 प्रतिशत माताओं ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ घर पर रहना पसंद करते हैं। वैश्विक स्तर पर, पितृत्व अवकाश परिवारों में पिताओं की भागीदारी को बढ़ा सकता है और इससे बच्चों, स्वयं पिता, अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ होता है।

माताएं घर के बाहर कितना काम करेंगी, इसे कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है परिवार में पिता की भूमिका। आजीविका कमाने वाले बेहद पारंपरिक दृष्टिकोण वाले पिता अक्सर ज्यादा देर तक काम करते हैं, जिससे परिवार और काम को लेकर तनाव हो सकता है। जब माता और पिता परिवार में मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं, तो माताएं अक्सर बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाने में तब अधिक सहज महसूस करती हैं, जब पिता सक्रिय रूप से बच्चों के साथ जुड़े होते हैं, और तभी वह पिता पर एक साथी और देखभालकर्ता के रूप में भरोसा करती है। माता-पिता को यह तय करना होगा कि उनके परिवार के लिए क्या सबसे अच्छा है। किफायती और सुलभ बाल देखभाल परिवार के इस निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है कि माता-पिता घर से बाहर काम करेंगे या नहीं। एक सर्वेक्षण में ज्यादातर पिता (90 प्रतिशत) बताते हैं कि बच्चों का पालन-पोषण करना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। पिता बच्चों को अनोखे और विविध अनुभव प्रदान करते हैं, और बच्चों के दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक सक्रिय पिता अधिक खुश और स्वस्थ रहते हैं तथा भावी पीढ़ियों को इससे परिवार में भागीदारी और लैंगिक समानता की सीख भी मिलती है। जब पिता अपने छोटे बच्चों के जीवन में शामिल होते हैं, तो बेटियों की कॅरिअर संबंधी आकांक्षाएं अधिक होती हैं तथा उनके बेटों के अच्छे जीवन साथी बनने की संभावना अधिक होती है। यदि बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा में माता-पिता दोनों की भूमिका हो, तो यह बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा। लेकिन अक्सर पुरुष (जो खुद को मुख्य कमाने वाले के रूप में मानने के लिए समाजीकृत होते हैं) बच्चों के प्रारंभिक शिक्षक के रूप में काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे ऐसी दुनिया में सही ढंग से बड़े नहीं हो सकते, जहां केवल मां ही उनका पालन-पोषण करें। बच्चों को माता-पिता, दोनों की जरूरत होती है, चाहे वह घर हो या प्रारंभिक शिक्षा या देखभाल।

> आज फादर्स डे पर यह समझें कि जब पिता बच्चों से सक्रिय जुड़ाव रखते हैं, तो वे परिवार अधिक मजबूत और बच्चे अधिक आत्मविश्वासी होते हैं।

द कन्वर्सेशन से

मूढस्य दर्पः स पुनर्मोह एव
मूढस्य नायं परोऽस्ति लोकः।
न ह्येव दुःखानि सदा भवन्ति
सुखस्य वा नित्यशो लाभ एव।।

अर्थात मूढ़ मनुष्य को गर्व होता है। उसका वह गर्व मोह रूप ही है। मूढ़ के लिए न तो यह लोक सुखद होता है और न परलोक ही। किसी को भी न तो सदा दुख ही उठाने पड़ते हैं और न नित्य, निरंतर सुख का ही लाभ होता है।

-शांतिपर्व 286/12

–(महर्षि समङ्ग का देवर्षि नारद को उपदेश)

प्रस्तुति : विवेक चौरसिया

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

चंचुला भी कुमार्ग पर चल पड़ी थी। उसने एक बार कथा सुनी कि परपुरुष का गमन करने वाली स्त्री को घोर यातनाएं मिलती हैं। उसने कथा वाचक से मुक्ति का उपाय पूछा, तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की सलाह दी।

शिव कथा से पापिनी चंचुला बनी मुक्तात्मा

किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम, दुरात्मा और महापापी था। हालांकि, उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, फिर भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, मगर उसे छोड़कर बिंदुग वेश्यागामी हो गया था। कुकर्म में लगे हुए बिंदुग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म-नाश के भय से क्लेश सहकर दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह भी दुराचारिणी हो गई।

धूप आने दो

वर्षों तक दोनों पापाचार में डूबे रहे। अंत में बिंदुग की मृत्यु हो गई। वह नरक में भयंकर यातनाएं झेलकर एक दिन पिशाच के रूप में विंध्य पर्वत पर पैदा हुआ। चंचुला अपने घर में पुत्रों के साथ रहने लगी, लेकिन भीतर से वह व्याकुल रहती थी। उसका जीवन पाप की छाया में डूब चुका था। एक दिन, किसी अच्छे समय में वह तीर्थ यात्रा पर निकली। वह गोकर्ण क्षेत्र पहुंची, जहां उसने पवित्र तीर्थों में स्नान किया और मंदिरों के दर्शन किए। वहीं एक मंदिर में, एक साधु भगवान शिव की पावन कथा सुना रहे थे। कथावाचक कह रहे थे कि 'जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनको घोर यातनाएं देते हैं।' ब्राह्मण साधु के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। भय और ग्लानि से उसका हृदय भर आया।

> कथा के बाद वह ब्राह्मण के पास गई और रोते हुए बोली, 'मैं पाप के मार्ग पर चली। मैंने धर्म का त्याग किया और अब मुझे अपने पापों का भय सताने लगा है। मुझे बचा लीजिए! आपकी इस कथा ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है।'

ब्राह्मण ने उसे करुणा से उठाया और बोले, 'नारी! यह सौभाग्य की बात है कि समय रहते तुम्हारा हृदय पश्चात्ताप से भर गया। शिव की कृपा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चात्ताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जैसे दर्पण को साफ करने से वह चमक उठता है, वैसे ही *शिवपुराण* की कथा मन को निर्मल करती है। इससे पूर्णतया चित्तशुद्धि हो जाती है। चित्तशुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों (ज्ञान और वैराग्य) के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है-इसमें संशय नहीं है।' चंचुला उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, 'हे ब्राह्मण देव! आप धन्य हैं। कृपा करके मुझे यह कथा सुनाइए।' इसके बाद वह ब्राह्मण की सेवा में लग गई और प्रतिदिन कथा सुनने लगी। ब्राह्मण ने उसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त शिव कथा सुनाई। कथा के साथ-साथ चंचुला का हृदय शुद्ध होता गया। उसके पापों का बोझ हल्का होने लगा। अब उसका जीवन तपस्विनी की भांति शुद्ध और शांत हो गया। वह भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करने लगी और संसार से उसका मोह छूट गया।

जब अंत समय आया, तो वह पूर्ण पवित्र हो चुकी थी। जब उसने शरीर त्यागा, उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। वह रत्नजड़ित विमान स्वयं भगवान शिव ने भेजा था। उसमें शिवगण सवार थे। वह विमान चंचुला को सम्मानपूर्वक शिवलोक ले गया। चंचुला का रूप दिव्य हो चुका था-आभूषणों से सजा शरीर, तेजस्वी मुख और सिर पर अर्धचंद्रयुक्त मुकुट। शिवलोक में पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी महादेव के दर्शन किए। उनके चारों ओर गणेश, नंदी, भृंगी और वीरभद्र सेवा में उपस्थित थे। विद्युत के समान चमकती हुई पार्वती जी उनके वामभाग में विराजित थीं।

यह दृश्य देखकर चंचुला का हृदय आनंद से भर गया। उसने शिव-पार्वती को बार-बार प्रणाम किया। उसके नेत्रों से आनंदाश्रु बह निकले और सारा शरीर रोमांच से भर उठा। फिर भगवती पार्वती ने उसे प्रेम से बुलाया और सखी बनाकर अपने साथ रख लिया। इस तरह वह शिवकृपा से पापों से मुक्त होकर सदा के लिए परम धाम में निवास करने लगी। चंचुला शिवलोक में निवास करती है-जहां न दुःख है, न मृत्यु, क्योंकि वहां केवल आनंद, भक्ति और शांति है।

अध्ययन कक्ष

फ्रेंड्स फॉरएवर
ट्रंप-मस्क ट्रू फ्रेंडशिप: ए ट्रू स्टोरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क
लेखक : के. डेनियल
प्रकाशक : स्वस्तिका पब्लिशर्स
मूल्य : 749 रुपये (किंडल संस्करण)

ट्रंप, मस्क और ट्रंप टावर की वे बैठकें

इस चर्चित किताब के जरिये आप खुद को ट्रंप टावर में देर रात चलने वाली बैठकों में पाएंगे, जहां मस्क ने ऐसे विचार रखे, जो विज्ञान कथाओं के पन्नों से निकले लगते हैं। फिलहाल, उनमें मनमुटाव सुर्खियों में है, लेकिन यह बताती है कि कैसे इस अप्रत्याशित साझेदारी ने मानवता के सितारों तक पहुंचने के लिए मंच तैयार किया था।

फ्रेंड्स फॉरएवर आधुनिक युग की दो सबसे प्रभावशाली हस्तियों-डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच बनते-बिगड़ते संबंधों की एक सम्मोहक खोज है। किताब बताती है कि किस तरह उनकी दोस्ती ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल की स्थापना से लेकर अमेरिका की अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं को तेजी से आगे बढ़ाने तक, चंद्रमा और मंगल पर अभूतपूर्व मिशनों में परिणत होने तक, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। अंतरिक्ष से परे, उनका सहयोग भविष्य की परिवहन परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा उन्नति और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में नवाचारों तक फैला, जिसने न केवल प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि अन्वेषण की अमेरिकी भावना को भी फिर से जगाया। के. डेनियल के मुताबिक, स्पेस फोर्स के निर्माण से लेकर ऊर्जा ग्रिड के आधुनिकीकरण तक, उनका संयुक्त दृष्टिकोण अमेरिका जैसे राष्ट्र को प्रेरित करता रहा और नवाचार व नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। लेकिन उनकी यात्रा विवादों से अछूती नहीं रही।

आलोचकों ने उनके तरीकों, उनकी प्रेरणाओं और यहां तक कि उनकी भव्य योजनाओं की व्यवहार्यता पर भी सवाल उठाए। फिर भी, संदेह और राजनीतिक प्रतिरोध के बावजूद, मस्क और ट्रंप आगे बढ़ते रहे, इस विश्वास के साथ कि असंभव केवल एक चुनौती है, जिसे दूर किया जाना है। इस पुस्तक में राजनीति, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण पर उनके गहन और विचारोत्तेजक संवाद हैं, जो पाठकों को यकीनन प्रेरित करेंगे। जैसे ही आप यह किताब पढ़ना शुरू करेंगे, आप खुद को ट्रंप टावर में देर रात तक चलने वाले विचार-मंथन में पाएंगे, जहां मस्क ने ऐसे विचार रखे, जो विज्ञान कथाओं के पन्नों से निकले हुए लगते हैं।

आप केप कैनावेरल के लॉन्च-पैड पर खड़े होंगे, जहां स्पेसएक्स रॉकेट न केवल पेलोड, बल्कि एक राष्ट्र की उम्मीदों को लेकर आकाश में उड़ा। आप देखेंगे कि कैसे इस अप्रत्याशित साझेदारी ने मानवता के सितारों तक पहुंचने के लिए मंच तैयार किया और साथ ही तकनीकी क्रांति के युग में नेतृत्व करने के अर्थ को फिर से परिभाषित किया। यह पुस्तक केवल दो व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सहयोग और दूरदर्शिता की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में है। यह इस विचार का प्रमाण है कि जब नेता और नवोन्मेषक एक साथ काम करते हैं, तो वे एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने, आगे बढ़ने और जितना संभव हो सके, उससे कहीं अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। *फ्रेंड्स फॉरएवर* उन लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए, जो सत्ता साझेदारी, अंतरिक्ष अन्वेषण, इलेक्ट्रिक वाहनों और भविष्य के लिए साहसिक दृष्टिकोणों में रुचि रखते हैं। यह पुस्तक इस बात पर एक अंतरंग नजर डालती है कि महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता कैसे दुनिया को और उससे परे सितारों को आकार दे सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

अभियान

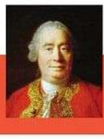

"जितना ज्यादा आजाद मनुष्य का दिमाग है, उतना ज्यादा आजाद दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है। - डेविड ह्यूम

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

कार रोज शाम ठीक उसी जगह पार्क हो जाती है,
चाबी भी रोज उसी कील पर लटक जाती है,
बस एक किस्त है,
जो कभी-कभी इधर-उधर हो जाती है...

मैं आजाद घूमता हूं इधर-उधर,
रिश्ते अब मोबाइल में कैद हैं,
चलो फिर मजहबों की बात करें,
हादसा फिर हुआ है शहर में,
जिंदगी में है जरा ऊंच-नीच मगर
एक मौत सबको यहां बराबर बंटी है...

पहली बार हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन

झरोखा
15 जून

1667 में आज के ही दिन पहली बार एक फ्रांसीसी चिकित्सक ने रक्त-संचार (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) किया गया था। खून की कमी से जूझ रहे 15 वर्षीय एक लड़के को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ी। उस समय विज्ञान को यह जानकारी नहीं थी कि न सिर्फ अलग-अलग प्रजातियों के बीच रक्त संचार खतरनाक होता है, बल्कि यह भी कि मनुष्यों में अलग-अलग और सामान्यतः असंगत रक्त समूह होते हैं। उस लड़के को जो खून चढ़ाया गया, वह एक भेड़ का था। हालांकि इस तरह की ट्रांसफ्यूजन की प्रथा ने वैज्ञानिक और धार्मिक/नैतिक, दोनों कारणों से समाज में बहुत विवाद पैदा कर दिया था। आगे चलकर जब भेड़ के रक्त को अन्य लोगों को चढ़ाया गया तो वे उतने सफल नहीं रहे। अंततः इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1818 में ब्रिटिश प्रसूति विशेषज्ञ जेम्स ब्लंडेल ने एक रोगी को सफलतापूर्वक मानव रक्त चढ़ाया, जिसे प्रसव के दौरान रक्तस्राव हो गया था। 1901 में वियना के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टाइनर ने रक्त समूह 'ए', 'बी' और 'ओ' की खोज की। उन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला।

■ रीमा यादव, हिसार

अहमदाबाद से लंदन जा रहे एअर इंडिया के विमान का उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। जांच जारी है। जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

कड़ी कार्रवाई की जरूरत

निष्पक्ष जांच तो जरूरी है

देश में ट्रेन और बस के साथ ही एअरक्राफ्ट दुर्घटनाओं का बढ़ता ग्राफ चिंताजनक है। बीते दिनों अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट 171 उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

आधुनिक तकनीक से लैस एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत ही दुखद है। इस विमान को दिल्ली से अहमदाबाद होते हुए लंदन जाना था। विमान जब दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा, तब भी यात्रियों ने वीडियो बनाकर एसी समेत कुछ दूसरी आंतरिक खामियों की ओर इशारा किया था। सारी जांचों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद ही विमान डॉक्टर्स हॉस्टल के मेस की छत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें दो पायलट, दस क्रू मेंबर समेत 242 यात्री थे, जिनमें 53 ब्रिटिश, 1 कनाडा का और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक का आश्चर्यजनक रूप से बचना सुखद है। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस के ऊपर विमान गिरने से मेडिकल छात्रों का हताहत होना बहुत ही अफसोसजनक है। यह दुर्घटना कई सवाल छोड़ गई है। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, पायलट द्वारा की गई मेडे कॉल यानी 'मेरी मदद करो' भी कोई काम नहीं आई। इसमें तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है, लेकिन किसी षड्यंत्र से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हादसे की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब विशेषज्ञ अलग-अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह मानवीय चूक है या तकनीकी खराबी। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

चिट्ठी 1

■ अमृता पांडे, नैनीताल

तार-तार होते रिश्ते

इंदौर के सोनम-राजा रघुवंशी मामले ने एक बार फिर भारतीय समाज को झकझोर दिया है। लगता है, जैसे-जैसे पूंजीवाद और पश्चिमी सभ्यता का असर गहरा होता जा रहा है, वैसे-वैसे हमारे रिश्ते और पारंपरिक मूल्य दरकते जा रहे हैं। खासतौर पर इन दिनों पति-पत्नी के संबंध हमारे समाज में विशेष रूप से संवेदनशील होते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से देश में एक के बाद एक इस तरह के कई मामले चर्चा में आ चुके हैं।

यह हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री-पुरुष का रिश्ता ही समाज का आधार होता है। कभी जहां पत्नियां पतियों के प्राण यमराज से मांग लाती थीं, उनकी चिता के साथ सती हो जाती थीं, वहीं आज वे किसी छुद्र स्वार्थ में पड़कर पतियों के खिलाफ जानलेवा साजिश तक रचने में कोई संकोच नहीं कर रहीं। इससे जाहिर होता है कि हमारे अधिकांश रिश्ते भी अब भोगवादी संस्कृति की चपेट में आ चुके हैं और उनमें भावनात्मक लगाव काफी छिछला हो चला है। आज अमेरिका में तलाक सामान्य है और करीब हर दूसरे जोड़ा तलाक ले रहा है। पर अपने यहां यह अब भी इतना आसान नहीं है और इसमें कानूनी जटिलताओं के अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा की पेंचीदगी भी शामिल होती है। इसके बावजूद अमेरिका में हम पति-पत्नी की हत्या आदि के मामले अपवाद स्वरूप ही पा सकते हैं। इस विरोधाभास की क्या वजह है? क्या इसकी वजह भारतीय परंपराओं की जकड़न है, जिसमें व्यक्ति, खासतौर पर स्त्री वर्ग या तो दमित है या फिर मुक्ति का अनुभव होते ही स्वच्छंद हो जाता है! अगर ऐसा कुछ है तो यह जरूरी है कि कानूनी सुधारों के अलावा हमारे समाज में इस पर एक व्यापक और सार्थक विमर्श होना ही चाहिए।

चिट्ठी 2

■ बिपिन तिवारी, गोंडा

प्रकृति को नहीं समझेंगे तो...

तापमान का उतार-चढ़ाव लोगों के जीवन पर भारी पड़ने लगा है। इस साल दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब पांच डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से छह डिग्री कम था। मार्च के अंत में तापमान तेजी से बढ़ा और दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच गया। तापमान में आ रहे इन भारी बदलावों से दशकों बाद रूबरू हुए। फसलों के उत्पादन पर यह तापमान में आ रहा बदलाव सामान्य नहीं है। भले ही इसे हम जलवायु परिवर्तन की आहट न मानें, लेकिन यह एक खतरे की दस्तक जरूर है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार दरवाजे पर दस्तक दे रहे इस खतरे से अनजान बनने की कोशिश कर रही है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।

अचानक तपती धरती और गरम हवाओं के थपेड़ों ने ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के राज्यों में चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। लू और गर्मी से मौतों की जो खबरें मई में आती थीं, इस बार मार्च में ही आनी शुरू हो गई थीं। देश के पहाड़ी राज्यों में मार्च के आखिर का तापमान दो से तीन डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई बूंदाबांदी ने उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी है, लेकिन गर्मी का भीषण दौर अभी बाकी है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के जो खतरे पिछले तीन दशकों से चर्चाओं में है, उनके प्रति भी सरकार गंभीर नहीं है।

चिट्ठी 3

■ कांतिलाल मांडोत सूरत

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

प्रयागराज से आशीष कुमार गुप्ता, बरेली से सीमा गुप्ता, फिरोजाबाद से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मंडी से पारुल अरोड़ा, अमरोहा से डॉ. महताब अमरोहवी, रुड़की से डॉ. सम्राट् सुधा, कासगंज से मेघ सिंह, देहरादून से अतुल रावत, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, मेरठ से डॉ. नरेन्द्र टोंक, नई दिल्ली से विजय कुमार तिवारी, बड़वानी से प्रो. आरके जैन, झाबुआ से अरविन्द रावल।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

ग्लेशियर से बहता है 'लाल' पानी

ग्लेशियर से पानी निकलना आम है, लेकिन अगर लाल पानी निकलता दिखे तो...? अंटार्कटिका के इस ग्लेशियर की कहानी बहुत रोचक है।

आमतौर पर आपने किसी ग्लेशियर से पानी के झरने निकलते हुए देखे होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई यह कहे कि ग्लेशियर से खून का झरना निकल रहा है तो आपका चौंकना स्वाभाविक है। लेकिन असल में, अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से गहरे लाल रंग का पानी बहता है।

इस झरने की खोज 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने की थी। इसके पानी की वजह से ऐसा भ्रम भी हुआ कि यहां दूसरी दुनिया के जीव रहते हैं, पर अब इससे परदा उठ चुका है। यह झरना पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर है और गहरे लाल रंग का यह झरना कई दशकों से बह रहा है। वैज्ञानिकों ने जब इस झरने के पानी के सैंपल की जांच की, तब पता चला कि यह स्वाद में नमकीन है, जैसा कि खून का स्वाद होता है। साल 1960 में इस बात का पता चला कि ग्लेशियर के नीचे लौह नमक यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड है और यह बर्फ की मोटी परत से ठीक वैसे ही निकल रहा है, जैसे आप ट्यूब से क्रीम निकालते हैं। इस जगह का तापमान दिन में माइनस सात डिग्री सेल्सियस रहता है। कहने का अर्थ यह कि यह झरना बहुत ठंडा है और अत्यधिक नमक होने की वजह से यह बहता रहता है, नहीं तो जम जाता। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि बर्फ की परत पर अंदर से कौन दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से गहरे लाल रंग का पानी ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है। इसके पीछे भूगर्भीय दबाव है या कुछ और। इस झरने से लोहे के साथ-साथ सिलिकॉन, कैल्सियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के कण भी निकल रहे हैं, साथ ही यह एक दुर्लभ सबग्लेशियल इको सिस्टम के बैक्टीरिया का घर है। यह ऐसी जगह है, जहां ऑक्सीजन है ही नहीं। ये बैक्टीरिया बिना फोटोसिंथेसिस के ही जी रहे हैं और नए बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं।

■ कोमल सिंह, जालंधर

आकाश में खोजबीन बगल में 'मिली'

1975 में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिली' के सेट पर 'आए तुम याद मुझे...' गाने की शूटिंग के दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी।

■ आराधना वत्स, गाजियाबाद

छायानट

हिट फिल्म को नहीं मिला कोई खरीदार

हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देने वाली कॉमेडी फिल्म हेरा-फेरी रिलीज के 25 साल पूरे कर चुकी है। परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग ने इसे ऑल टाइम क्लासिक बना दिया, लेकिन इस फिल्म में इतने अधिक सैड सीन्स थे कि कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस बारे में निर्माता फिरोज ए नाडियाडवाला ने एक बार बताया था, "पहले फिल्म में गरीबी और अभाव की कहानी इतने बड़े हिस्से में थी कि फिल्म को बेचना मुश्किल हो रहा था। कंसेशन के साथ भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा था।

तब सोचा गया कि फिल्म की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए एक-दो गाने शूट करने चाहिए। सब कुछ तय होने और गानों की शूटिंग के बाद दोनों गानों के बिना ही फिल्म 3 घंटे 40 मिनट की हो रही थी। तब निर्देशक प्रियदर्शन ने एक मेजर कॉमिक हिस्सा फिल्म से हटा दिया, ताकि ये दोनों गाने शामिल किए जा सकें। फाइनल एडिटिंग के बाद मैंने कुछ नए सीन्स भी शूट कराए। मेहनत रंग लाई और जिस फिल्म को लेनदार नहीं मिल रहे थे, उसे हमने तय तारीख से दो महीने पहले बिना किसी डिस्काउंट के अच्छी-खासी कीमत पर रिलीज किया।

■ श्याम कुमार सिंह, लुधियाना

आपातकाल का साया पीछा नहीं छोड़ रहा!

तानाशाही और परिवारवाद की राजनीति वर्षों पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन 50 सालों के बाद तानाशाही और परिवारवाद की राजनीति एक बार फिर से हमें डराने लगी है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अब यह दूसरे दलों द्वारा किया जा रहा है।

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

इस महीने के आखिर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। मैंने अपनी किताब 'इंडिया आफ्टर गांधी' में इतिहास के इस काले कालखंड के बारे में लिखा है। इच्छुक पाठकों को मैं इस विषय पर अन्य विद्वानों के अलावा एम्मा टारलो, ज्ञान प्रकाश, क्रिस्टोफ जैफरलॉट और प्रतिनव अनिल के साथ हाल में सुगाता श्रीनिवासराजू की लिखी किताबें पढ़ने के लिए भी कह सकता हूं। हालांकि इस कॉलम में मैं एक युवा कॉलेज छात्र के रूप में आपातकाल का अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं।

मई 1975 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक का पहला साल पूरा करने के बाद मैं छुट्टियां बिताने अपने घर देहरादून आ गया। छुट्टियों के दौरान ही आपातकाल की घोषणा हुई। जुलाई के तीसरे सप्ताह में जब मैं विश्वविद्यालय परिसर में लौटा तो इस बारे में सोच रहा था कि इंदिरा गांधी द्वारा अपने विरोधियों को जेल में डालने का मेरे देश के वर्तमान या भविष्य से क्या संबंध था। ऐसा इसलिए, क्योंकि मैं 17 साल का था और कॉलेज की क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की करने को लेकर बहुत चिंतित था। सेंट स्टीफंस में मेरे दोस्त भी पूरी तरह से गैर-राजनीतिक थे।

राजनीति के प्रति इस तरह की उदासीनता को कॉलेज प्रशासन द्वारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के पदों के लिए चुनाव जोर-शोर से लड़े जाते थे, लेकिन स्टीफन्स कॉलेज के छात्रों को मतदान करने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर, परिसर के अन्य कॉलेजों जैसे हिंदू, हंसराज, रामजस और किरोड़ीमल के छात्र डूसू चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। राजनीति में इससे भी कहीं अधिक सक्रिय थे जवाहरलाल नेहरू के नाम बने विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र।

स्टीफंस कॉलेज के छात्र अपनी संस्था का संबंध महात्मा गांधी से जोड़ते थे, क्योंकि उनके करीबी दोस्त सीएफ एंड्रयूज वहां पढ़ाया करते थे। हालांकि इस कॉलेज से लाला हरदयाल और बृजकृष्ण चांदीवाला जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी निकले, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में इसका योगदान मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी, प्रयागराज (तब इलाहाबाद), पटना और अन्य स्थानों के कॉलेजों की तुलना में बहुत कम है। राजनीति के प्रति इस तरह का असम्मान आजादी के बाद भी बना रहा, तब स्टीफन्स कॉलेज के होनहार छात्रों ने नौकरशाही या राजनयिक दल में शामिल होना बेहतर समझा। 1960 के दशक में कुछ स्टीफेनियन्स का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हुआ। उनके समकालीन या तो सरकारी नौकरी करने लगे या पत्रकार, शिक्षाविद और कॉरपोरेट अधिकारी बन गए।

जिस सेंट स्टीफन्स को मैं जानता था, उसमें कई विशेषताएं तो थीं, लेकिन राजनीतिक सक्रियता उनमें से एक नहीं थी। जुलाई 1975 में गर्मी की छुट्टियों के बाद जब मैं कॉलेज लौटा तो पाया कि वह बिल्कुल भी नहीं बदला था। विपक्षी नेताओं की हिरासत और प्रेस पर सेंसरशिप का हम पर कोई असर नहीं पड़ा। हम पहले की तरह ही बातें करते रहे, हंसते-खेलते रहे। 1975 के उत्तरार्ध में मेरा ध्यान अपनी स्टॉक डिलीवरी, ऑफ-ब्रेक के साथ चलने वाली लेग-कटर विकसित करने पर था, जबकि अन्य स्टीफेनियन्स अपनी पसंद के क्षेत्र में मग्न थे, चाहे शेक्सपियर को पढ़ना हो, पूल खेलना हो या शास्त्रीय संगीत सुनना।

जैसे-जैसे आपातकाल लंबा खिंचता गया, उसके काले पक्ष की कुछ कहानियां हमारे सामने आती गईं। हमने प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के बढ़ते रुतबे, पीएस भिंडर नामक एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी पर उनके बढ़ते भरोसे के बारे में सुना। एक बहुत ही प्रिय शिक्षक विजयन (उन्नी) नायर को संजय गांधी ने अपने साथ जुड़ने के लिए बुलाया। वे दोनों दून स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। संजय ने एक दोस्त के माध्यम से उन्नी को खबर भिजवाया कि वह अंडरग्रेजुएट को पढ़ाना बंद करें और उनके साथ मिलकर देश चलाएं। उन्नी नायर ने बड़ी ही उदारता के साथ जवाब दिया, वह जहां भी हैं, खुश हैं।

उसके बाद हम विश्वविद्यालय के कॉफी हाउस में हर दिन एक भूरी दाढ़ी और रंगीन चश्मा लगाए व्यक्ति को अकेले बैठा देखा करते थे। हमें लगता था कि वह आईबी का एजेंट है और कॉलेज में शांति और सद्भाव की जांच के लिए तैनात किया गया है।

इस घटना ने मेरे अंदर के राजनीतिज्ञ को थोड़ा झकझोरा। अप्रैल 1976 के दूसरे सप्ताह में देर रात ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित कुछ टिप्पणियों ने भी ऐसा ही किया। हममें से कुछ लोग वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा टेस्ट मैच के आखिरी दिन की कमेंट्री सुनने के लिए रेडियो को घेर कर खड़े थे। भारतीय टीम 400 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और उसने उसे हासिल भी कर लिया, जिसमें लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ के शतक शामिल थे। जैसे ही विजयी रन लिया गया, रेडियो कॉमेंटेटर जोर से चिल्लाया, "यह इंदिरा गांधी का देश है! यह बीस सूत्री कार्यक्रम का देश है।" उस समय भी मुझे यह बहुत अपमानजनक लगा था, क्योंकि जो श्रेय हमारे क्रिकेटरों को मिलना चाहिए था, वह एक तानाशाह राजनेता को दिया जा रहा था।

1977 के वसंत में आपातकाल हटा दिया गया और चुनावों की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी और उनके कांग्रेस का विरोध करने वाली चार पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। सेंट स्टीफन्स के सामने मौरिस चौक पर एक रैली हुई, जिसमें हजारों अन्य छात्रों के साथ मैंने भी भाग लिया। हमने हरे रंग का साफा बांधे समाजवादी राज नारायण के भाषण सुने, जिसमें उन्होंने नेहरू परिवार के खिलाफ जमकर हमला बोला। वाशिंगटन और मॉस्को में देश की राजदूत रहीं जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी अपनी भतीजी की निरंकुशता को समाप्त करने की मांग को लेकर इस रैली में शामिल हुईं।

मौरिस चौक पर हुई उस रैली ने क्रिकेट और सेंट स्टीफन्स से बाहर की दुनिया में मेरी दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। कुछ सप्ताह बाद जब चुनाव संपन्न हो गए और वोटों की गिनती शुरू हो गई, तब मैं अपने दोस्तों के साथ बहादुर शाह जफर मार्ग गया, जहां उस समय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होने वाले कई प्रमुख अखबारों के मुख्य कार्यालय थे। इंटरनेट दशकों बाद आने वाला था और नवीनतम या विश्वसनीय जानकारी के लिए ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता था। हम समाचार पत्रों के कार्यालयों के बाहर लगे उस बड़े ब्लैक बोर्ड के सामने बैठे थे, जिस पर परिणाम आते ही फ्लैश हो जाता था। जब हमने यह देखा कि संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो जोरदार नारे लगे और जब बोर्ड पर इंदिरा गांधी के हारने की भी खबर फ्लैश हुई तो और भी जोर से नारे लगाए लगे।

तानाशाही और परिवारवाद की राजनीति भी खत्म हो चुकी थी। 50 सालों के बाद तानाशाही और परिवारवाद की राजनीति एक बार फिर से हमें डराने लगी है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अब यह दूसरे दलों द्वारा किया जा रहा है।

अंग्रेजों के दिल में क्यों बसते थे पहाड़?

भारतीय हिल स्टेशन लोगों के लिए मनोरंजन और विश्राम के स्थान के रूप में आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इनका इतिहास ब्रिटिश काल से है। शुरुआत में भारतीय पहाड़ियां अंग्रेजों के लिए छावनी और सैनिटोरियम क्षेत्र के रूप में काम करती थीं।

हालांकि उन्नीसवीं सदी के मध्य में फिरंगियों के लिए ये पहाड़ियां मनोरंजन का माध्यम बन गईं और अंग्रेजों ने अपनी राजधानियों को मैदानों से पहाड़ी स्टेशनों पर स्थानांतरित कर दिया, यानी भारत में हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा भारत में उनके प्रवास को अधिक आरामदायक, मनोरंजक और उन्हें यूरोपीय परिस्थितियों के समान बनाने के लिए विकसित किए गए थे।

मनीष कुमार चौधरी

खुला आकाश

हिल स्टेशन मुख्य रूप से 19वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आए। भारत में हिल स्टेशन अंग्रेजों के प्रवास को अधिक आरामदायक, मनोरंजक और उन्हें यूरोपीय परिस्थितियों के समान बनाने के लिए विकसित किए गए थे।

हिल स्टेशन मुख्य रूप से 19वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आए। दार्जिलिंग उन्नीसवीं सदी के मध्य में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ग्रीष्मकालीन घर के रूप में नामित पहली पहाड़ी बस्तियों में से एक थी। भारत में ब्रिटिश राज के तहत लगभग 80 हिल स्टेशन थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया था। यूं तो हिल स्टेशन मूल रूप से औपनिवेशिक शहरी केंद्र थे, जो मैदानी इलाकों की गर्मी और बीमारियों से यूरोपीय लोगों के शरीर को ठीक करने में सहायता के लिए उष्णकटिबंधीय तराई से दूर पर्वत शृंखलाओं पर बनाए गए थे।

मैदानों की तपती गर्मी में ठंडे पहाड़ों पर यानी हिल स्टेशनों पर जाने की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। दरअसल, अंग्रेज ठंडे मुल्क के वासी थे। भारत के मैदानी इलाकों की गर्मी और समुद्र तट पर बने नगरों की उमस उन्हें बड़ा परेशान करती थी। इसी वजह से अंग्रेज औरतें बहुत कम भारत आती थीं और जो आती थीं, वे ज्यादा समय तक यहां नहीं रह पाती थीं। अंग्रेजों के राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा जब पहाड़ों तक पहुंच गई तो वे शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण हिल स्टेशन का इस्तेमाल देश के अन्य इलाकों में पड़ने वाली तेज गर्मी, लू से बचने के लिए करने लगे।

शिमला को तो उन्होंने बाकायदा ग्रीष्मकालीन राजधानी ही बना लिया। हालांकि अधिकांश अंग्रेज वहां इतनी आसानी से जा नहीं पाते थे। यात्रा खर्च, पहाड़ पर रहने का खर्च और इससे जुड़ी कई अन्य बातें सोचनी पड़ती थीं। यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि वहां कैसी संगत मिलेगी। कोई परिचित व्यक्ति या परिवार वहां मिलेगा या नहीं। इसलिए अधिकतर अंग्रेज अफसर तो अपने-अपने शहरों में काम पर बने रहते, उनकी बीवियां पहाड़ों पर चली जातीं और आराम के साथ मनोरंजन करती थीं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid